हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

3 सितम्बर, 2008

खण्ड 2, अंक 3

अधिकृत विवरण

विषय सूची

बुधवार, 3 सितम्बर, 2008

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(3)1
अति विशिष्ट व्यक्तियों का अभिनन्दन	(3)2
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	(3)2
नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(3)20
शोक प्रस्ताव	(3)22
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना	(3)22
सदस्यों का नाम लेना/वाक–आऊट	(3)23
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–	(3)27
(1) मानसून ऋतु में हरियाणा राज्य में मलेरिया, डेंगू वायरल बुखार के बढ़ रहे मामलों संबधी	
वक्तव्य–	(3)27
उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी स्वास्थ्य मन्त्री द्वारा	

– वाक–आऊट	(3)36
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–	(3)36
(2) नैनो कार परियोजना को पश्चिमी बंगाल से स्थानान्तरित करके हरियाणा राज्य में भूमि उपलब्ध करवाने सम्बन्धी	
वक्तव्य –	(3)36
उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी मुख्य मंत्री द्वारा विधान सभा हाल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा लगाना	
नियम– 15 केर अधीन प्रस्ताव	(3) 99
नियम– 16 के अधीन प्रस्ताव	(3)39
सदन की मेज पर रखे गए कागज–पत्र	(3)40
विधान कार्य –	(3)40
दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं० 3) बिल, 2008	
दि हरियाणा म्यूनिसिप्लिटी पब्लिक डिसक्लोजर बिल, 2008	
दि हरियाणा फायर सर्विसिज बिल, 2008	

दि हरियाणा म्यूनिसिप्ल कारपोरेशन (अमैंडमैंट) बिल, 2009	
दि हरियाणा टाउन इम्प्रूवमैंट बिल, 2008	
दि हरियाणा म्यूनिसिपल सियइजन्ज पार्टीसिपेशन बिल, 2008	
दि हरियाणा अर्बन डिवैल्पमैंट अथॉरिटी (अमैंडमैंट) बिल, 2008	
दि हरियाणा टैक्स ऑन एन्टरी आफ गुडज इन लोकल एरियाज (अमैंडमैंट) बिल, 2008	
विशेषाधिकार कमेटी की विशेष रिपोर्ट पर चर्चा (पुनरारम्म)	(3) 78
अध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद	(3)80

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 3 सितम्बर, 2008

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में प्रातः 11.00 बजे हुई। अध्यक्ष (डॉ० रघुवीर सिंह कादियान) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Mr. Speaker: Hon'ble Member, now the questions hour.

ताराकिंत एवं संख्या–1004

(इस समय माननीय सदस्य थी नरेश यादव सदन में उपस्थित नहीं थे इसलिए यह प्रश्न पूछा नहीं गया।)

Rules for issuing completion certificate by HUDA

***1019. Sh. Radhey Shyam Sharma:** Will the Chief Minister be pleased to state:

(a) whether it is a fact that different rules are being applied for issuing completion certificate of houses by HUDA in different cities, if so, the details thereof.

(b) whether Government intends to apply the same rules in al l the cities for issuing completion certificate for Houses in the sectors of HUDA and

(c) whether it is a fact that a portion of HUDA

park in sector I 5, Gurgaon has been encroached by Administrator, HUDA for his personal use ; if so, whether Government will get it vacated for the public use ?

Power Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala):

(a) No. Sir.

(b) Yes Sir.

(c) No Sir.

श्री राधेश्याम शर्मा अमरः अध्यक्ष महोदय, गुड़गांव के सैक्टर 9, 56,57,45 और 46 में जो मकान हैं उनके पीछे छज्जा बनाने का प्रोवीजन है लेकिन सैक्टर 15 के मकानों में छज्जा बनाने का प्रोवीजन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वे हुडा के सभी सैक्टर्ज में हुडा की तरफ से एक जैसा कानून लागू करवाने का प्रावधान करेंगे?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो प्रश्न भेजा था वह हुडा के यार्डस्टिकस के बारे में था कि क्या हुडा अलग–अलग जगहों पर अलग–अलग यार्डस्टिकस और कम्पाउडिंग फोलो करता है तो मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि हमने इस बारे में स्पष्ट जवाब दिया है कि यार्डस्टिकस जो हैं वे कामन हैं। There are no different yardsticks that are being followed. There are common yardsticks that HUDA follows. As qua. compounding of offences, we have framed a clear-cut policy that where compounding penalty has to be

imposed, penalty has to be uniformed and it cannot be different. As far as the 3rd question that my learned friend has put regarding zoning of the area, zoning cannot be common for the entire State. It is impossible to do so. Zoning always vary from city to city and area to area. If he has a specific grievance, he should send it in writing and we will see it that it could be redressed or not and he will get the reply to his specific grievance.

अति विशिष्ट व्यक्तियों का अभिनन्दन

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I heartily welcome all the Members of the Parliamentary Delegation of Bhutan headed by the Hon'ble Speaker of National Assembly of Bhutan who are present in the V.I.P. Gallery to witness the proceedings of the House. I also welcome Sh. Nirmal Singh Kahlon, Hon'ble Speaker, Punjab Vidhan Sabha.

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

श्री राधेश्याम शर्मा अमरः अध्यक्ष महोदय, हुडा के 15 सैक्टर में जो पार्क है, उसका 3–4 एकड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस समय के हुडा एडमिनिस्ट्रेटर ने अपने लिए रिजर्व किया हुआ था और उसमें सैर करने वालों और घूमने फिरने वालों को घुसने नहीं दिया जाता था। लोग बैठकर बातें करते हैं कि ऐसा अंग्रेजों के समय में होता था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वे इस पार्क के ताले को खुलवाएंगे ताकि वहां पर आम आदमी धूमने फिरने के लिए जा सकें?

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की बात वाजिब है। 1991 –95 में 100 मीटर के करीब ग्रीन बैल्ट डिवैल्प हुई थी। उसका एक हिस्सा उस समय के एडमिनिस्ट्रेटर ने एक दीवार बनाकर आरक्षित कर लिया था। उसके बाद इस बारे में लिटीगेशन हुई। मौजूदा सरकार ने निर्णय किया था कि ग्रीन बैल्ट या पार्क का कोई स्पेस किसी व्यक्ति विशेष के लिए आरक्षित नहीं रह सकता। हमारी सरकार ने यह प्रतिबंध हटा दिया था लेकिन हमारे नोटिस में आया है कि जो दीवार उस समय खींची गई थी वह अभी भी वहीं है। मुख्यमंत्री महोदय ने आदेश दे दिए हैं कि उस दीवार को हटा दिया जाएगा and it will be a contiguous greenbelt and there will be no difficulty to the residents. I can assure you.

Opening of Govt. Engineering Colleges, Polytechnics and. IT] 's

***1013. Sh. Ram Kumar Gautam:** Will the Technical Education Minister be pleased to state the number of Government Engineering Colleges, Polytechnics and I.T.I's opened in the State since April, 2005 togetherwith the name of places and criteria thereof ?

Urban Development Minister (Sh. A.C. Chaudhary): Sir, the information is placed on the Table of the House.

Information

I. No new Govt. Engg. College has been started

after April, 2005.

II. The following 8 Govt. Polytechnics have been started after April 2005 namely:

(1) Ch. Matu Ram Arya Govt. Polytechnic at Sanghi (Rohtak)

(2) Govt. Polytechnic, Lisana (Rewari)

(3) Guru Gobind Singh Govt. Polytechnic, Cheeka (Kaithal)

(4) Govt. Polytechnic Narwana (Jind)

(5) Govt. Polytechnic for Women, Morin (Panchkula)

(6) Deen Bandhu Sir Chhotu Ram Govt. Polytechnic, Sampla (Rohtak)

(7) Ch. Bansi Lal Govt. Polytechnic, Bhiwani

(8) Govt. Polytechnic, Meham (Rohtak)

The criteria for opening of Polytechnics is as prescribed by AICTE which is minimum land of 5 acres and 9 sq. mtr. built up area per student. The other parameters include suitability of land, connectivity, availability of power, water, students, industrial scenario, employment potential and placement facilities.

III. 30 Industiral Training Institutes (ITI's) have been started since April, 2005 at the following places:

(1) Deverala (Bhiwani),

(2) Guhna (Kaithal),

(3) Gullah Cheeka (Kaithal),

(4) Julana (Jind).

(5) Kathura (Sonepat),

(6) Loharu (Bhiwani),

(7) Muana (Jind),

(8) Mudlana (Sonepat),

(9) Naultha (Panipat),

(10) Panchkula (Panchkula),

(11) Mojabad (Gurgaon),

(12) Pchowa (Kurukshetra),

(13) Raipur Rani (Panchkula),

(14) Rakhishahpur (Hisar),

(15) Seenk (Panipat)

(16) Sujapur (Mohindergarh),

(17) Tankri (Rewari),

(18) Trawari (Karnal),

(19) Uchana Khurd (Jind),

(20) Ujjina (Mewat),

(21) Purkhas (Sonepat),

(22) Daroli Ahir (Mohindergarh),

(23) Tosham (Bhiwani),

(24) Bhaproda (Jhajjar),

(25) Asodha Mor (Jhajjar),

(26) Berlikalan (Rewari),

(27) Mattanhail(Jhajjar),

(28) Sal hawas (Jhajjar),

(29) Malrabas (Mohindergarh),

(30) Dumerkhan Khurd (Jind).

The criteria for opening of ITI is as per norms prescribed by Directorate General of Employment & Training, Ministry of Labour, Govt. of India which is 5 to 10 acres land depending upon number of units and trades. The other parameters include suitability of land, connectivity, availability of power, water, students, Industrial scenario and employment potential.

श्री राम कुमर गौतमः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक 9 राजकीय बहुतकनीकी संस्थान नये खोले गये हैं और 50 आई०टी०आईज० नई खोली गई हैं जिनके नाम इन्होंने अपनी रिप्लाई में दिये हुये हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा तो सरकार से यही अनुरोध है कि इन 30 आई०टी०आईज० में से एक आई०टी०आई० नारनौंद में मी खोलनी चाहिए थी। जब से मैं विधायक बना हूं तब से मैं नारनौंद हल्के

में आई०टी०आई० खोलने की मांग कर रहा हूं। बहुत से छोटे–छोटे गांवों में आई०टी०आई० खोल दी गई जैसे देवराला, गुहना, गुल्लाह, जुलाना, कपुरा, मुआना, नौल्था, रायपुररानी, सीक, टकरी आदि मेरे हल्के के बांस, नारनौंद और पेटवाड़ जो की बहुत बड़े–बड़े गांव हैं उनमें से भी किसी एक गांव में आई०टी०आई० खोलनी चाहिए थी। बांस गांव हिसार जिले का नम्बर एक णव है लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। अध्यक्ष महोदय, सरकार आई०टी०आई० खोलते वक्त कोई तो क्राईटरिया अपनाती होगी और मेरे हल्के के जो दो–तीन बड़े गांव हैं उनमें से भी किसी एक गांव में आई०टी०आई० खोलते।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी यह भी बता दें कि रक्शीशपुर अब कौन से हल्के में पड़ता है।

श्री राम कुमार गौतम: अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि बड़ी अच्छी बात है कि बच्चों के लिए सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम बनवा रही है। सुलचानी छोटा सा गांव है जहां सरकार स्टेडियम बनवा रही है और नारनौंद तथा बांस जो बड़े गांव हैं वहां स्टेडियम नहीं बनाया जा रहा। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि जो बड़े–बड़े कस्बे और गांव हैं उनमें भी स्पोर्ट्स स्टेडियम बनवाये जायें।

श्री ए०सी० चौधरी: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के पर्सनल इंट्रैस्ट के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज और पहले भी कई बार बता दिया है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि सरकार जो भी काम करती है उसमें क्राईटेरिया पहली प्राथमिकता होती है और हमारे टैक्नीकल इन्स्टीच्यूशंज जैसे पॉलटैक्नीकस, आई०टी०आईज० और इंजीनियरिंग कालेजिज के लिए ए०आई०सी०टी० के नार्म्ज बने हुए हैं। इस तरह के किसी भी इन्स्टीच्यूट को चलाने के लिए हमने जो क्राइटइरिया रखा है उसके लिए 5 से 10 एकड़ जमीन चाहिए होती हे, उसको भी माननीय साथी देखें। इसके अलावा जहां पर इस तरह के इन्स्टीच्यूट खोले जायें वहां आसपास इतने स्कूल ही कि उनसे बच्चों की पूरी आवक हो, जो आगे पढ़ने के लिए इन इन्स्टीच्यूट्स में एडमिशन लें। इसके अतिरिक्त यह भी देखा जाता है कि ये इन्स्टीच्यूट्स इस हिसाब से खोले जाते हैं कि प्रदेश के हर कोने में तरक्की का जाल फैले। इसके लिए हमने 10 से 15 कि०मी० की रेंज रखी हुई है। 10 कि०मी० से कम की दूरी पर अभी हम और इन्स्टीच्यूट नहीं दे पा रहे। अध्यक्ष महोदय, टैक्नीकल एजूकेशन के प्रति हमारी सरकार पूरी तरह से सजग है। यदि आप वर्ष 2006 से 2008 तक के आकड़े देखें तो पाएंगे कि कुल 37–38 आई०टी०आईज० चार साल के दौरान खोली गई थी और इस एक साल के अंदर 34 आई०टी०आईज० खोली हैं और 30 आई०टी०आई० अंडर कंसीडरेशन हैं जो कि अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसको कम नहीं आका जा सकता। अध्यक्ष

महोदय, मैं एक विनती करूंगा कि टैक्नीकल एजूकेशन की जरूरत की हमारी सरकार ने पूरी तरह से आका है और उसे प्राथमिकता केर आधार पर माना है। उसी नाते से टैक्नीकल इन्हीच्यूट्स के लिए हम जहां–जहां जगह ढूंढ रहे हैं टैक्नीकल इन्स्टीच्यूट बनाने के प्रस्ताव सरकार के पास आ रहे हैं उसके लिए नियरर टू दि मेन रोड जगह होना बहुत जरूरी है। अदरवाईज तो रूरल एरियाज में डैफ्त में जाने पर बच्चे दाखिला लेने नहीं जायेंगे। अगर माननीय सदस्य को कहीं ज्यादा जरूरत है तो वे वहां पर मेरी थोड़ी–बहुत मदद कर दें ताकि मैं भी विचार करके उसको कोई न कोई गति जरूर दे सकता है ताकि उनको भी यह लगे कि उन्होंने जो हाउस में मांग की है उसको नेतृत्व ने पूरा सम्मान दिया है।

श्री राम कुमार गौतमः स्पीकर सर, मंत्री जी का जो व्यान है वह तथ्यों से बिलकुल अलग है क्योंकि इनका यह कहना कि इन्होंने आई०टी–आई० खोलने के लिए 5– 10 किलोमीटर का पैरामीटर रखा है। मैं तो यह कहना चाहता हूं, कि आई०टी०आई० पहले इनकी नारनौंद में खोलनी चाहिए थी उसके बाद राखी में खोलते क्योंकि आई०टी०आई० खोलने कै लिए नारनौंद से बढ़िया जगह दूसरी नहीं हो सकती। नारनौंद में आई०टी०आई० खोलने के बाद ये राखी में खोल देते और उसके बाद सुलतानी में स्टेडियम बना देते। इन्होंने स्टेडियम बनाकर बहुत अच्छा किया है। यह एक बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा और भी बहुत अच्छी बातें हैं। हमें तो यही कबूल करना पड़ेगा कि

जहां—जहां पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय की नजर अच्छी तरह से पड़ जाती है वहां—वहां बढ़िया काम हो जाते हैं और जहां नजर में कमी रह जाती है वे हिस्से पीछे रह जाते हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मैं अपने साथी की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जहां तक नारनौंद में आई०टी०आई० खोलने का सम्बन्ध है मैंने इसकी घोषणा की थी लेकिन इन्होंने आई०टी०आई० खोलने के लिए हमें जमीन ही नहीं दी इसलिए वहां पर आई०टी०आई० हम नहीं खोल पाये। ये अगर आज भी हमें वहां पर जमीन दिलवा दें तो हम अभी वहां पर आई०टी०आई० बनवा देंगे। इसके अलावा नारनौंद शहर का सीवरेज भी हमने मंजूर करवाया। उसमें भी जमीन का झगड़ा पड़ गया और सुप्रीम कोर्ट तक हमें झगड़ना पड़ा।

श्री राम कुमार गौतमः स्पीकर सर, जहां तक जमीन देने की बात है हम जमीन देने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज के दिन किसी शहर में जमीन मिलना बहुत मुश्किल है। नारनौंद इस समय म्यूनिसिपल कमेटी का एरिया है और वहां पर जमीन की बहुत भारी प्रॉब्लम है। जमीन उपलब्ध करवाने के मामले में शहर और गांव में बहुत अन्तर है। श्री भूपेन्द्र सिंह खडाः अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य नारनौंद के अन्दर आई०टी०आई० के लिए जमीन नहीं दिलवा सकते तो आस—पास के किसी भी गांव में दिलवा दें, हम वहां पर भी नारनौंद के नाम से आई०टी०आई० बनवा देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के

लिए बताना चाहता हूं कि ये जो आई०टी०आई०, इंजीनियरिंग कालेज या इस किस्म के दूसरे कोर्सिज हैं ये आज बहुत जरूरी हैं। हरियाणा सरकार का यही प्रयास है कि इस प्रकार के कालेज ज्यादा से ज्यादा बनें क्योंकि इनसे हमारे बच्चों को रोजगार मिलता है। इस बात के लिए मैं अपने विभाग को भी बधाई देता हूं। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए यह भी बताना चाहता हूं कि वर्ष 2005–06 में बी०ई०, ए०बी०ए०, एम०सी०ए०, बी० फार्म०, बी०एच० और एम०सी०पी० डिप्लोमा इन सबको मिलाकर 27 हजार इनटेक था और इन तीन सालों के अन्दर 81 ,890 सीटें हमने क्रियेट की हैं। इसके अलावा आई०टी०आई० का लगभग 31 हजार के करीब इनटेक था जो कि आज बढ़कर 1,03,000 हो गया है। आगे भी हम इसको बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं ताकि अधिक से अधिक रोजगार हमारे बच्चों को मिल सके। आज जिस प्रकार से हरियाणा का विकास और इण्डस्ट्रियलाईजेशन हो रहा है इससे बच्चों को रोजगार मिल सकता है। इसलिए हमारा प्रयास है कि आई०टी०आई०, पालिटैक्नीक्स और इंजीनियरिंग कालेज ज्यादा से ज्यादा खोले जायें। माननीय सदस्य आई०टी०आई० और स्पोर्ट्स स्टेडियम के लिए जमीन दिलवा दें, हम दोनों बनवा देंगे।

प्रो० छत्तर पाल सिंहः स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि आई०टी०आई० खोलने का और प्रोफैशनल एजूकेशन देने का (जो कार्यक्रम सरकार ने चलाया है उसमें जो क्वालिटी 'ऑफ एजूकेशन है

उसको इनश्योर करने के लिए क्या स्टैप्स उठाये जा रहे हैं और जहां बच्चे पढ़ते हैं उन बिल्डिंग्स की मैनटेनैंस के लिए, उनके रख–रखाव के लिए क्या स्टैप्स सरकार द्वारा उठाये जा रहे हैं, क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे? इसके अलावा इसमें मैं स्पैसिफिकली पाबडा गांव का जिक्र करना चाहूंगा। वहां पर जे०बी०टी० की एक बिल्डिंग के अन्दर वोकेशनल एजूकेशन की क्लासिज चलाई जा रही हैं। उस बिल्डिंग की हालत बहुत जर्जर है। मैंने इस बारे में कई बार लिखकर भी दिया है। क्या मंत्री जी उस बिल्डिंग की मैनटेनैंस के लिए पैसा देंगे?

श्री ए०सी० चौधरी: अध्यक्ष महोदय, जहां तक वी०आई० का ताल्लुक है, हमने लेटैस्ट स्नेरियो में टैक्निकल ऐजूकेशन को पूरा प्रोत्साहन देने का फैसला किया है और जहां पर भी ये वी०आईज० थे ये हमने खत्म कर दिये हैं। केवल वे वी०आईज० एग्जिस्ट कर रही हैं जिनका लास्ट सैशन है। बाकी जो एकैडमिक स्टाफ था वह हमने ऐजूकेशन को दे दिया है और जो टैक्निकल स्टाफ था वह हमने अपनी आई०टी०आईज० में मर्ज कर लिया है। वैसे उस बिल्डिंग को अगर किसी दूसरे इस्तेमाल के लिए प्रोपोज किया जायेगा तो इस बात को सुनिश्चित किया जायेगा कि वह जर्जर न हो ताकि किसी किस्म का एक्सीडैंट न हो।

प्रो० छत्तर पाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, तो उसमें जे०बी०टी० खोल दो।

श्री ए०सी० चौधरी: वी०आई० में एक दम से जे०बाइ०टी० खोलना सम्भव नहीं है। **श्री अरजन सिंह:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मंत्री जी कह रहे हैं कि 10 किलोमीटर तक हम आई०टी०आई० दे देंगे। मेरे हल्के में छछरौली से कलेसर तक 50 किलोमीटर के एरिया में कोई भी आई०टी०आई० नहीं है। हम जमीन देने के लिए भी तैयार हैं। क्या मंत्री जी वहां पर कोई आई०टी०आई० का प्रावधान करेंगे?

श्री ए०सी० चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य इसको फोर्मल वे में लिख कर दे दें और साथ' में यह भी कह दें कि हम जमीन दे देंगे तो मैं उसको कट–शार्ट करके अगले सैशन तक उस पर परफॉरमैंस दे दूंगा।

श्री अरजन सिंह: धन्यवाद सर।

श्रीमती गीता भुक्कल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने शिक्षा–वर्ष 2009 में कलायत जैसे बैकवर्ड क्षेत्र के लिए आई०टी०आई० की घोषणा की है। मैं केवल यह जानना चाहूंगी कि कब तक इसका निर्माण कार्य शुरू हो जायेगा? हमने लिख कर दिया हुआ है तथा सब डॉकूमैंट जमा भी करवा दिये हैं कि जब तक आई०टी०आई० की बिल्डिंग का निर्माण नहीं हो जाता

तब तक कलायत में अग्रवाल धर्मशाला है उसमें कुछ कोर्सिज शुरू कर दिये जायें।

श्री ए०सी० चौधरी: अध्यक्ष महोदय, धर्मशाला के मामले में अभी ऑफ हैंड कुछ पता नहीं हो सकता क्योंकि क्लासरूम का साईज और उनकेलिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने के लिए वर्कशाप के लिए, कम्प्यूटर कोर्सिज के लिए कमरों का साईज मुकरर है। जब वे कमरे उपलब्ध होते हैं तभी हम क्लासिज शुरू करते हैं। अगर इन्होंने लिख कर दिया हुआ है तो मैं आज शाम को ही अधिकारियों को बुलाकर देखूंगा अगर धर्मशाला की बिल्डिंग इस काबिल हुई कि उसमें क्लासिज विधिवत लग सकती हैं तो यह देख लूंगा कि कितने सबजैक्ट दे सकता हूं उसको मैं कंसीडर कर लूंगा।

Shri Phool Chand Mulana: Speaker Sir, I would like to know from the Hon'ble Minister that there is an announcement of the Hon'ble Chief Minister that Government Polytechnic will be opened in Barara. But the work has not yet been started. May I know from the Hon'ble Minister in what time the work will be started ?

Shri A.C. Chaudhary: Sir, commitment of worthy Chief Minister is a verdict for us. Whatever is committed, that is definitely to be adhered to. So far as the time schedule is concerned, this file has not come to me and it is difficult for me to say anything at this time. I will study the and after that I will send the reply to the Hon'ble Member.

श्रीमती शकुन्तला भगवाडिया: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि इन्होंने पहले कहा है कि यदि कोई जमीन दिलवा दे तो वहाँ पर आई०टी०आई० या पालिटैक्निक हम खोल देंगे। हमने बावल में धामलावास में पहले ही 20–22 एकड़ जमीन दे रखी है। अगर और जरूरत हो तो हम 40 एकड़ तक जमीन दे सकते हैं तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वहां पर पालीटैक्निक खोलने की कृपा करेंगे?

श्री ए०सी० चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय बहन जी से पूछना चाहूंगा कि वह जमीन किस परिप्रेक्ष में दी गई है, उसके साथ कोई डिमांड तो नहीं की गई है या महज एक ऑफर दे रहे हैं? मैं चाहूंगा कि इस मामले में जो भी कारमैलीटीज हैं उनको पूरा करके आपको लिखित में देना होगा। अगर लिखित में किसी बात की मांग नहीं क्री जायेगी तो सूयो मोटी जिलेवार हमारे पास फिगर्ज हैं और हम यह कोशिश कर रहे हैं कि सर्वांगीण विकास के लिए हर जिले तक टैक्निकल ऐजूकेशन का फैलाव हो। जहां–जहां से मांग आ रही है उसे हम प्राथमिकता के तौर पर दे रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री एस०स० सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री को चिट्ठी लिख कर कैथल में पॉलिटैक्निक खोलने के लिए रिक्वैस्ट की थी। जहां तक जमीन का सवाल है, मन्त्री जी ने 5 से 10 एकड़ जमीन देने के लिए कहा था, हम विभाग को 10 से 12 एकड़ जमीन दिलवाने के लिए तैयार हैं। कैथल डिस्ट्रिक्ट–

हैडक्वार्टर है लकिन वहां पर एक आई०टी०आई० ही चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, .मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या कैथल में पालिटैक्निक खोलने के बारे में सरकार विचार करेगी?

श्री ए०सी० चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि क्राईटेरिया के हिसाब से ही कोई इंस्टीच्यूट खोला जाता है। माननीय सदस्य का नोट मुझे प्राप्त हुआ था और उसकी रिपोर्ट के लिए मैंने वह पत्र महकमें को भेज रखा है। महकमे की तरफ से उसकी रिपोर्ट आने पर एक हफ्ते में माननीय सदस्य को उसकी पोजीशन सबमिट कर दी जाएगी।

श्रीमती अनीता यादव: .अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि पूर्व सरकार ने शिक्षा की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया था। अब तो विपक्ष की तरफ कुछ पढ़े–लिखे विधायक बैठे हुए हैं वर्ष 2000 से 2006 के बीच जो सरकार थी वह तानाशाही लोगों की सरकार थी और हम उनको कहा करते थे कि इतना तानाशाही का रवैया ठीक नहीं है। इन्होंसे प्रदेश को गुमराह किया, प्रदेश को लूटा और विपक्ष के सदस्यों के प्रति भी बेहद तानाशाही रवैया अपनाये रखा। उस समय तो इनकी तरफ पढ़े–लिखे लोग नाममात्र को थे जब कि अब तो इनके भी कुछ पढ़े–लिखे लोग बैठे हुए हैं। जब भी हम किसी प्वायंट पर बोलते थे तो हमें बोलने नहीं दिया जाता था और हाउस से बाहर निकाल दिया जाता था। साल 2000 से 2006 तक

हमने वह समय देखा है जब ऐसे– ऐसे विधायक यहां पर बैठे होते थे जो शिक्षा के नाम पर चुप रहते थे। जब हम लोग शिक्षा की बात करते थे, उस समय हमें बैठ जा' कह कर बिठा दिया जाता था। (विघ्न एवं शोर)। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं मेरे विधान सभा क्षेत्र में खुर्शीद नगर गांव है उसके अन्दर बहुत अच्छा ऐजूकेशन इंस्टीच्यूट चल रहा था। पिछली तानाशाही और भ्रष्ट सरकार ने शिक्षा का भट्ठा बिठा दिया और उस सरकार ने इस इंस्टीच्यूट को भी बंद कर दिया था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि क्या वे उस इंस्टीच्यूट को दोबारा से चालू करवाने की कृपा करेंगे?

श्री ए०सी० चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय बहिन जी को बताना चाहूंगा कि इन्होंने कोसली के लिए इंस्टीच्यूट मांगा था उसका कंस्ट्रक्शन वर्क अण्डर हैंड है और उसकी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। हमारी यह पूरी कोशिश है कि विद इन टाईम लिमिट उसका काम पूरा हो जाए। अध्यक्ष महोदय, ऐजूकेशन के प्रचार प्रसार के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है और अपनी वचनबद्धता को पूरा करने के लिए यह सरकार पूरे प्रयास कर रही है।

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे सम्मानित सदस्यों ने तकनीकी शिक्षा के बारे में भारी चिन्ता प्रकट की है। इस बारे में कई माननीय सदस्यों ने

बहुत सारे सवाल भी पूछे हैं और माननीय मंत्री जी ने बहुत सारे सवालों के जबाब भी दिये हैं। स्पीकर सर, आज के युग में तकनीकी शिक्षा सबसे ज्यादा आवश्यक और जरूरी है इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपकी अनुमति से सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार शिक्षा को प्राथमिकता दे रही है। स्पीकर सर, वर्ष 2000–2005 में जो पिछली सरकार थी उसके शासनकाल में तकनीकी शिक्षा का बजट मात्र 29 करोड़ रूपये सालाना था, जबकि वर्ष 2008–09 में हमारी, सरकार में यह बक्स 150 करोड़ रुपये, सालाना है। (इस समय मेजें थपथपाई गई) विपक्ष के माननीय सदस्य कुछ भी कहें इनकी सरकार के कार्यकाल में तकनीकी शिक्षा की कुल सीटें 22 हजार थी (विघ्न)। स्पीकर सर, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि 22 हजार सीटों के मुकाबले में आज हरियाणा में 1,03,890 सीटें हो गई हैं। अध्यक्ष महोदय, जब इनका शासन काल था उस वक्त अगस्त, 2004 में हरियाणा में केवल 78 आई०टी०आईज० थीं और आज हरियाणा में 107 आई०टी०आईज० हैं। 15,000 केवल सीटें थी और आज 22 हजार 112 सीटें हैं। आपके वक्त में कोई सैंटर आफ एक्सीलैंस आई०टी०आई० हरियाणा में नहीं था। आज 16 हैं। सीटिंग कपैस्टी सैन्टर ऑफ एक्सीलैंसं की 2 हजार 736 है। इसके अलावा इन्डस्ट्रीयल ट्रेनिंग सैंटर जो कि प्राईवेटली इन्हवीज्वल बनाते हैं वे इनके समय में 1706 थे और आज 6,880 हैं। यह कहानी तकनीकी शिक्षा के बढ़ावे की चौधरी भूपेन्द्र सिंह डुड्डा की सरकार के वक्त में है।

डॉ० सुशील इन्दौराः आप यह बताएं कि आज आबादी कितनी बड़ी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः क्या साढ़े तीन साल में साढ़े सात गुणा आबादी बड़ी है। (शोर एवं व्यवधान) आप कभी सार्थक बात तो किया करें।

डॉ० सीता रामः ....। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौराः ....। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Nothing is to be recorded. (Interruptions) इनका कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया जाए।

डॉ० सीता रामः ....। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौराः ....। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ए०सी० चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रिक्वैस्ट करूंगा कि बजाए हालात को बिगाड़ने की इनकी साजिश कामयाब हो, इन्होंने जो कहा है कि सारा मंत्रिमण्डल करप्ट है, इस बारे ये सदन में माफी मांगे। इनके ये लफ्ज रिकॉर्ड में से हटा दिए जाए। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता रामः ....। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौराः ....। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Please understand the seriousness of

the question hour. So many members are asking questions. They want to get the information. Please do not interrupt the proceedings.

डॉ० सीता राम: ....। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा: ....। (शोर एवं व्यवधान)

सिंचाई मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव): ये सदन में किस तरह से बात कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ए०सी० चौधरी: अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे हैं कि आबादी बड़ी है तब ये बड़े हैं। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव: स्पीकर सर, ये फालतू बकवास करते हैं। (शोर एवं व्यवधान) इन्होंने सारे मंत्रिमण्डल को भ्रष्ट कहा है, वह कार्यवाही से निकलवा दिया जाना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कैप्टन साहब वह रिकॉर्ड नहीं हुआ है। (शोर एव व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का दूनका व्यवहार सदन के अन्दर नहीं चलेगा। (शोर एवं व्यवधान) We will have to bring a notice for suspending him from the House. (Noise and Interruptions).

Mr. Speaker: Nothing is to be recorded.

डॉ० सीता रामः ....। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौराः ....। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता रामः ....। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Nothing is to be recorded. (शोर एवं व्यवधान) डॉक्टर साहब आप बैठ जाएं। Please take your seat.

Minister of State for Forests (Smt. Kiran Chaudhary): Speaker Sir, what is happening in the House ?

डा० सीता रामः ....। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादवः ....। (शोर एवं व्यवधान) (इस समय रूलिंग और अपोजीशन के सदस्य अपनी सीटों से खड़े होकर बोलने लग गए।)

Mr. Speaker: Nothing is to he recorded. (Interruptions)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर सीता राम जी का व्यवहार सदन में ठीक नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)।

कैप्टन अजय सिंह यादवः इसने सभी मंत्रियों को करप्ट कैसे कह दिया? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कैप्टन साहब, वह रिकॉर्ड नहीं किया गया है। (शोर एवं व्यवधान) पण्डित जी, आप बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान) प्लीज आप सभी अपनी सीटों पर बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान) पार्लियामैंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर बोलने के लिए खड़े हुए हैं। (शोर एवं व्यवधान) Please every member must maintain the decorum and decency of the House.

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, सरकार के द्वारा केवल यह आकड़े दिए गए थे कि जब 2005 में यह सरकार आयी तो उस समय क्या तकनीकी शिक्षा की फिगर्ज थी और आज क्या है? क्या इसके अंदर भी विवाद हो सकता है? क्या हरियाणा के बच्चों को 22 हजार सीटस से एक लाख तीन हजार सीटस उपलब्ध करवाने पर भी विवाद हो सकता है? किस प्रकार का व्यवहार डॉक्टर सीता राम जी कर रहे हैं? ये दूसरी चार सदस्य बनकर आये हैं, नौजवान हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ये बगैर चेयर को ऐड्रैस किए बगैर किसी की अनुमति के किसी के पर भी अवांछित टिप्पणी कर सकते हैं। This is unacceptable, unparliamentary, condemnable and highly derogatory.

डा० सीता राम: स्पीकर साहब, क्या उनका व्यवहार सही था?

श्री अध्यक्ष: डॉक्टर साहब, आप बैठिए। (Interruption).

डॉ० सीता राम: स्पीकर साहब क्या मैंने उनका नाम लिया है? वे तो अपने आप ही उठकर खड़े हो रहे हैं।

Mr. Speaker: Dr. Sahib, please sit down. The Hon'ble Member is asking question (Interruptions). Please maintain the dignity of the House. A delegation is sitting in the Gallery. You must maintain the decorum of the House.

श्री भूपेन्द्र चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने पटौदी के अंदर आई०टी०आई० खोलने की बात कही थी। वहां की म्यूनिसिपल कमेटी ने इसके लिए पांच एकड़ जमीन भी सरकार को दे दी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अब उस आई०टी०आई० की क्या पोजीशन है और कब तक वह आई०टी०आई० वहां पर सरकार के द्वारा खोल दी जाएगी?

श्री ए० सी० चौधरी: स्पीकर सर, जिला गुड़गांव में पटौदी में जटौली के लिए आई०टी०आई० खोलने की पहले भी डिमांड आयी थी। इसके लिए लैंड ट्रांसफर का प्रपोजल आया था। इसका केस डिपार्टमैंट के पास गया हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि ज्यों ही यह पूरा प्रोसैस होकर आएगा और डिपार्टमैंट के नाम जमीन कर दी जाएगी तो उसके बाद हम इस आई०टी०आई० खोलने का अगला प्रोसैस शुरू कर देंगे।

श्री राम किशन फौजी: अध्यक्ष महोदय, बवानीखेड़ा एक बहुत बड़ा कस्बा है। वहां पर एक वोकेशनल इंस्टीच्यूट पहले भी

था लेकिन अब उसकी जगह पर कहा जा रहा है कि आई०टी०आई० खोलेंगे। अध्यक्ष महोदय, हम इसके लिए जमीन भी फी ऑफ कास्ट देने के लिए तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वहां पर आई०टी०आई० खोलने का सरकर का प्रस्ताव है क्योंकि वह एक रूरल एरिया है और वहां पर दूर तक कोई आई०टी०आई० भी नहीं है?

श्री ए०सी० चौधरीः स्पीकर सर, भिवानी में आई०टी०आई० खोलने के लिए दो डिमांडज आयी हैं एक तो बहल में और दूसरे रवलधी में। इन दोनों का काम इन हैंड है। बहल में तो आर०सी०सी० वर्क के काम भी शुरू हो गये हैं। स्पीकर सर, जहां क्क बवानी खेड़ा में आई०टी०आई० खोलने की बात हे मेरे पास अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं आया है। ये लिखकर मुझे भिजवा दें। मैन इस बारे में प्रक्रिया पहले ही बता दी है अगर उसके मुताबिक वहां पर नोर्म्ज पूरे होंगे तो हम उसको प्रोयौरिटी देंगे।

डॉ० शिवशंकर भारद्वाजः स्पीकर सर, भिवानी विधान सभा क्षेत्र के नंद गांव में आई०टी०आई० खोलने की डिमांड की गयी है। यहां पर आई०टी०आई० खोलने से भिवानी और दादरी हल्के के कई गांवों के कलस्टर को फायदा होगा। इसके लिए हम वहां पर जमीन भी देने के लिए तैयार है। अध्यक्ष महोदय, मैं

आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वहां पर आई०टी०आई० खोलेंगे?

श्री ए०सी० चौधरीः स्पीकर सर, भिवानी जिले में आई००टी०आई० खोलने के लिए तीन डिमांड आयी हुई हैं और वे अंडर स्कूटनी हैं। ये इस वक्त प्रोसैस में है। ये तीनों हमें इन हैंड मिली हैं। ज्यों–ज्यों ओफिशिएल कार्यवाही मुकम्मल होती जाएगी हम इन पर साथ–साथ आगे प्रक्रिया करते जाएंगे!

श्री राधे श्याम शर्मा अमरः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। अध्यक्ष महोदय, निजामपुर नलवा के क्षेत्र में बीस पच्चीस गांवों का ऐसा समूह है जहां पर आई०टी०आई० की आवश्यकता है। वहां पर हम आई०टी०आई० खोलने के लिए फी जमीन भी देने के लिए तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वहां पर आई०टी०आई० खोलने का सरकार विचार करेगी?

श्री ए०सी० चौधरीः अध्यक्ष महोदय, आई०टी०आई० खोलने के क्राईटेरिया केवल जमीन का ही नहीं है। हमें यह भी देखना पड़ता है कि वहां पर स्कूल कितने हैं, कितने बच्चे पढने वहां आ सकते हैं और उसके आसपास कितने आई०टी०आईज० हैं। अगर ये सारा क्राईटेरिया वहां पर पूरा होगा तब हम आगे की कार्यवाही पूरी करते हैं।

श्री ईश्वर सिंह पलाकाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जैसा मुख्यमंत्री महोदय ने भी कहा है कि यदि जमीन दिलवाएंगे तो हम आई०टी०आई० जरूर बनवाएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि रादौर एक बहुत बड़ा कस्बा है। क्या वहां आई०टी०आई० खोलने का प्रावधान है? यदि हम पंचायत के माध्यम से वहां जमीन जो आई०टी०आई० बनाने के लिए उचित हो, उपलब्ध कराएं तो क्या वहां आई०टी०आई० खोलने पर विचार किया जाएगा?

श्री ए०सी० चौधरीः अध्यक्ष महोदय, इस सवाल पर भी जवाब तो वही होगा कि जब तक डिमांड नहीं आएगी और जब तक उसका क्राइटेरिया चौक नहीं होगा, तब तक यह नहीं हो पाएगा। माननीय सदस्य डिमांड भिजवा दें और मुझे एक महीने का समय दे दें, फिर मैं सारी इन्फर्मेशन कलैक्ट करके इनके साथ बैठकर डिस्कस कर लूंगा कि क्या रिक्वायरमैंट्स हैं ताकि ये भी उसको पूरा करवाने में हमारी मदद करें और अपनी स्टेट की डिवैल्पमैंट में सहयोग दे सकें।

श्री अध्यक्षः आप लिखकर भिजवा दें फिर इस बारे में मंत्री जी क्राइटेरिया दिखवा लेंगे।

श्री नरेश कुमार शर्मा प्रधानः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे बादली विधान सभा क्षेत्र से 50 किलोमीटर दूर स्थित बापडौदा में आई०टी०आई०

खोल दी गई है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। मेरे बादली विधान सभा क्षेत्र में माजरी गांव है जिसके अंदर 20 कमरे ग्राम सभा ने बना दिये हैं। मैं आग्रह करूंगा कि वहां जल्द से जल्द आई०टी०आई० खोली जाए। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए।) बादली की ग्राम पंचायत 8 एकड़ जमीन देने के लिए भी तैयार है और बामडौला के अंदर 10 एकड़ जमीन ग्राम पंचायत ने दे रखी है। कृपा करके बताएं कि इस दिशा में क्या कार्यवाही हो रही है? धन्यवाद।

श्री ए०सी० चौधरी: उपाध्यक्ष महोदय, तीसरी चौथी बार मैं इस सदन को पॉलिसी के बारे में स्ट्रैस कर चुका हूं। जो प्री रिक्यीजिट्स हैं, जो रिक्वायरमैंट्स हैं, जो नॉर्म्स हैं वह जब तक पूरे नहीं होते तब तक हम कोई भी प्रौजैक्ट अप्रूव नहीं कर सकते हैं। आन दि फ्लोर ऑफ दि हाउस यहाँ पर डिमांड रख कर कैटेगरीकली इस बारे में जवाब नहीं दिया जा सकता है। मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे इस बारे में डिमांड लिखकर भिजवाए और मुझे 15–20 दिन या 30 दिन का समय दें, उसके बाद बैठकर बातचीत कर लेंगे तो अगले सैशन में आपको यहां सवाल रखने की नौबत ही नहीं आएगी। श्रीमती राज रानी पूनमः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि मेरे हल्के में मतलौडा में आई०टी०आई० खोलने के लिए कंप्लीट पेपर्ज दिये हुए हैं। क्या वहां आई०टी०आई० बननी विचाराधीन है?

श्री ए०सी० चौधरीः सर, मतलौडा का अभी इस स्टेज पर बताना संभव नहीं है क्योंकि इसके लिए प्रोसैस से उठकर डिपार्टमैंटल अप्रूवल के लिए पेपर्ज नहीं आए हैं। आफ हैण्ड मैं इतनी जानकारी रखता हूं कि मतलौडा में आई०टी०आई० खोलने के लिए पेपर काफी एडवांस स्टेज पर हैं।

श्री नरेश यादवः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से मेरे हल्के में अटेली के पास सुर्जापुर में एक वोकेशनल इंस्टीच्यूट था, उसको आई०टी०आई० का दर्जा देने का ऐलान किया था लेकिन वहां अब तक न तो कोई बिल्डिंग बनी है न ही वर्कशाप बनी है। कब तक वहां की बिल्डिंग, वर्कशाप और आई०टी०आई० बन जाएगी? क्या कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

श्री ए०सी० चौधरीः उपाध्यक्ष महोदय, एक सवाल छोड् कर अगला ही सवाल इस बारे में है। यदि इस सवाल को उसके साथ लिंक कर लें तो अच्छा रहेगा क्योंकि टाइमआउट होता जा रहा है।

श्री उपाध्यक्षः नरेश यादव जी, आप इस बारे में लिखकर भिजवा दैना।

प्रो० छत्तर पाल सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, अभी पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर ने ऑन बिहाफ आफ टैक्नीकल

ऐजूकेशन मिनिस्टर एक फिग्गर बताई थी, मैं जानना चाहता हूं कि डिग्री डिप्लोमा के अंदर बी० फार्मेसी डिप्लोमाज को इंक्लूड करके फिगर बताई है या उनको अलग रखकर बताई है?

श्री ए०सी० चौधरी: उपाध्यक्ष महोदय, जिस फिगर का ये जिक्र कर रहे हैं उसके बारे में मुझे पता नहीं है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस फिगर के बारे में बताया था, मैं क्लीयर कर देता हूं। Intech. of the Department also includes this figure for B. Pharmacy.

Construction of Bridge on Ghaggar River

***1031. Dr. Shushil Indora:** Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to construct a bridge on Ghaggar river for linking Kutawadh directly to Dania city in Ellenabad Constituency ; and

(b) if so, the estimated expenditure likely to he incurred thereon togetherwith the time by which it will be constructed ?

Irrigation Minister (Capt. Ajay Singh Yadav):

(a) No, Sir

(b) Question does not arise.

डॉ० सुशील इन्दौराः माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश में बरसाती नदी घग्गर प्रदेश के कई भागों से होकर गुजरती है, जो कई खेत–खलियानों को तथा गांवों और शहरों को बहुत ज्यादा उजाड़ देती है। वर्तमान सरकार किसान हितैषी है और आम आदमी के लिए कुछ करने वाली सरकार है और अक्सर हरियाणा को नम्बर एक बनाने वाली सरकार है हालांकि हरियाणा अब तक नम्बर एक बना नहीं है। (विघ्न)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुडा): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय साथी को मालूम होना चाहिए कि पर कैपिटा इन्वेस्टमैंट में पिछली सरकार के समय हरियाणा का चौदहवाँ नम्बर था जबकि आज हरियाणा नम्बर एक पर है। आगे सुनो, व्हीट की प्रोडैक्टिविटी मे पहले पंजाब आगे था लेकिन आज हरियाणा नम्बर एक पर है और मिल्क प्रोडैक्शन में हरियाणा नम्बर एक पर है और पर कैपिटा इन्कम में बड़े स्टेट्स में हरियाणा नम्बर एक पर है। हरियाणा गोवा को छोड़कर क्योंकि गोवा में टूरिज्म की इन्कम ज्यादा है। हरियाणा नम्बर एक और कैसे बनेगा? प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है। औलम्पिक गेम्ज में भी हरियाणा नम्बर एक रहा है।

डा० सुशील इन्दौराः माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हरियाणा कई मामलों में नम्बर एक पर है। साथ में यह भी बताएं कि क्या बी०पी०एल० के कार्ड बनाने में और कानून–व्यवस्था में भी हरियाणा नम्बर एक पर है? (विघ्न)

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): उपाध्यक्ष महोदय, यह क्वैश्चन ऑवर है, माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिए। ये सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं।

डा० सुशील इन्दौराः माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कई मामलों में हरियाणा नम्बर एक पर है तो मैं भी यह कहना चाहता हूं कि इसमें एक दो नम्बर और जोड़ दें ताकि मुख्यमंत्री जी उन पर कंट्रोल कर लें। (विघ्न) मैं स्पलीमैंटरी ही पूछ रहा हूं कि जो घग्गर बरसाती नदी है उससे कई गांवों में बाढ़ आ जाती है। (विघन) **श्री कर्ण सिंह दलालः** उपाध्यक्ष महोदय जी, जब इनकी सरकार थी तब ये कहां गये हुए थे? (विघन)

Mr. Deputy Speaker: Indora Sahib, ask your specific question.

डॉ० सुशील इन्दौराः माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आदरणीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि किसानों के भले के लिए और आम जनता के भले के लिए ये पुल बनाने का काम करेंगे जिससे किसानों को फायदा होगा और आम जनता को भी फायदा होगा। (विघन) वहां पर पुल बनने से वाटर लैवल०पर आयेगा। क्या रानिया शहर को कुटावड और केहरवाल गांव से सीधा जोड्ने के लिए कुटावड से रानिया के बीच में पुल बनाने का काम करेंगे क्योंकि गुडानिया खेड से सड़कें बनी हुई हैं थोड़े से खर्च की बात है? मुख्यमंत्री जी एक बात बता दूं कि यदि आप

यह काम कर देंगे तो सदा–सदा के लिए हिन्दी में आपका नाम लिखा जायेगा।

Mr. Deputy Speaker: Please take your seat. आप भाषण देने लग गये।

डा० सुशील इन्दौराः माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं क्यैशचन ही पूछ रहा हूं कि क्या आप एक समयबद्ध तरीके से केहरवाल से कलवाडा को जोड़ते हुए वाया गुडानिया खेड से और कुटावड से रानिया को जोड़ते हुए इन दोनों पुलों को बनाने का काम करेंगे?

कैप्टन अजय सिंह यादवः उपाध्यक्ष महोदय, गांव कुटावड से रानिया कनैक्ट होता हे जिसकी दूरी वाया ओटू होकर जायें तो 18 किलोमीटर की है। ओटू गांव है वहां पर पुल है। यह बात सही है कि यह पुल बनने से रानिया और कुटावड गांव की दूरी साढ़े आठ किलोमीटर की रह जाएगी। कुटावढ गांव की आबादी तकरीबन 4191 है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि अगर यह पुल बनता है तो इस पर 12 करोड़ रुपये के करीब खर्च होगा। हम कसल्टैंट अप्यांयट कर देंगे और वे इसकी स्टडी करेंगे और उनकी रिपोर्ट फिजीबल हुई तो हम एक वैबसैसको नाम की कम्पनी को या फिर किसी अच्छे कंसल्टैंट को यह काम देंगे और अगर वे इसको एप्रूव कर देते हैं और वे कहते हैं कि ये वायबल है तो हम इस केस को नाबार्ड को भेज देंगे।

डॉ० सुशील इन्दौराः उपाध्यक्ष महोदय, रतिया में घग्घर नदी पर ऐसा ही पुल बना हुआ था लेकिन पता नहीं किन कारणों से वह पुल टूट गया और घग्घर नदी में पानी का बहाव बढ़ गया जिससे काफी जान माल की हानि हुई। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस हादसे में मरने वालों को क्या मुआवजा दिया गया क्योंकि इस बारे में किसी को नहीं पता? सरकार ने इस बारे में क्या–क्या कदम उठाए हैं? क्या इस पुल की इन्क्वायरी करवाई गई है कि यह पुल क्यों टूटा तथा इस पुल को बनाने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है?

कैप्टन अजय सिंह यादवः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि 2000–2005 तक इनकी सरकार में 22 पुल बने थे जबकि हमारी सरकार ने आज तक 3 सालों में 3028 करोड़ रुपये की लागत से 24 पुल बनाए हैं। 13 पुल ऐसे हैं जिन पर काम चल रहा है और ये 31 मार्च 2009 तक बन जाएंगे। इस प्रकार कुल 37 पुल मार्च, 2009 तक हमारी सरकार बना देगी। इसके अलावा 35 पुल, पाइप लाइन में है। उपाध्यक्ष महोदय, जहां भी पुल बनाने के लिए कंसल्टैंट की रिपोर्ट फिजीबल होगी हम वहां पुल बनाएंगे। जहां तक इन्होंने रतिया का जिक्र किया कि पुल टूट गया तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि रतिया में घग्घर नदीं पर बना पुल टूटा नहीं था बल्कि वहां भारी इम्बैंकमैंट था, पानी का बहाव तेज था। पुल नहीं टूटा

बल्कि बांध को चीरकर एक सड़क ढह गई। उस समय लोग स्कूटरों से उस सड़क से जा रहे थे तो कुछ लोगों की उस जगह पर मौत हो गई थी। इस केस में एक एक्सीयन को सस्पैंड किया गया है, एस०ई० को चार्जशीट कर रहे हैंय जे०ई० को सस्पैंड किया गया है और एक एस०डी०ओ० को जो रिटायर भी हो गया है, फिर भी उसको रूल 7 के तहत चार्ज शीट किया गया है। गलत काम करने वालों के खिलाफ मौजूदा सरकार, कार्यवाही करती है। जब बारिश होती है हम बकायदा चौकिंग करवाते हैं। यह जो रतिया में हादसा हो गया है, इसके लिए हमें दुःख है। इस हादसे में कुछ लोगों की मौत हो गई लेकिन इस केस में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

Restoring the status of Municipal Committee of Hassanpur Town

***1025. Shri Udai Bhan:** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Govt. to restore the status of Municipal Committee of Hassanpur Town which was dissolved and converted into Gram Panchayat by the previous Govt.; if so, the details thereof ?

Urban Development Minister (Sh. A.C. Chaudhary): No, Sir.

श्री उदय भान: उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय जी भली भांति अवगत हैं कि हसनपुर में लगभग 30 सालों से नगरपालिका है। जिसको पिछली ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार ने अपनी

दुर्भावना के कारण भंग कर दिया था। हसनपुर की आबादी लगभग 16 हजार की है। यहां पर अनाज मंडी है, पी०एच०सी० है, ब्लाक समिति है, पुलिस स्टेशन है, लत के०वी०ए० सब–स्टेशन है और वहां पर बिजली बोर्ड का एस०डी०ओ० भी बैठता है, पी०डब्ल्यू०डी० रैस्ट हाउस है, बैंक है, बस स्टैण्ड है, कालेज है, प्रोफैशनल कालेज है, गवर्नमैंट गर्ल्ज सीनियर सैकेंडरी स्कूल है, गवर्नमैंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर ब्यायज भी है, 50 प्राइवेट स्कूल हैं, पंचायतों की 65 दुकानें हैं, तेल मिल है, चावल मिल है, सरसों मिल है और 700 दुकानें हैं और 3000 मकान हैं। हसनपुर में पूरा इन्फ्रास्ट्रक्चर है और मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों के अनुसार यहां यमुना का पुल बनाने के लिए भी बात चल रही है। इसके अतिरिक्त होडल–हसनपुर रोड पर आर०ओ०बी० बनाने पर भी सरकार विचार कर रही है। इसके अलावा अलीगढ़–मधुरा रोड भी यहां पर निकलेगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से हसनपुर के अंदर पूरा इन्फ्रास्ट्रक्चर मौजूद है और हसनपुर की नगरपालिका पहले भी कभी लौस में नहीं रही, हमेशा प्रोफिट में रही है। हसनपुर नगरपालिका की अपनी दुकानें भी हैं, हाउस टैक्स और चूल्हा टैक्स भी आता है इसलिए वह नगरपालिका अच्छी तरह से चल सकती है। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि क्या मंत्री जी हसनपुर नगरपालिका का दर्जा बहाल करने की घोषणा करेंगे?

श्री ए०सी० चौधरीः डिप्टी स्पीकर सर, मैं आदरणीय साथी का सम्मान करता हूं और हाउस को बताना चाहता हूं कि

जहां पब्लिक का चुना हुआ नुमाइंदा एक बार नहीं चार–चार बार इलाके की आबादी 16 हजार डिक्लेयर कर रहा है, वहीं पिल्ली सरकार ने जिसने हसनपुर नगरपालिका को भंग किया था उसकी आबादी 9090 दिखाई थी और इसी आधार पर हसनपुर नगरपालिका को उन्होंने भंग किया था। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी जानकारी ली थी और मुझे आदेश दिए हैं कि हसनपुर के साथ नाइंसाफी न हो। जिस समय यह नगरपालिका भंग की गई थी उस समय इसकी आमदनी 12,19,474 रुपये दिखाई गई थी और खर्चा 12,46,000 दिखाया गया था। उपाध्यक्ष महोदय, यह रिपोर्ट पुरानी है और मुझे लगता है कि इसमें कोई न कोई चूक है।

मैं आदरणीय साथी का मान करते हुए यह कहना चाहूंगा कि हम इसको रिव्यू करवायेंगे और यदि संभव होगा तो माननीय साथी ने जो मांग की है उसको पूरा किया जायेगा।

मुख्यमंत्री ('श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने जो सवाल हसनपुर के बारे में उठाया है, मंत्री जी ने उसका जबाब दे दिया है। मैं भी माननीय साथी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि यदि हसनपुर में नगरपालिका की वायबिलिटी और फीजीबिलटी होगी तो हम इसका नगरपालिका का दर्जा बहाल कर देंगे।

श्री कर्ण सिंह दलालः उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने चौधरी उदयभान के सवाल के जवाब में उदारता दिखाते हुए उस इलाके की बहुत बड़ी समस्या के बारे में अपना वक्तव्य दिया है और आश्वासन भी दिया है कि उनके साथ न्याय होगा। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री श्री ए०सी० चौधरी जी ने जनसंख्या के बारे में बात की है। इस बारे में मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जनसंख्या का जो सैंसैक्स रिकॉर्ड हमारे मुल्क का और प्रदेश का है उसमें से ही हसनपुर की जनसंख्या का पता लगाया जा सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं है जैसा कि चौधरी उदयभान जी ने कहा कि पिछली सरकार ने दुर्भावना से हसनपुर के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था। हमारे मुख्यमंत्री जी ने हसनपुर नगरपालिका को बहाल करने के लिए अपना वक्तव्य दिया है, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मुझे पूर्ण आशा है कि हसनपुर नगरपालिका को जल्दी ही बहाल किया जायेगा।

श्री ए०सी० चौधरीः उपाध्यक्ष महोदय, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुहर लगा दी है तो इस पर आगे चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं है। पिछली सरकार नै जो गलतियां की है उनके बारे में मैंने बता दिया है। हम इसको मान्यता देते हुए जल्द बहाल करने के लिए अपना प्रोसैस शुरू कर देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री जी, पुनहाणा में भी नगरपालिका बनाई जानी थी। उसकी फाईल आपके पास आई हुई है। उसको कब तक नगरपालिका बनाया जायेगा?

श्री ए०सी० चौधरी: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुनहाणा के अंदर चार पंचायतें पड़ती है और उन चारों पंचायतों ने प्रस्ताव पास करके भेजा हुआ है कि पुनहाणा में नगरपालिका न बनाई जाये। उपाध्यक्ष महोदय, फिर भी आपने मुझे इस बारे में कहा था तथा मैंने आपको कहा था कि आज सैशन खत्म हो जायेगा और कल मैं आपके साथ बैठकर जैसे भी होगा इस मामले को निपटा देंगे।

मेजर नृपेन्द्र सिंह सांगवान: उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दादरी नगरपालिका की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि बाढ़ के दौरान दादरी नगरपालिका की हालत बहुत जर्जर हो गई है। पिन्ने एक साल से दादरी नगरपालिका में कोई भी अधिकारी नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पता है कि अधिकारियों की कमी है। परंतु बाढ़ की वजह से वहां इतने बुरे हालात हो गये हैं कि इन पर काबू पाने के लिए वहां पर एक सक्रेटरी, एकाउंटैंट और एक जे०ई० की सख्त जरूरत है। इनका जल्दी से जल्दी प्रबंध किया जाये नहीं तो दादरी के सारे के सारे वाशिंदे तकलीफ में रहेंगे।

श्री ए०सी० चौधरी: उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय मेजर साहब ने सही बात कही है कि बरसात इतनी ज्यादा हुई है जिसकी वजह से किसानों की फसल बरबाद हो गई और सारे की सारी सड़कें टूट गई। मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि बरसात का सीजन खत्म होने के बाद मैं स्वयं प्रदेश की सभी कमेटियों का दौरा करूंगा। हमने आदेश भी दे दिए हैं कि पैचिंग का काम दो महीने के अंदर–अंदर पूरा कर दिया जाये। इसके अतिरिक्त बरसात की वजह से जहां मेजर रोडज डैमेज्ड हुई हैं उनके सारे एस्टीमेटूस दोबारा हमें भेज दिए जायें या फीगर्ज ही भेज दो जाये ताकि हम उनका पूरी तरह से इंतजाम करवा सकें। इसके साथ–साथ जहां तक स्टाफ की कमी का ताल्लुक है, ऑन रिकॉर्ड मैंने अभी इसी हफ्ते ऑर्डर किए हैं कि जहां–जहां जरूरी स्टाफ की कमी है वहां पर डी०सी० रेट्स पर भर्ती करके स्टाफ की कमी को पूरा कर लिया जाये।

श्री उदय भान: डिप्टी स्पीकर सर, हमारी डिमाण्डज को बड़ी उदारता से स्वीकार करने के लिए, मे आपके माध्यम सै माननीय मुख्यमत्री महोदय और मंत्री महोदय का बहुत–बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

श्री सोमवीर सिंह: डिप्टी स्पीकर सर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि लोहारू की म्युनिसिपल कमेटी के अन्दर हॉस्पिटल को जो रोड जाती है उसकी हालत बहुत खस्ता है। मैंने पिछले सैशन दमे दौरान भी उसको बनवाने की प्रार्थना की थी।

उस समय मुझे उसको जल्दी बनवाने का आश्वासन भी दिया गया था लेकिन उसे अभी तक भी नहीं बनाया गया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या उसको जल्दी से जल्दी बनवाने की कृपा करेंगे?

श्री ए०सी० चौधरी: डिप्टी स्पीकर सर, मैं समस्त हाउस को आश्वस्त कर रहा हूं। एक तो बारिश की वजह से लगभग सारी सड़कें डैमेज हो चुकी हैं और दूसरा बारिश का मौसम जल्दी शुरू हो जाने की वजह से जो काम हमें शुरू करने थे वे भी हम समय पर शुरू नहीं कर पाये जिससे वे काम वैसे के वैसे ही रह गये। अब भगवान की कृपा से मौसम साफ हो चुका है। इसी सितम्बर मास में ही मै पूरी स्टेट की म्यूनिसिपल कमेटी की सड्कों का सर्वे करवाकर सड्कों की रिपेयर का काम करवाने का आश्वासन देता हूं,। यहां एकु बात मैं और स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब मैं दादरी की बात कर रहा हूं तो उसमें तोशाम, लोहारू और भिवानी सभी शामिल हो गये हैं, ऐसा समझना चाहिए। मेरी पहली प्राथमिकता माननीय सदस्य के जिले की विजिट ही होगी।

श्री हबीब–उर–रहमान: डिप्टी स्पीकर सर, सबसे पहले तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने मेरी कास्टीच्यूएंशी नूह को हरेक मामले में प्राथमिकता दी और मेवात को जिला बनाया। मेवात को जिला बनाकर इन्होंने मेवात के लोगों के०पर एक बहुत बड़ा अहसान किया है। चारों तरफ से जो इलाका–ए–मेवात की तरक्की के लिए जरूरीयात थी

चाहे वह पॉलिटेक्नीकल कॉलेज हो, चाहे इंजीनियरिंग कालेज हो, चाहे आई०टी०आई० हो, चाहे मेवात फीडर कैनाल हो और चाहे कोटला लेक हो, मेवात की तरक्की के लिए अनेकों योजनायें लागू की हैं। मैं मंत्री महोदय से दो सवाल पूछना चाहता हूं। मेरा पहला सवाल तो यह है कि जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मेवात कै अन्दर हरियाणा प्रदेश की पहली सबसे बड़ी आई०टी०आई० खोलने की घोषणा करके उसकी आधारशिला रखी थी उसके कंस्ट्रक्शन का काम कब तक शुरू हो जायेगा? दूसरा सवाल मेरा यह है कि नूह जो कि पहले सब–डिवीजन थी अब जिला बन गया है इसकी बॉऊण्डरीज के लिए एक प्रस्ताव आया हुआ है क्योंकि यह पहले सब–डिवीजन था और अब जिला बन गया है इसीलिए इसकी इन्कम भी बहुत कम है, क्या इन्कम बढ़ाने के लिए इसकी बॉऊण्डरीज बढ़ाये जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

श्री ए०सी० चौधरी: डिप्टी स्पीकर सर, अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने नूह में आई०टी०आई० का फाऊंडेशन स्टोन ले किया था उस दिन बाकायदा तौर पर उसे रिव्यू भी किया गया था। माननीय मुख्यमंत्री ने पी०डब्ल्यू०डी० (बी० एण्ड आर०) डिपार्टमैंट को भी कहा था किं इसका काम शुरू कर दिया जाये। इसके लिए टैण्डर वगैरह' की जो प्रोसैस होती है वह पी० डब्ल्यू डी० (बी० एण्ड आर०) डिपार्टमैंट के लैवल पर हो रही है। मैं खुद भी इसको चौक कर लूंगा। सैशन के बाद मैं इसी के

फोलो–अप में लगूंगा। इसके अतिरिक्त जहां तुक सीमायें बढ़ाने का ताल्लुक है, अभी तक मेरे पास प्रशासन की तरफ से इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं आया है। फिर भी अगर इस प्रकार का कोई प्रस्ताव आयेगा तो हम उस पर अवश्य काम करेंगे। (इस समय माननीय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए) मैं स्वयं भी नूह की ग्रिवैंसिजं कमेटी की मीटिंग्स में जाता हूं और इस बारे में लोगों की भावनाओं को मैंने महसूस किया है इसलिए मैंने स्वयं भी इसकी रिपोर्ट मांगी हैं।

श्री नरेश यादवः अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि अटेली और कनीना की म्यूनिसिपल कमेटीज को इन्होंने दोबारा बहाल कराया। ये म्यूनिसिपल कमेटीज 12 साल के बाद बहाल हुई हैं इसलिए वहां पर कोई पैसा नहीं है। इसलिए मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि अटेली और कनीना की म्यूनिसिपैल्टीज में पैसा देकर सड्कों और सीवरेज को ठीक करवायें।

श्री ए० सी० चौधरीः अध्यक्ष महोदय, इसके लिए क्राइटेरिया फिक्स किया जाता है कि म्यूनिसिपैल्टीज अपने साधनों से अपने आपको मेनटेन कर लें। अभी म्यूनिसिपैल्टीज स्टेटस सिम्बल बनती जा रही हैं। हर गाँव, गाँव को तोड़ कर उसको स्टेटस सिम्बल के तौर पर म्यूनिसिपैल्टीज बनवाना चाहता है। माननीय सदस्य की म्यूनिसिपैल्टी अभी बहाल हुई है इसलिए मैं चाहूंगा कि उसका ऐस्टीमेट बनवा कर या और कोई रिक्वायरमैंट

हो तो वह भी आप भिजवा दें, वह हम कर देंगे। अगर सरकार के लैवल पर टैक्नीकल अप्रेवल या एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रुवल की बात हो तो जिस दिन भी केस यहाँ आ जायेगा मुझे इतला कर देना, मैं 24 घंटे में दोनों अप्रूवल भेज दूंगा।

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now the Question Hour is over.

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांक्ति प्रश्नो के लिखित उत्तर

Opening of I.T.I. in Bhojawas

***1005. Sh. Naresh Yadav:** Will the Industrial Training & Vocational Education Minister be pleased to state:-

(a) Whether there is any proposal under consideration of the Govt. to open an I.T.I. in Bhojawas near Kanina ; if so, the time by which it is likely to be opened ; and

(b) the steps taken by the Govt. to accord the full status of I.T.I. to the Vocational Institute situated at village Sujapur of Ateli Constituency together with the full details thereof ?

शहरी विकास मंत्री (श्री ए०सी० चौधरी):

(क) कनीना के निकट गांव भोजावास में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का केस सरकार के विचाराधीन है। इस बारे समय–सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

(ख) व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, सुजापुर को स्वतन्त्र औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में परिवर्तित करते हुए इस वर्ष 3 व्यवसायों में तृप्त स्वीकृत सीटों के प्रति प्रथम वर्ष का दाखिला किया गया है।

Milling of Rice

***1033. Sh. Radhey Shayam Sharma:** Will the Agriculture Minister be pleased to state:-

(a) whether it is fact that the Haryana Agro-Industries Corporation had got done milling of rice from M/s Subash Rice Mill of Palwal during the period from April, 2002 to April, 2004 ; if so, the amount of loss caused to the Corporation on account of it.

(b) the name of the officer/officials responsible for the above said loss ; togetherwith the action taken against them ?

कृषि मंत्री (सरदार एच०एस० चट्ठा):

हां, श्रीमान जी,

(क) हरियाणा कृषि उद्योग निगम ने खरीफ मार्केटिंग सीजन 2003–2004 के दौरान मै० सुभाष राईस मिल्ज, पलवल से धान की मिलिंग करवाई थी और निगम को रुपये 2440506/– जमा ब्याज की हानि हुई। निगम ने हानि की वसूली के लिए मै० सुभाष सईस मिल्क, पलवल के विरुद्ध आरबीटरेटर के पास केस दायर किया हुआ है।

(ख) इस हानि के लिए जिम्मेवार श्री पी०सी० गोयल, तत्कालीन जिला प्रबन्धक, किसान सेवा केन्द्र, पलवल को कार्यालय द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया था। कार्यालय द्वारा नियमानुसार सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात् उनके वर्तमान वेतनमान को तुरन्त प्रभाव से तीन वर्ष की अवधि के लिए निम्न वेतनमान में बदलने का दण्ड दिया गया है तथा इसके साथ हानि की राशि की वसूली के आदेश किए जा चुके हैं।

Completion of Sewerage Work of Narnaund Municipal Committee

***1014. Shri Ram Kumar Gautam:** Will the Water Supply & Sanitation Minister be pleased to state the time by which the sewerage work of Narnaund Municipal Committee is likely to be completed ?

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): नारनौंद शहर में केवल 15 प्रतिशत तक मल निकासी व्यवस्था लगी हुई थीं सरकार ने वर्ष 2006–07 में पूरी मल निकासी व्यवस्था लगाने, डिस्पोजल बनाने तथा भूमि अर्जित करने के लिए 291 लाख रुपये की प्रशासकीय अनुमति प्रदान की। इस योजना को पूरी धनराशि आबंटित की जा चुकी है जिसके विरुद्ध 140.69 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं। डिस्पोजल के लिए भूमि का अधिग्रहण उच्चतम न्यायालय तक चली लम्बी मुकदमेबाजी के उपरान्त हुआ। सीवरेज लाईन तथा डिस्पोजल का कार्य 30.6.2009 तक सम्पन्न होने की संभावना है।

शौक प्रस्ताव

Mr. Speaker: Now, Hon'ble Chief Minister will make obituary references.

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): अध्यक्ष महोदय, पिछले सैशन और इस सैशन के बीच में हमारे जो साथी हमें छोड़ कर चले गये उनके लिए जैसे हमने पहले शोक प्रस्ताव पेश किया था उसमें किसी कारण से दो शोक प्रस्ताव छूट गये थे उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि यह सदन हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मास्टर हुक्म सिंह के पोते श्री विजय फौगाट तथा हरियाणा के पूर्व मंत्री श्री सुरेन्द्र मदान की माता श्रीमती बेवाबाई के दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। यह सदन दिवंगत आत्माओं के शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

डा० सुशील इन्दौरा: अध्यक्ष महोदय, मैं भी अपने आपको सदन के नेता के साथ जोड़ते हुए अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं तथा दिवंगत आत्माओं के शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, सदन के नेता श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने जो शोक प्रस्ताव हाउस मैं रखा है, मैं भी अपने आपको उनकी भावनाओं के साथ जोड़ता हूं। मुझे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हुक्म सिंह के पोते श्री विजय फौगाट तथा

हरियाणा के पूर्व मंत्री श्री सुरेन्द्र मदान की माता श्रीमती बेवाबाई के दुखद निधन पर गहरा शोक है। मैं परमपिता परमात्मा से दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। शोक संतप्त परिवारों तक इस सदन की संवेदना पहुंचा दी जायेगी। अब मैं दिवंगत आत्माओं के सम्मान में दो मिनट का मौन धारण करने के लिए सदन के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं।

(इस समय दिवंगत आत्माओं के सम्मान में सदन में दो मिनट का मौन धारण किया गया।)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैंने आपकी सेवा में एक कालिंग अटैंशन मोशन दिया है कि पश्चिम बंगाल में टाटा की जो नैनो कार तैयार हो रही थी वह पश्चिम बंगाल के लोगों तथा सरकार की खिलाफत के कारण वहाँ से शिफ्ट हो रही है। आज के अखबार में उसके बारे में छपा भी है। टाटा ने उसको वहाँ से शिफ्ट करने की बात कही है।

श्री अध्यक्षः दलाल साहब, आपकी कालिंग अटैंशन मोशन अभी अण्डर कंसीड़ेशन है।

श्री कर्ण सिंह दलालः ठीक है सर।

सदस्यों का नाम लेना/वाक–आऊट

डा० सुशील इन्दौरा: अध्यक्ष महोदय, कल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के खिलाफ जो विशेष रिपोर्ट लाई गई है, वह सरासर असंवैधानिक है। (शोर एवं व्यवधान) **बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला):** अध्यक्ष महोदय, ये जो अब कर रहे हैं यह भी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है क्योंकि अध्यक्ष महोदय, एक कमेटी आपके द्वारा बनाई गई थी! उस कमेटी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट श्री कर्ण सिंह दलाल ने पेश की है।

श्री अध्यक्ष: डॉ० इन्दौरा, आप एक मिनट सुनिये। आप इंटरनल रिपोर्ट पेश होने दें। Now, the report is under consideration and nothing has been finalized yet. (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा: अध्यक्ष महोदय, रिपोर्ट पेश होना ही तो असंवैधानिक है। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: No. Nothing is unconstitutional.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, ये जो अब कर रहे हैं यह भी ब्रीच आफ प्रिविलेज है। हर बार जब रिपोर्ट आती है तो ये वैल में आकर शोर करते हैं। चौटाला जी इनको सदन में भेज देते हैं। वे यहाँ आकर बैठे, सुनें और अपने डिफैन्स में कुछ कहें। उनकी दलील सुन कर हो सकता है यह सदन इस रिपोर्ट को खारिज भी कर सकता है। अध्यक्ष महोदय, इनको चाहिए कि ये पूरी बात सुनें। (विघ्न एवं शोर) अध्यक्ष महोदय, जो

दोषी है, जिसको सजा मिलनी हे वह खुद तो हाउस में नहीं आता लेकिन वह इनके कन्धे पर बन्दूक रख कर चलाने में लगा हुआ है। वे यहां हाउस में आएं और यहा आ कर पूरी बात सुनें। उनको भी अपनी बात कहने का पूरा मौका मिलेगा। हो सकता है यह सदन उनकी बात से सहमत हो और यह रिपोर्ट वापिस हो जाए। (विघ्न एवं शोर) अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की बात कह कर ये लोग हाउस का समय खराब कर रहे हैं। (विघ्न एवं शोर) अध्यक्ष महोदय, इनकी अपनी कालिंग अटेंशन मोशन लगी हुई है, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेहरबानी करके उसको टेक अप करें। (विघ्न एवं शोर)

Dr. Sushil Indora: Speaker Sir, this is not fair. मैं यह रिक्यैस्ट करता हूं कि हमारी बात सुनी जाए। (विघ्न एवं शोर)

श्री अध्यक्षः आपकी बात कौन नहीं सुन रहा है (विघ्न) आपको बोलने का पूरा मौका दिया गया है।

डा० सुशील इन्दौराः स्पीकर सर, आप रूल 218 देखें। (विघ्न)

श्री रणदीप सिंह सुरजेबालाः अध्यक्ष महोदय, आप रिकॉर्ड निकलवा कर देख लें कि इनको बोलने के लिए कितना समय दिया है। (विघ्न) जब यह रिपोर्ट आएगी तो' ये उस पर टिप्पणी कर सकते हैं। स्पीकर साहब, अभी वह रिपोर्ट आएगी। ये चौटाला साहब को बुलवा लें वे इस विषय पर अपनी बात कह

सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान) Speaker Sir, he can raise any issue while speaking on the Report of the Committee which is listed in today's agenda. It is not the issue of Zero Hour. ये कमेटी की रिपोर्ट सबमिट होने के बाद उस पर अपनी टिप्पणी कर सकते हैं।

Mr. Speaker: The matter has been referred to the Committee of Privileges. (interruptions) This is not the way. Special opportunities have been given to the Hon'ble Members. Mr. Om Parkash Chautala was asked to explain his position to the Committee but he was intentionally avoiding the meetings of the Committee. If he is disobeying the Committee, it means that he is disobeying the House. Mr. Indora, it is a sorry state of affairs. (Interruptions)

डॉ० सुशील इन्दौरा: स्पीकर साहब, हम अपनी बात रखना चाहते हैं। (विघ्न एवं शोर)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, ये लोग इस विषय पर बोलना नहीं चाहते हैं। (विघन एवं शोर) हर बार ये लोग कॉलिंग अटैंशन नोटिस तो दे देते हैं लेकिन ये कभी उस पर बोलते नहीं हैं। ये सिर्फ हाउस का समय खराब करने के लिए आते हैं। (विघन एवं शोर)

(इस समय इण्डियन नेशनल लोकल के हाउस में उपस्थित सभी माननीय सदस्य वैल के निकट आकर बोलने लगे)

Mr. Speaker: Please take your seats. Mr. Indora,

you are speaking irrelevant. Dr. Sita Ram, please read your calling attention motion. (Interruptions) Please take your seats. (Interruptions) **I** warn you Dr. Indora. Nothing is to be recorded. (Interruptions)

Dr. Sushil Indora: Speaker Sir, *** *** ***

Mr. Speaker: Dr. Indora, I warn you. Please take your seat. (Interrutpions) Dr. Indora, I warn you. (Interruptions) Nothing is to be recorded.

Dr. Sushil Indora: Speaker Sir, *** **** ****

Mr. Speaker: Dr. Indora, I warn you. (Interruptions) I name Dr. Sushil Indora. He may leave the House.

(At this stage, Dr. Sushil Indora withdrew from the House)

Mr. Speaker: Please take your seats. (Noise and Interruptions). I will allow you to speak. Please go to your seats. (Noise and Interruptions) Nothing is to be recorded.

श्री रामफल चिड़ाना: अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं

Mr. Speaker: I warn you, Mr. Ram Phal Chirana. (Interruptions)

श्री रामफल चिडाना: अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं

Shri Randeep Singh Surjewala: Speaker Sir, is it

the conduct of the I Hon'ble Member in the House ? (Noise and Interruptions).

श्री रामफल चिढ़ाना: अध्यक्ष महोदय,

Mr. Speaker: I again warn you, Mr. Ram Phal Chirana. (Interruptions), Chirana ji, please go to your seat, otherwise, I will have to name you.

श्री रामफल चिडाना: अध्यक्ष महोदय,

Mr. Speaker: I name Shri Ram Phal Chirana. He may please leave the House. (Noise and Interruptions).

(At this stage Shri Ram Phal Chirana, MLA withdrew from the House)

श्री ईश्वर सिंह पलाका: अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं ....

Mr. Speaker: I warn you, Mr. Ishwar Singh Palaka. (Interruptions).

श्री ईश्वर सिंह पलाका: अध्यक्ष महोदय, ...

Mr. Speaker: I again warn you, Mr. Ishwar Singh Palaka. Please go to your seat. (Interruptions). Palaka ji, please go to your seat, otherwise, I will have to name you.

श्री ईश्वर सिंह पलाका: अध्यक्ष महोदय, ...

Mr. Speaker: I name Shri Ishwar Singh Palaka. He may please leave the House. (Interruptions).

(At this stage Shri Ishwar Singh Palaka, MLA withdrew from the House)

Mr. Speaker: Please take your seats. (Interruptions)

श्री बलवन्त सिंह सढौरा: अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं ....

Mr. Speaker: I warn you, Mr. Balwant Singh Sadhaura. Please go to your seat. (Noise and Interruptions).

श्री बलवन्त सिंह सढौरा: अध्यक्ष महोदय, ...

Mr. Speaker: I again warn you, Mr. Sadhaura. (Noise and Interruptions). Mr. Sadhaura ji, please go to your seat, otherwise, I will have to name you. (Noise and interruptions).

श्री बलवन्त सिंह सढौरा: अध्यक्ष महोदय, ...

Mr. Speaker: I name **Shri** Balwant Singh Sadhaura. He may please leave the House. (Interruptions).

(At this stage Shri Balwant Singh Sadhaura, MLA withdrew from the House).

Mr. Speaker: Please take your seats. Nothing is to be recorded (Interruptions)

श्री साहिदा खान: अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं .. ..

Mr. Speaker: I warn you, Mr. Sahida Khan. Please

go to your seat. (Noise and Interruptions).

श्री साहिदा खान: अध्यक्ष महोदय, ...

Mr. Speaker I again warn you, Mr. Sahida Khan (Noise and Interruptions). Mr. Sahida Khan ji, please go to your seat, otherwise, I will have to name you. (Noise and interruptions).

श्री साहिदा खान: अध्यक्ष महोदय, ...

Mr. Speaker: I name Shri Sahida Khan. he may please leave the House. (Interruptions)

(At this stage Shri Sahida Khan, MLA withdrew from the House). Dr. Sita Ram: Speaker Sir, *****

Mr. Speaker: Sita Ram ji, it is not a matter of zero hour. In the zero hour you can raise the issue of public importance. (Noise and interruptions).

Dr. Sita Ram: Speaker Sir, ****

Mr. Speaker: What is the importance of your topic? (Noise and interruptions). It is not pertaining to the zero hour. You please go to your seat. I allow you to speak. You may read your calling attention motion. (Noise and interruptions).

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, ये इस तरह से सदन की वैल में आकर कमैंट्री नहीं दे सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान) आप इनको इनकी सीटों पर जाने के लिए कहें। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता रामः आप हमें इन्स्ट्रक्शन नहीं दे सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः डॉ० सीता राम जी, आपका कालिंग अटैंशन नोटिस है, वह आज के लिए एडमिट हो गया है। अब आप अपनी सीट पर जाकर अपना नोटिस पढ़ें। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता रामः अध्यक्ष महोदय, हमारे बाकी साथियों का नाम भी इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में हैं। आपने उनको सदन से नेम कर दिया है आप उनको सदन मे वापिस बुला लें ताकि वे भी इस बारे में सदन में चर्चा कर सकें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः डॉ० साहब, आप अपनी सीट पर जाकर अपना नोटिस पढें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, ये सदन की वैल में आकर लगातार टीका—टिप्पणी नहीं कर सकते हें। इनको अपनी सीटों पर जाकर बोलना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) आप इन्हें कहें कि ये अपनी सीटों से बोलें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चन्दः अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। इसलिए मैं सदन से वाक—आऊट करता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय इंडियन नेशनल लोक दल के सदस्य थी धान बन्द सदन से वाक कर गए।)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–

(1) मॉनसून ऋतु में हरियाणा राज्य में मलेरिया, डेंगू वायरल बुखार के यह रहे मामलों संबधी

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received a Calling Attention Notice from Dr. Sita Ram and five other MLAs regarding increasing cases of Malaria, Dengue, Viral Fever in the State of Haryana in this Monsoon Season. I admit it. Dr. Sita Ram may read out his notice. (interruptions) The Hon'ble Members have given the Calling Attention Motion and it is pertaining to the health of the State. It has been accepted. Dr. Sita Ram, you may read out your notice. (interrutptions)

श्री अध्यक्ष: आप सभी अपनी सीटों पर जाएं। (शोर एवं व्यवधान) डॉक्टर साहब, आप अपना नोटिस पढ़ें। (शोर एवं व्यवधान)

@ **डा० सीता राम:** अध्यक्ष महोदय, इस सूचना में मेरा नाम है और मेरे साथ–साथ डॉ० सुशील इन्दौरा जी, रामफल चिड़ाना, बलवन्त सिंह सढौरा, साहिदा खान तथा ज्ञान चन्द जी का नाम भी शामिल है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। मेरा निवेदन है कि आप उनको भी सदन में वापिस बुला लें।

श्री अध्यक्ष: सीता राम जी, पहले आप अपना नोटिस पढ़ें।

डॉ० सीता रामः ठीक है सर, मैं अपना नोटिस पड़ता हूं—

''अध्यक्ष महोदय, मैं इस सूचना के माध्यम से इस महान सदन का ध्यान हरियाणा राज्य में इस मानसून ऋतु में मलेरिया, डेंगू, वॉयरल बुखार इत्यादि के बढ़ रहे मामले संबंधी एक अत्यन्त लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। राज्य में बहुत अधिक संख्या में इन मामलों का पता चला है तथा इनसे मौतें भी हुई हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि०पर वर्णित बीमारियों के होने को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा क्या पग उठाए गए हैं? इसके साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि यह बीमारी किस कारण से बढ़ रही है और किस कारण स्वास्थ्य विभाग इसको रोक सकने में सक्षम नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं सरकार से सदन के पटल पर एक वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं ताकि हरियाणा राज्य की जनता के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके। ''

वक्तव्य—

उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी स्वास्थ्य मंत्री द्वारा—

स्वास्थ्य मंत्री (वहन करतार देवी): अध्यक्ष महोदय, हरियाणा राज्य में मलेरिया हमेशा से ही जन स्वास्थ्य समस्या रहा है। यह रोग एक चक्र के अनुसार घटता बढ़ता है। वर्ष 1976 में राज्य मे 7.36 लाख मलेरिया के केसिज दर्ज किये गये। भारत सरकार के मार्गदर्शनानुसार मलेरिया के नियंत्रण हेतु एक संशोधित

योजना (मोडीफाईड प्लान ऑफ औपरेशन) को वर्ष 1977 में लागू किया गया। इसके परिणामस्वरूप मलेरिया केसिज में निरन्तर कमी आई, यद्यपि वर्ष 1993 के उपरान्त मलेरिया के केसिज में फिर से बढ़ोतरी शुरू हुई और वर्ष 1996 में राज्य में 128 लाख केसिज मलेरिया के पाए गए। वर्ष 1997 से 2002 तक मलेरिया के केसिज में फिर से कमी आई, परन्तु वर्ष 2003 एवं 2004 से मलेरिया केसिज फिर से बढ़ने शुरू हो गये और वर्ष 2006 में काफी बढोतरी आई। राज्य में पहली बार वर्ष 1996 में डेंगू का प्रकोप हुआ था, जिसके कारण 1642 केस रिपोर्ट हुए और 54 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। तब से ही विभिन्न क्षेत्रों में डेगू के केस होते रहे हैं। वर्ष 2007 में राज्य में डेगूं के 566 कन्फमर्ड केस हुए थे। इस वर्ष दिनांक 01.09.2009 तक डेन्गू के 397 केसिज हो चुके हैं जिनमें से 320 केस गुड़गांव से ही हैं।

वर्षवार हरियाणा राज्य में मलेरिया डेन्गू चिकुनगुनिया व जे०ई० के केसिज की स्थिति निम्न प्रकार से हैं:

बीमारी का नाम		वर्ष			
		2005	2006	2007	2008 (1.9.2008 तक)
मलेरिया	केसिज	33,204	47,077	30,895	24,343

	डैथ	0	0	0	0
पी०एफ० मलेरिया	केसिज	244	507	326	348
	डैथ	I	0	0 I	1 बाहरी व्यक्ति
डेन्गू/डी० एच० एफ०	केसिज	183	838	365	397
	डैथ	1	4	11	4
चिकुनगुनिया	केसिज	0	13	13	1
	डैथ	0	0	0	0
जे०ई०	केसिज	4	3	32	0
	डैथ	2	1	18	

इस वर्ष का अब तक का जिलावार ब्यौरा पताका 'क' पर है।

इस वर्ष समय से पहले व भारी वर्षा हुई जिसकी वजह से बहुत जगहों पर पानी इकट्ठा हो गया। खड़े पानी एवं गन्दगी का सम्मिश्रण मच्छरों को पैदा करता है, जिससे मलेरिया में

बढ़ोतरी होती है। डेगूं का मच्छर साफ खड़े पानी में पैदा होता है। इसके मुख्य स्रोत भवन निर्माण स्थल, घरों में रखे गये कूलर, फूलदान, खुले बर्तन, छतों पर रखी बिना ढक्कन की टंकियां एवं खुले में रखा कबाड इत्यादि हैं जिसके कारण मच्छर पैदा होते हैं। मलेरिया की रोकथाम हेतु एक्सन खान भारत सरकार की नीति के अनुसार दृढ़ता से लागू किया जा रहा है। मलेरिया की रोकथाम हेतु निम्नलिखित गतिविधियां चलाई जा रही हैः –

–जनवरी, 2008 से अगस्त 2008 तक 14.01 लाख ज्वर रोगियों की रक्त पट्टिकायें (Blood Slides) बनाकर उनका राज्य की स्वास्थ्य संस्थाओं में रक्त पट्टिकाओं की जांच के लिए स्थापित 482 मलेरिया क्लीनिकों में जांच करवाई गई और गोलियां स्थापित हैं और मलेरिया पोजीटिव पाये जाने पर उन्हें चिकित्सा दी गई है।

– राज्य में प्रेरित व निष्ठावान ग्राम पंचायतों/अध्यापकों/आंगनवाडी वर्करों इत्यादि के पास ज्वर उपचार केन्द्र खोले गये हैं, जहां पर ज्वर रोगियों को मुफ्त में क्लोरोक्वहन की गोलियां दी जाती हैं।

– जिन क्षेत्रों में मलेरिया के अधिक केस पाये जा रहे हैं, वहां पर चिकित्सा अधिकारी एवं पैरामैडीकल की टीम नियमित तौर पर दौरा कर रही है और फीवर मास सर्वे एवं फौगिंग की जा रही है।

– जनता को स्वास्थ्य शिक्षा दी जा रही है और मलेरिया रोग तथा इसकी रोकथाम के तरीके भी बताये जा रहे हैं।

– स्वास्थ्य विभाग ने शहरी निकाय, जन स्वास्थ्य विभाग व हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से अनुरोध किया है कि सभी बस्तियों में स्वच्छ पेयजल तथा शौचालय आदि की सुविधा उपलब्ध करवाये।

– प्रभावित क्षेत्रों में जे का कार्य आरम्भ किया जा चुका है।

डेन्गू ग्रस्त क्षेत्रों में क्यो नियंत्रण हेतु निम्न आवश्यक उपाए किये जा रहे हैं –

– बुखार के सभी केसों, जिनमें को जैसे लक्षण पाये जाते हैं, की निगरानी की जा रही है।

– डेन्गू सम्भावित क्षेत्रों में घरों में डेन्गू मच्छरों के लारवा की चौकिंग की जा रही है तथा लोगों को जानकारी दी जा रही है कि वे सप्ताह में एक बार अपने घर के सभी पानी से भरे बर्तनों को खाली करें या उन्हें ढक कर रखें।

– जहां पर यह सम्भव न हो, वहां पर उन्हें लारवा को मारने के लिए पानी में एक चम्मच मिट्टी का तेल या पैट्रोल डालने का सुझाव दिया जा रहा है।

– क्यो प्रभावित क्षेत्रों में मैलाथीन फोगिंग की जा रही है।

– जन संचार गतिविधियों को और सघन किया गया है। मुद्रण और इलैक्ट्रोनिक माध्यमों से आम जनता में जागृति पैदा की जा रही है।

राज्य मुख्यालय से जिला/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक बीमारी की स्थिति का प्रतिदिन अवलोकन किया जा रहा है।

भारत सरकार द्वारा गुड़गांवा में डेन्गू की स्थिति की दो बार समीक्षा की जा चुकी है, जिसमें उन्होंने राज्य के स्वास्थ्य विभाग सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर संतुष्टि की एक महत्वपूर्ण बैठक भी आयोजित की गई है, जिसमें पी०जी०आई० चण्डीगढ़, पी०जी०आई० रोहतक के विशेषज्ञ, एण्टोमोलोजी विशेषज्ञ व प्रभावित क्षेत्रों के सिविल सर्जन, जिला मलेरिया अधिकारियों तथा जीव वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में यह निष्कर्ष निकला कि मलेरिया व क्लो बढ़ने का मूल कारण सफाई का अभाव व मच्छर फैलाने वाले हालात हैं। इस बैठक में इस बात की भी सिफारिश की गई कि मलेरिया व डेन्गू की रोकथाम हेतु बाहरी फौगिंग का कोई लाभ नहीं है। अगर आवश्यकता हो तो घरों के अन्दर फौगिग करवाई जा सकती है। इस बात पर भी जोर दिया गया कि मच्छरों से होने वाली

बीमारियों पर नियंत्रण हेतु जन साधारण व स्कूल/कालेजों के बच्चों की सहायता लेना आवश्यक है।

विभाग द्वारा पहले ही इन हिदायतों के अनुसार कार्य किया जा रहा है। सभी सिविल सर्जनों को जन साधारण, साक्षर महिला समूह, आशा कार्यकता व स्कूली बच्चों की सहायता लेने हेतु निर्देश दिये जा चुके हैं। राज्य के सभी शहरों व ग्रामीण क्षेत्रों में फौगिंग करवाई जा रही है। सभी सिविल सर्जन को पंचों/सरपंचों व नगरपालिका के कौन्सिलरस का सहयोग लेने हेतु कहा गया है। सभी जिलों को कीटनाशक दवाई की खरीद व वैक्टर जनित रोगों के नियंत्रण हेतु गतिविधियों के लिए अतिरिक्त बजट दे दिया गया है। उनको अपने क्षेत्र में पानी की उचित निकासी व स्वच्छता बनाये रखने हेतु हिदायतें जारी कर दी गई हैं, ताकि पानी इक्ट्ठा न हो और मच्छरों को पनपने से रोका जा सके।

Annexure-A

Daily Report of Vector Borne Diseases (Malaria, Dengue) upto 01-09-2008

Name of the State: Haryana

No. of Districts: 20

Malaria

Sr.	District	Date of	No.	cases	Progressi	Total	

					ve		
No.		report	Total	Pf	Total	Pf	No. Death
1.	Ambala	01-09-2008	4	0	26	1	0
2.	Bhiwani	01-09-2008	69	0	1654	4	0
3.	Faridabad	01-09-2008	0	0	23	1	0
4.	Fatehabad	01-09-2008	11	0	2007	2	0
5.	Gurgaon	01-09-2008	0	0	73	7	0
6.	Hisar	01-09-2008	216	0	5116	4	0
7.	Jhajjar	01-09-2008	0	0	386	1	0
8.	Jind	31-08-2008	0	0	4867	3	0
9.	Kaithal	01-09-2008	70	0	1410	0	0
10.	Karnal	31-08-2008	0	0	4411	292	0
11.	Kurukshetra	01-09-2008	7	1	147	3	0
12.	Mewat	01-09-2008	93	0	377	1	0
13.	Namaul	31-08-2008	0	0	121	0	0
14.	Panchkula	01-09-2008	2		62	2	0
15.	Pan ipat	01-09-2008	11	2	702	10	0
16.	Rewari	31-0-2008	0	0	100	0	0

17.	Rohtak	01-09-2008	30	0	763	1	0
18.	Sirsa	01-09-2008	11	0	975	1	0
19.	Sonepat	31-08-2008	0	0	676	3	0
20.	Yamunanagar	01-09-2008	9	0	447	12	0
			0	0			0
	Total		533	3	24343	348	0

	Pv	Pf	Total
30-09-2007	27733	201	27934
01-09-2008	23995	348	24343

Dengue

Sr.	District	Cases Reported				Progressive Total			
No.		Total Susp. Cases	No. death	No. Conf. Cases	No. Death	Total Susp. Cases	No. Death	No. Conf. Cases	No. Death
1.	Ambala	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Bhiwani	0	0	0	0	8	1	4	0
3.	Faridabad	0	0	0	0	59	0	7	0
4.	Fatehabad	0	0	0	0	93	0	9	0

5.	Gurgaon	88	0	0	0	565	2	320	2
6.	Hisar	5	0	0	0	19	0	4	0
7.	Jhajjar	0	0	0	0	4	1	1	0
8.	Jind	0	0	0	0	6	0	0	0
9.	Kaithal	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Karnal	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Kurukshetra	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Mewat	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Narnaul	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Panchkula	0	0	0	0	3	0	3	0
15.	Panipat	15	0	0	0	102	0	28	0
16.	Rewari	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Rohtak	0	0	0	0	16	I	16	1
18.	Sirsa	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Sonepat	0	0	0	0	6	1	3	1
20.	Yamunanagar	0	0	0	0	3	I	2	0
		0	0	0	0				

	Total	108	0	0	0	884	7	397	4

Dengue Conf.	Cases	Death
30-09-2007	164	7
01-09-2008	397	4

Japanese Encephalitis

Sr.	District	Cases Reported				Progressive Total			
No.		Total Susp.. Cases	No. death	No. Conf. Cases	No. Death	Total Susp. Cases	No. Death	No. Conf. Cases	No. Death
1.	Ambala	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Bhiwani	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Faridabad	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Fatehabad	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Gurgaon	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Hisar	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Jhajjar	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Jind	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Kaithal	0	0	0	0	0	0	0	0

10.	Karnal	0	0	0	0	0	0	0	0
11 .	Kurukshetra	0	0	0	0	2	I	0	0
12.	Mewat	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Narnaul	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Panchkula	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Panipat	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Rewari	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Rohtak	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Sirsa	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Sonepat	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Yamunanagar	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	0	0	0	0	2	1	0	0

Chikungunya

Sr.	District		Cases Reported					Progressive	Total
No.		Total Susp. Cases	No. death	No. Conf. Cases	No. Death	Total Susp. Cases	No. Death	No. Conf. Cases	No. Death
1.	Ambala	0	0	0	0	0	0	0	0

2.	Bhiwani	0	0	0	0	10	0	0	0
3.	Faridabad	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Fatehabad	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Gurgaon	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Hisar	0	0	0	0	3	0	0	0
7.	Jhajjar	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Jind	0	0	0	0	6	0	0	0
9.	Kaithal	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Karnal	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Kurukshetra	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Mewat	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Narnaul	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Panchkula	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Panipat	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Rewari	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Rohtak	0	0	0	0	1	0	1	0
18.	Sirsa	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Sonepat	0	0	0	0	0	0	0	0

20.	Yamunanagar	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	0	0	0	0	20	0	1	0

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहती हूं कि इस वर्ष दिनांक 1.9.2008 तक 397 केसिज डेंगू के पाये गये थे जिनमें से 520 केसिज तो गुड़गांव से ही थे उनमें से 4 केसिज में डैथ्स हुई हैं फिर भी हमारा प्रयास है कि इस स्थिति को जल्द से जल्द सुधारें। मैं अपने विपक्ष के साथियों से अनुरोध करूंगी कि चाहे शिक्षा का मामला हो या स्वास्थ्य का मामला हो, यह मामले पार्टियों में नहीं बंटा करते। इसमें तो हमें आप सबका सहयोग चाहिए। आप पड़े लिखे हैं, आप डॉक्टर भी हैं, आप लोगों को समझाएं कि अपने घर में जो कूलर हैं उनको ये नहीं कि एक बार भर लिया और चलते रहे। उस कूलर को सप्ताह में एक बार खाली करें और उनको साफ करें। घर में भी सफाई होनी चाहिए। फोगिंग की जहां जरूरत हो वहां फौगिग होनी चाहिए। यह हिदायतें दी हुई हैं कि जहां से भी इस प्रकार की कोई डिमांड आती है वहां तुरन्त पहुंचे। मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहूंगी कि यहां आलोचना करने से काम नहीं चलता। हमने आपके डबवाली के अस्पताल का दर्जा 100 बैड का कर दिया है और वहा बहुत जल्द और सुविधायें भी दे दी जाएंगी, जो थोड़ी बहुत कमी है उसको भी दूर कर दिया जाएगा। हम यह नहीं सोचते हैं कि किसका हल्का है। मुख्यमंत्री जी की यह सोच है कि चाहे सिरसा हो या रोहतक हो,

शिक्षा का मामला हो या स्वास्थ्य का मामला हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं करना है। हमने आपके यहां लड़कियों के लिए कालेज खोला है। यह जो मलेरिया फैलता है यह अपनी–गलियों से फैलता है। इसके अलावा जो जापानी बुखार होता है उससे बचाव के लिए टीके लगाने की शुरूआत पिछली बार हमने कुरुक्षेत्र से की थी और इस बार अम्बाला से की है। एक बार टीका लग जाने से बच्चे एक साल तक इस बीमारी से बचे रहते हैं। हमारे लिए एक खुशी की बात है कि चिकनगुनिया की बीमारी हमारी स्टेट में नहीं है, इससे हम बचे हुए हैं। एक केस मिला है वह भी बाहर से आया है उसकी भी डैथ नहीं हुई है वह बच गया है। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहूंगी कि हैल्थ का कार्य केवल डाक्टरों के सहयोग से नहीं चलता, उसके लिए हमें सारी जनता का सहयोग चाहिए, आप लोगों का भी सहयोग चाहिए। जितनी आप साथियों को इस बारे में चिंता है उससे कहीं ज्यादा चिंता हमारी है। ये जो चार डैथ्स हुई हैं इनका भी हमें मलाल है। आप बैठकर कभी यह सोचा करें कि आपने 412 एम०पी०एच०डब्ल्यू० की पोस्ट्स खत्म कर भी और जितनी ट्रेंड दाई थी वे पोस्टें भी आपने खत्म कर दी थी। अब यहां आप शोर मचा रहे हैं।

Mr. Speaker: So far as diseases of dengue and malaria are concerned, precautionary measures should be taken before the rainy season.

डा० सीता राम: बहिन जी, आप हमारे को कहने लग गये आप उन बातों की तरफ ध्यान दीजिए, जिनकी तरफ ध्यान देना जरूरी है। मलेरिया यह नहीं देखता कि यह विपक्ष का है या सस्ता पक्ष का है, वह किसी को भी एफैक्ट करेगा।

श्री अध्यक्ष: डाक्टर साहब, स्वास्थ्य और शिक्षा को बांटा नहीं जा सकता।

डा० सीता राम: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री महोदया को कहना चाहता हूं कि मलेरिया के केसिज बहुत ज्यादा हैं। हकीकत तो यह है कि सभी हॉस्पिटल्ज में जो डॉक्टर और एम०पी०एच०डब्ल्यू० हैं, जो मलेरिया को टैस्ट करते हैं, वे कम से कम स्लाईड को और पोजीटिव केसिज को कागजों में निकालते हैं। हकीकत तो यह है कि मलेरिया के केसिज बहुत ज्यादा हो रहे हैं। हम गांवों में जाते है तो वहां जिस आदमी को बुखार आता है अगर उसको हम कहते हैं कि मलेरिया टैस्ट कराओ तो वह कहता है कि मलेरिया बताया है। गांवों में ज्यादातर आर०एम०पी० डॉक्टर्ज होते हैं जिनसे आम आदमी इलाज करवाते हैं। लेकिन सरकार रिकार्ड में बहुत कम फिग्गर्ज दिखा रही है।

Mr. Speaker: Please ask only relevant question.

डॉ० सीता राम: अध्यक्ष महोदय, बहुत ज्यादा केसिज हो रहे हैं। लेकिन माननीय मंत्री महोदया हमारे०पर रिसपौन्सिब्लिटी

डाल रही हैं कि आप लोगों ने यह किया है। आप अपना काम कीजिए। हमें जब भी मौका मिलता है हम लोगों को बताते हैं कि स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखो। जब अखबारों में मलेरिया के बारे में कोई खबर आती है तो प्रशासन में हलचल होती है और तब सरकार को इसके बारे में पता चलता है। जब भी रैनी सीजन आने वाला होता है तब भी आप प्री-क्योशन मईयर्ज क्यों नहीं उठाते।

श्री अध्यक्षः आप सवाल पूछिये। Ask only specific question.

बहिन करतार देवीः अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी बात का जवाब दे देती हूं। डॉ० साहब, रैनी सीजन आने से पहले विभाग द्वारा मलेरिया संबंधी पोस्टर छपवाये जाते हैं। विभाग के सभी डिस्ट्रिक्ट मलेरिया आफिसर्ज और एम०पी०एच० डब्ल्यू को हिदायत दे दी जाती हैं। इनका काम गांवों में मलेरिया संबंधी स्लाईड बनाने का होता हे। इस बारे में इन सब की मीटिंग ली जाती है। इनको हिदायत दी जाती हैं कि ये जल्दी से जल्दी स्लाईड बनायें। सरकार की तरफ से कोई कोताही नहीं बरती जाती है लेकिन फिर भी मैं समझती हूं कि कहीं न कहीं कमी रह ही जाती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जनता के घरों में कूलर लगे हुए हैं जिनके अन्दर पानी होता है वहां पर मच्छर पैदा हो जाते हैं। अब सरकार ने फैसला लिया है कि सभी घरों के अन्दर मैलाथीन फोगिंग करवाई जायेगी। पहले यह घरों के बाहर ह्वीं करवाई जाती थी।

डॉ० सीता राम: अध्यक्ष महोदय, इसका सबसे बड़ा कारण है सफाई व्यवस्था का न होना। जो मलिन बस्तियां हैं और गांवों के अन्दर जो नालियां हैं उनकी सफाई ठीक ढंग से नहीं होती और उनमें गन्दा पानी खड़ा रहता है। बरसात के सीजन में वह और ज्यादा बढ़ जाता है। अगर इन चीजों की पहले से ही सफाई करवा ली जाए और प्रोपर सैनीटेशन ड्राईव चलाया जाए तो इस पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली इस प्रकार का काम नहीं किया जाता और सिर्फ कागजों में ही सफाई हो जाती है जिसकी वजह से बीमारियां फैलती हैं और बढ़ती हैं। इस तरफ ध्यान देने का कष्ट करें।

बहिन करतार देवी: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगी कि सफाई की तरफ ध्यान देने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने गांवों की आबादी को देखते हुए 11 हजार सफाई कर्मचारी लगाए हैं ताकि वे गावों में सफाई का काम कर सकें।

डॉ० सीता राम: अध्यक्ष महोदय, अगर ये सफाई कर्मचारी हकीकत में काम कर रहे होते तो ये बीमारियां न फैलती। अगर स्वास्थ्य विभाग जागरूक होता तो ये बीमारियां न फैलती। मैं मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट नहीं हूं।

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, जो 11 हजार दलित सफाई कर्मचारी लगाए गए हैं ये उन

कर्मचारियों पर ही इल्जाम लगा रहे हैं, जोकि बहुत गलत बात है। 11 हजार कर्मचारियों को जो रोजगार दिया है ये उनकी नियत पर, उनकी मेहनत पर और उनके चरित्र पर इल्जाम लगा रहे हैं। इनको इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

वाक आऊट

डॉ० सीता राम: अध्यक्ष महोदय, हमारे साथियों के साथ नाइंसाफी की गई है। हमारे साथियों के साथ तानाशाही की गई हे। मेरा कालिंग अटैंशन मोशन था इसलिए मैं यहां रुका हुआ था और मैं जानना चाहता था कि स्वास्थ्यः विभाग क्या कर रहा है। हरियाणा की सरकार लोगों के स्वास्थ्य को ठीक करने में सक्षम नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आपने हमारे साथियों के साथ संवैधानिक तरीके से व्यवहार नहीं किया। मेरे कालिंग अटैंशन नोटिस का मंत्री जी ने जवाब दिया है मैं उससे भी संतुष्ट नहीं हूं इसलिए एज ए प्रोटैस्ट मैं सदन से वाक–आऊट करता हूं।

(इस समय इंडियन नेशनल लोकल के सदस्य डॉ० सीता राम एज ए प्रोटैस्ट सदन से वाक कर गए।)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–

(2) नैनो कार परियोजना को पश्चिमी बंगाल से स्थानांतरित करके हरियाणा राज्य में भूमि उपलब्ध करवाने सम्बन्धी

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received a Calling Attention Notice from Shri Karan Singh Dalal, MLA

regarding shifting of Nano Car Project from West Bangal and providing land in the State of Haryana. I admit it. Shri Karan Singh Data] may read his notice.

Shri Ka ran Singh Dalal: Speaker Sir, **I** want to draw the kind attention of this august House towards a matter of public importance that after the break down of Nano Car Project in West Bangal and declaration of TATA to shift the project elsewhere, I request the Government that the land can be made available in the State of Haryana and the Government should give an offer to TATA so that this project is drawn in the State of Haryana. On account of it, new opportunities will be created for the development of the State. I therefore, request the Government to make a statement in this august House.

वक्तव्य–

उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबधी मुख्यमंत्री द्वारा

Mr. Speaker: Now the Chief Minister will make a statement on the Calling Attention Notice put forth by Shri Karan Singh Dalal.

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): अध्यक्ष महोदय हमारे साथी कर्ण सिंह दलाल जी ने एक कालिंग अटैंशन मोशन दी है। यह मसला कई दिनों से चल रहा था। टाटा कम्पनी ने नैनो कार वैस्ट बंगाल में बनाने का फैसला किया था। नैनो कार बहुत सस्ती गाड़ी है। इसका इंतजार देश के ही नहीं बल्कि विदेशों के लोग भी बेचौनी से कर रहे थे। इस गाड़ी को जब दिल्ली में इंट्रोड्यूस

किया गया था उस समय मैं भी दिल्ली में गया था और मैंने उस गाड़ी में बैठकर देखा था। कीमत के हिसाब से गाड़ी बहुत अच्छी है। लोगों को उम्मीद है कि उनको जल्दी ही सस्ती गाड़ी मिलेगी। इसमें तेल का खर्चा भी कम होगा लेकिन आज जैसा आप सबने अखबारों में पढा है कि टाटा कम्पनी के चेयरमैन मिस्टर रतन टाटा ने कहा है कि वे सिंगर में नैनो कार का खाट नहीं रखेंगे. कहीं और इस प्लांट को शिफ्ट करेंगे। उन्होंने कहा है कि वे अक्मा प्लांट उस प्रदेश में ले जायेंगे जहां शांतिप्रिय इलाका हो और किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। अध्यक्ष महोदय, इस संदर्भ में जो बात कही गई है उस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक हरियाणा की बात है, हरियाणा 1966 में बना था और 1966 से लेकर जब हमारी सरकार बनी उससे पहले 40 साल तक 40 हजार करोड़ रुपये का निवेश हुआ था। उसके बाद सवा तीन साल पहले हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। अध्यक्ष महोदय, हमारी एक नीति है जिसके तहत हम एक नई इण्डस्ट्रीयल पॉलिसी लेकर आये हैं। हरियाणा प्रदेश पहला प्रदेश है जो नई लेबर कालक लेकर आया और मिनिमम वेजिज एक्ट के अनुसार मिनिमम वेजिज पूरे देश में सबसे ज्यादा हमारे प्रदेश में दिए जाते हैं। इस प्रकार हमने प्रदेश में एक माहौल बनाया है। जिसको इन्वैस्टमैंट फैंडली माहौल कहते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम नई उद्योग नीति लेकर आये हैं ताकि हमारे प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगें और लोगों को रोजगार मिले क्योंकि जमीन तो बढ़ नहीं सकती। अगर दादा के पास दस एकड़ जमीन थी तो पोते के पास तो

आधा एकड़ जमीन ही बचती है और अकेली जमीन से गुजारा नहीं हो सकता। न ही सबको सरकारी नौकरियां मिल सकती हैं। जितनी नौकरियां होती हैं उतने लोगों को रोजगार दिया जाता है। लैकिन आने वाली पीढ़ी को रोंजगार कैसे मिलेगा इस बात को ध्यान में रखते हुए ही हम नई उद्योग नीति लेकर आये हैं ताकि हरियाणा में ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। अध्यक्ष महोदय, आपको यह जानकर खुशी होगी कि जितनी कारें पूरे हिन्दुस्तान में बनती हैं उसकी 5० प्रतिशत कारें केवल हरियाणा प्रदेश में बनती हैं। इसी प्रकार से साईकिल, मोटरसाईकिल, ट्रैक्टर, रैफीजरेटर और जे०सी०बी० आदि में हमारा मेजर शेयर है जिसके कारण हमारे प्रदेश के बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है। इसके अलावा हम एस०सी०जैड० भी लगा रहे हैं। एक–एक एस०सी०जैड० में लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, आपको जानकर खुशी होगी कि 40 साल के दौरान 40 हजार करोड़ रुपये की इनवैस्टमैंट हुई और हमारी सरकार के सवा तीन साल के कार्यकाल के दौरान 40 हजार करोड़ रुपये के उद्योग लग चुके हैं और 9० हजार करोड़ रुपये की इनवैस्टमैंट पाईप लाईन में है। इसमें हम दो लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य लेकर चले हैं ताकि 20 लाख लोगों को रोजगार मिल सके। अध्यक्ष महोदय, आज प्रश्नकाल के दौरान आई०टी०आईज० के बारे में प्रश्न चल रहा था। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि पहले हमारे प्रदेश में इंजीनियरिंग कालेजिज में, आई०टी०आईज० में और पॉलिटैकनीक्स

में कुल 23–24 हजार सीट्स थी जो हमने बढ़ाकर 1,30,000 सीट्स कर दी हैं ताकि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके। अध्यक्ष महोदय, यदि कोई इस प्रकार की मदर यूनिट प्रदेश में आती है जिस प्रकार की मारुति का मदर यूनिट बुआई थी, हम उसके लिए तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, आपको जानकर खुशी होगी कि जब मैं डैलीगेशन लेकर जापान गया था उस समय मारुति के चेयरमैन मिस्टर ओ० सूजूकी से मिला था। उन्होंने 30–40 वैंडर्ज बुला रखे थे जिनके साथ हमारी मीटिंग रखी थी। उस मीटिंग में मारुति के चेयरमैन ने कहा था कि यदि मैं इण्डिया में एक पाई की भी इनवैस्टमैंट करूंगा तो वह हरियाणा में करूंगा, हरियाणा से बाहर नहीं करूंगा (इस समय मेजें थपथपाई गई)। इस प्रकार का माहौल हमारी सरकार ने प्रदेश में पैदा किया है और यही कारण है कि बहुत सी कंपनियां हरियाणा में अपनी यूनिट लगाना चाहती हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त हमारी सरकार री–हैबिलिटेशन पॉलिसी लेकर आई है जिसमें किसानों का विशेष ध्यान रख गया है और किसानों के लिए अन्यूटी फिक्स की है। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से मारुति की मदर यूनिट आई, उसके बाद बहुत सारी यूनिट्स आई। उसका नतीजा यह हुआ कि हरियाणा प्रदेश ऑटो मोबाइल कम्पोनैंट्स का हब बन गया है। अगर टाटा कंपनी वाले यह फैसला करें कि वे हरियाणा में अपना मदर यूनिट लेकर आयेंगे तो हरियाणा सरकार और हरियाणा के लोग उनका स्वागत करेंगे। यदि किसी कंपनी की मदर यूनिट हमारे प्रदेश में आती है तो हम उसको यहां पूरी सुविधाएं मुहैया

करवायेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि एक मदर यूनिट आने से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है इसलिए यदि टाटा वाले अपनी मदर यूनिट हमारे' यहां लगायेंगे तो हम उनका पूरा सहयोग करेंगे और स्वागत करेंगे।

श्री कर्ण सिंह दलालः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो तमाम हरियाणा कै फैक्ट्स दिए हैं यह बिल्कुल दुरूस्त बात है कि जब से हमारे मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने हरियाणा की कमान सम्भाली है, हरियाणा के अन्दर एक नया आत्मविश्वास दिखाई देने लगा है। उधोगपति पिछले शासन में श्री ओम प्रकाश चौटाला के डर के मारे हरियाणा में स्थापित 'अपनी 'अदद इकाईयों को हरियाणा से उठाकर दूसरे प्रदेशों में ले जाने के लिए विवश हो गये थे। उस समय हरियाणा का औद्योगिक माहौल पूरी तरह से बिगड़ने लगा था। यहां पर भय और डर का माहौल दिखाई देने लगा था उसके कारण पूरा हरियाणा प्रदेश हरेक मामले में पीछे की तरफ खिसकने लगा था। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से प्रदेश का संचालन किया उससे उद्योगपतियों को विकास के रास्ते पर 'अग्रसर होने के लिए एक नया संदेश और प्रोत्साहन मिला। हरियाणा प्रदेश के अन्दर सबसे पहले मिनिमम वेजिज एक्ट लागू किया गया जिससे हरियाणा पूरे देश में मिनिमम वेजिज देने वाला पहला राज्य बन गया। यह दिहाड़ीदार लोगों के हक के लिए लिया गया बहुत बड़ा फैसला था। इतना ही नहीं कानून व्यवस्था को भी हरियाणा प्रदेश के

अन्दर ठीक तरीके से लागू किया जिससे हरियाणा का नाम देश में ही नहीं अपितु पूरी दुनिया के नक्शे पर उभरकर सामने आया। माननीय मुख्यमंत्री जी का यह कहना भी दुरूस्त है कि आटोमोबाईल इण्डस्ट्री की ज्यादा इकाईयां हरियाणा में होने की वजह से और लोग भी यहां पर आने के लिए आकर्षित होने लगे हैं। स्पीकर सर, आपके माध्यम से जो मैंने कालिंग अटैंशन मोशन सदन में रखा उस पर बोलते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह बात कही है इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। इसके अलावा मेरा यह भी कहना है कि अगर नैनो कार प्रोजैक्ट हरियाणा को नसीब हो जाता है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इससे हरियाणा में एक नये भविष्य की शुरुआत हो सकती है। हमारी नौजवान पीढ़ी को एक अच्छी दिशा मिल सकती है। इससे हरियाणा की आमदन बढ़ सकती है, रोजगार भी बढ़ सकता है और कारोबार के आयाम भी बढ़ सकते हैं। जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है अगर ये सब हो सके तो नैनो कार प्रोजैक्ट को हरियाणा में अवश्य लाना चाहिए। यह हरियाणा के लिए एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात होगी। जहां तक इस प्रोजैक्ट के लिए जमीन उपलब्ध करवाने का सम्बन्ध है हम इसके लिए पलवल, ग्रं और मेवात में जहां भी माननीय मुख्यमंत्री चाहेंगे जमीन दिलवा देंगे। इस बारे में मेरा एक सुझाव यह भी है कि के०एम०पी० और इस्टर्न एक्सप्रैस हाईवे के चारों तरफ ऐसी बहुत सी बेकार जमीन पड़ी हुई है जी किसी भी काम नहीं आ सकती। इसलिए उस जमीन को भी नैनो कार प्रोजैक्ट के लिए कंसीडर किया जा सकता है। कुल

मिलाकर मैं यह कह सकता हूं कि जहां भी जमीन की मांग रखी जायेगी हम लोगों से यह बात कहलवा देंगे कि जमीन वहां पर उपलब्ध करवाई जा सकती है।

विधान सभा हाल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा लगाना

श्री फूल चन्द मुलानाः अध्यक्ष महोदय, आपने जो हाउस को रैनोवेट करवाया है इसके लिए सारा हाउस आपकी तारीफ करता है और यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे कुछ साथी जिनको प्रांत की जनता ने चुनकर यहां भेजा है वे यहां ठीक व्यवहार नहीं करते। उनके लिए न कोई आदर्श है और न ही कोई नियम है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी देश के सर्वमान्य नेता है उनका चित्र कई प्रांतों की असैम्बलीज में लगा हुआ है, पंजाब की असैम्बली में भी लगा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है इस विधान सभा में भी आपकी कुर्सी के पीछे खम्भे पर महात्मा गांधी जी का चित्र लगा दिया जाना चाहिए ताकि इन साथियों को कुछ प्रेरणा मिल सके।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत अहम बात है। फादर आफ दि नेशन महात्मा गांधी जी का चित्र कई असैम्बलीज में लगा हुआ है। हमारी विधान सभा में भी महात्मा गांधी जी का चित्र लगा दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा।

श्री अध्यक्षः ठीक है।

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker: Now the Parliamentary Affairs Minister will move the Motion under Rule 15.

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move---

That the proceedings on the items of business fixed for today he exempted at this day's sitting from the provisions of the **Rule** '**Sittings** of the Assembly', identifinitely.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

Mr. Speaker: Question is—

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly' indefinitely.

The motion was carried.

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the Motion under Rule 16.

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, **I** beg to move—

That the Assembly at its rising this day shall stand

adjoured sine-die.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

Mr. Speaker: Question is—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

The motion was carried.

सदन की मेज पर रखे गये कगज–पत्र

Mr. Speaker: Now, a Minister will lay papers on the Table of the House.

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to lay on the Table of the House—

The Annual Report of Haryana Forest Development Corporation Limited for the year 2001-2002, as required under section 619-A(3)(b) of the Companies Act, 1956.

The Annual Statement of Accounts of Haryana Urban Development Authority for the year 2006-2007, as required under section 19-A(3) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.

The 8th Annual Report of Uttar Haryana Bijli Vitran Nigam Limited for the year 2006-2007, as required under section 619-A(3)(b) of the Companies Act, 1956.

विधान कार्य

दि हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (नं० 3) बिल, 2008

Mr. Speaker: Now, the Finanace Minister will introduce the Haryana Appropriation (No. 3) Bill, 2008 and will also move the motion ofr its consideration.

Finance Minister (Shri Birender Singh): Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No. 3) Bill, 2008.

Sir, I also beg to move -

That the Haryana Appropriation (No. 3) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Haryana Appropriation (No. 3) Bill be taken into consideration at once.

श्री राम कुमार गौतम (नारनौंद): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं कि इन्होंने बी०सी० के भाइयों के लिए भी जोड़ दिया कि उनको भी 100– 100 गज के प्लाट दिये जायेंगे। इससे पहले केवल एस०सी० के भाइयों के लिए ही यह स्कीम थी। गाँव में जो सफाई कर्मचारी लगाये गये हैं जिस पर इनैलो के साथी ऐतराज कर रहे थे, उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं क्योंकि उससे गाँवों में सफाई की व्यवस्था सुदृढ़ होगी।

अध्यक्ष महोदय, एस०सी० भाइयों को जो पहले भूमि दी गई थी वे प्लाट उनको अभी तक नहीं मिल पाये हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि सरकार ने यह जो प्लान शुरू की है, एस०सी०/बी०सी० वालों को 100- 100 गज के प्लाट देने की सरकार ने घोषणा की है, क्या सरकार ने उसके लिए जमीन एक्वायर की है? अगर सरकार यह समझती है कि गाँवों में पंचायती जमीन पड़ी है उस पर प्लाट काट दिये जायेंगे तो यह सोच ठीक नहीं है क्योंकि एक-आध जगह को छोड़ कर कहीं भी पंचायती जमीन नहीं है। यदि सरकार इन भाइयों को जमीन दे भी देगी तो भी उन पर नाजायज कब्जे होंगे, क्योंकि उन बेचारे गरीब भाइयों को कोई भी जमीन नहीं लेने देगा। अध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार को सलाह है कि हर गाँव में, हर शहर में जमीन एक्वायर कीजिए और उसके बाद सुनिश्चित कीजिए कि जिन लोगों को आप जमीन देना चाहते हैं, उस पर उनका कब्जा हो जाये, उनको जमीन मिल जाये क्योंकि पहले का तजुर्बा अच्छा नहीं रहा है। दूसरी बात बी०सी० के भाइयों के लिए जो नौकरियों का प्रावधान किया है वह मी एक अच्छा काम सरकार ने किया है। पहले जब चौटाला जी की सरकार चल रही थी तो उनका मकसद था कि मण्डल कमीशन लागू न हो और उस समय इस उद्देश्य से बहुत बदमनी फैला दी थी। हरियाणा में डिपु के डिपु जलवाये थे ताकि मण्डल कमीशन की सिफारिशें लागू न हो सकें और किसी बी०सी० के भाई को नौकरी न मिले, उसके लिए उन्होंने गुरनाम सिंह कमीशन बना कर सभी बड़ी-बड़ी जातियों

को बैकवर्ड बना दिया था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को यह बात कहना चाहता हूँ कि अगर वे सही मायने में सभी गरीब लोगों की, सभी गरीब जातियों की, सच्ची सेवा करना चाहते हैं तो (बैकवर्ड क्लास के भाईयों के लिए भी सरकार उनको तोहफा देकर आए और उस कमी को पूरा करे) जो कांग्रेस पार्टी के रिजीम में चौधरी भजन लाल जी जो उस समय मुख्यमंत्री थे ने पैदा की थी। 1991 1992 में सारे देश में मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू की गई और 27 परसैंट नौकरियां सभी जगह दी गई। हरियाणा में चौधरी भजनलाल जी अपने–आपको नॉन जाट का सबसे बड़े चौम्पियन समझते थे, लोगों को बहकाते भी थे और बहुत लोग उनके बहकावे में आये भी थे, उन्होंने उनका गला काटने का काम किया। हरियाणा में 1991 की बजाय 1995 में मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू की गई और वह भी केवल श्रेणी–3 और श्रेणी–4 की। 16% और 11% की दो कैटेगरिया बी०सी०–ए और बी०सी–बी बनाई थी। बी०सी०–ए में जो असली बैकवर्ड नाई, तेली, धोबी, छीपी की 16% की जाति हरियाणा में मानी और बी०सी०–बी में हमारे यादव, गुज्जर, मेव, सैनी और लोनी जो हरियाणा में उपस्थित नहीं हैं, ये 5 जातियां डाली। क्लास– 1 और क्लास–2 की नौकरियों में इन भाइयों को 10 परसैंट का कोटा मिल रहा था जिसको लेकर वे गुजारा कर रहे थे, वह उनका हक छीन लिया गया। 1995 में ये जातियां भी उस 10 परसैंट में डाल दी। उसके बाद 1995 से लेकर आज तक बेचारे गरीव बैकवर्ड क्लासिज के भाइयों का कोई बच्चा गजटिड

ऑफिसर बना ही नहीं, कोई एक–आध ही बना होगा। अध्यक्ष महोदय, जिस खोर में एक साधारण बछिया या कटडी चर रही हो और उसी खोर में खागड और झोटे चरने के लिए छोड़ दिये जायें तो वह गरीब बछिया चर नहीं पायेगी। कम से कम वे लोग जिनके 6–6 एम०एल०ए० और मंत्री सैंटर में भी हैं, उनका सब कुछ है, उनको तो इसमें नहीं डालना चाहिए था। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आपकी मार्फत गुजारिश करता हूं क्योंकि मुझे थोड़ी तकलीफ नहीं है, बड़ी भारी तकलीफ है। यह जो इन भाइयों की कमी है इसको सरकार जरूर दूर करे। मुख्यमंत्री जी, बैकवर्ड क्लास वाले भाई आपका सम्मान करने के लिए आपको बुला रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप उनको यह तोहफा दे कर आएं ताकि इन गरीबों के बच्चे भी कोई क्लास– 1 या क्लास–2 की नौकरियों में अफसर बन सकें। अध्यक्ष महोदय. मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक डाकू गिरोह के लोग ओम प्रकाश चौटाला जैसी पार्टी के लोग जो हरियाणा में ही नहीं इस देश के फादर ऑफ करप्शन, करप्शन के भगवान, करप्शन के माई–बाप, लूट–पाट करने वाले, भेदभाव करने वाले, गुण्डागर्दी करने वाले, गरीबों के साथ अन्याय करने वाले, अत्याचार करने वाले ऐसे व्यक्ति और इस दल के लोग हमारे मंत्रियों और सरकार के खिलाफ करप्शन के इल्जाम लगा रहे हैं और यहां पर धड़ल्ले से बोल रहे हैं। स्पीकर सर, ये लोग ऐसे दल के लोग हैं जो शहरों के अन्दर अवांछित इलाके होते हैं जहां कोई आदमी रात–बेरात घुस जाता है और मुंह छिपा कर आता है

कि बड़ा कुकर्म करके आया हूं ऐसे दल के लोग ऐसी बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, यह बहुत ही सीरियस मामला है यह कोई छोटा मामला नहीं है, इस पर गौर कीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत बताना चाहूंगा कि कहां–कहां क्या–क्या भारी कमियां हैं, इन पर सरकार गौर करे। मुख्यमंत्री जी, आपका हर ऑर्डर लागू होना चाहिए लेकिन 100 में से 99 ऑर्डर लागू नहीं होते हैं। जो आफिसर्ज आपके ऑर्डरज को लागू नहीं करते उनको सीधा करो। अलग–अलग डिपार्टमैंट्स में जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको चौक करके भ्रष्ट लोगों को सजा दें वरना आपकी सरकार जो अच्छे कार्य कर रही है वह सारी की सारी छवि खराब हो जाएगी।

श्री अध्यक्षः गौतम जी, आप ऐप्रोप्रियेशन बिल पर बोलें।

श्री राम कुमार गौतमः अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ सही बात आपको बताना जरूरी समझता हूं अगर कहीं गाड़ी निकल गई तो उसके बाद बैठे रह जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, एक ऐसा वोट बैंक जो यह भी कभी नहीं पूछता था कि कैंडीडेट कौन है, वह बलात्कारी, अत्याचारी, बेईमान है या अच्छा, बुरा या लफंगा अथवा अंगहीन है वह कांग्रेस पार्टी के नाम पर वोट देता था। सरकार का एक बहुत बड़ा गलत फैसला है उसके बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इसे जरूर गौर से सुनें। कहीं भी नये स्कूलों में आपने संस्कृत लैक्चरर की पोस्टें नहीं दी हैं जिसके कारण लोगों में बड़ा भारी रोष है। संस्कृत के सारे टीचर्ज 90 से 100 प्रतिशत ब्राह्मण होते थे। अब भी संस्कृत पड़ाने वाले 90

प्रतिशत ब्राह्मण हैं, आपके इस फैसले के प्रति लोगों में बड़ा भारी रोष है। किसी स्कूल में आपने लैक्चरर के पद नहीं दिये, जूनियर और सीनियर लैक्चरर्ज के पद भी नहीं दिये। सरकार इस कमी को दूर करे। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात बी०ए०, बी०एड० बच्चे हैडमास्टर के लिए इलिजिबल होते हैं, प्रमोट होते हैं, यह जो शास्त्री लोग हैं इनकी इतनी क्वालिफिकेशन है जो कि बी०ए०, बी०एड० की क्यालिफिकेशन है, वही क्वालिफिकेशन संस्कृत ओ०टी० वालों की भी है। संस्क का टीचर पांच साल में शास्त्री करता है उसके बाद एक साल ओ०टी० करता है तब सत्का टीचर बनता है। आप उनको भी मौका दें और बी०ए०, बी०एड० के आधार पर संस्कृत ओ०टी० को मान्यता दें उसके बाद आपका बहुत बड़ा स्वागत होगा, बहुत बड़ी और अच्छी फीलिंग लोगों में जाएगी। एक दिन गुप्ता जी मुझे कहने लगे कि गौतम जी वे लोग आपको ही क्यों मिलते हैं? आपके नालेज के लिए बताता हूं। गुप्ता जी, वे लोग कई बार मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, वे लोग मेरे पास आए थे। (विघन)

शिक्षा मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। गौतम जी, आप गलत बात न कहें। अगर वे लोग आपसे मिलते हैं तो इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वे लोग सभी से मिल सकते हैं। संस्कृत टीचर्ज का डैलिगेशन माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला और मुझे भी वह डैलिगेशन कई बार मिला। उनकी जो मांगे हैं उनको हमने मान रखा है और वे

प्रोसैस में हैं और वह भी आपके कहने या आपकी सिफारिश से नहीं है। We are also responsible for that.

श्री राम कुमार गौतमः अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि उनकी मांगे मान लें तो आने वाले समय में रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। अध्यक्ष महोदय, अब मैं ओल्ड एज पैंशन के बारे में कहना चाहता हूं कि गांवों और शहरों के 50 से 60 साल की उम्र के कई लोग जुगाडू करके पैंशन ले लेते हैं लेकिन जो 60 साल से०पर के लोग हैं वे उस पेंशन से महरूम रह जाते हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन हैं कि जो लोग अब 60 साल से०पर के हैं और जब से वे 60 साल के हुए हैं, उनको पैंशन नहीं मिल रही है इसलिए उनको तब से पैंशन दी जाए। जिन लोगों ने जुगाडू करके 50 साल की उम्र में ही पैंशन लगवा ली थी उनसे तब से ही जब से वे पैंशन ले रहे हैं डबल हर्जाना लगा कर वापिस लिया जाए ताकि दोबारा से कोई इस प्रकार का डेयर न कर सके। अध्यक्ष महोदय, पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट सभी जगहों में पीने के पानी की व्यवस्था करता है। इस बारे में मेरा मंत्री जी से कहना है कि जहां पर भी पानी की लाइनें बिछाई जाएं वे ब्रापर बिछाई जाएं और एक भी गली को न छोड़ा जाए। मेरे पास टैलीफोन आया है और मुझे बताया गया है कि विभाग ने सात–आठ मोहल्ले ही छोड़ दिये हैं। अध्यक्ष महोदय, कई जगहों पर कई भाइयों ने अपनी पॉवर से लाइनें तोड़ रखी हैं, उनके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, नारनौंद से खांडा रोड है वहां पर भी मैंने पुल बनाने की बात कही थी। सरकार के द्वारा वहां पर रिटेनिंग वील तो बना दी है, इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं लेकिन वहां पर पुल का थोड़ा सा हिस्सा वैसे ही रह गया है उसको भी ठीक करवाने की कृपा करें। इसी तरह से नारनौंद से सुलचानी रोड है वह 7–9 साल पहले बनी थी लेकिन इसके बीच में 7–8 एकड़ का टुकड़ा बनाया नहीं गया था क्योंकि उसके लिए जमीन एक्वायर नहीं हुई थी। यह सड़क मार्किटिंग बोर्ड ने बनाई हैं। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस बारे में विभाग सोया न रहे और इस बचे हुए टुकड़े को बनाया जाए।

अध्यक्ष महोदय, पुठ्ठी से बडछप्पर रोड पर रोड़े तो डाल दिए गए थे लेकिन उसके बाद कुछ नहीं किया गया और वह सड़क अभी भी बुरी हालत में हैं। वह सड़क आज तक कम्पलीट नहीं हुई है। वहां का ठेकेदार भाग गया है, उस पर सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए। अध्यक्ष. महोदय, मुझे खंडेलवाल जी ने एक लैटर दिया है, उसमें मैंशन है कि मुख्यमंत्री जी ने हमारी मांग मान ली है। जब यह मांग की गई थी कि उस समय वित्तमंत्री जी ने भी कहा था कि अगर यह काम हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। अध्यक्ष महोदय, हमारी यह मांग सीसर से पेटवाड़ वाया बडाला की सड़क को बनाने की थी। मुझे पता चला है कि इसको पेटवाड़ से बडाला तक ही बनाया जाएगा और बडाला से सीसर को डैफर कर दिया गया है। यहां पर एग्रीकल्चर मिनिस्टर जी बैठे हुए हैं,

अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से इनसे प्रार्थना है कि इस सड़क को जैसा कि खंडेलवाल जी ने लैटर दिया था और उसमें जो मैंशन है, उसी तरह से पूरा बनाया जाए। सर, कुछ सड़कें जो मुख्यमंत्री महोदय मंजूर करके आए थे उनके लिए मैंने बार–बार कहा है। सर, राजली पुल से खानपुर से सीधा डाटा, उजली पुल से खानपुर होकर सीधा गुराना, ये ऐसी इम्पोर्टेंट रोड्ज हैं जिनका काम जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए और जो सड़कें बहुत खराब हालत में हैं, उन सड्कों को जल्द से जल्द रिपेयर करवाया जाए।

श्री अध्यक्षः गौतम साहब, आप लिखवाकर भिजवा देना। फाईनैंस मिनिस्टर आपके दोस्त हैं वे इस बारे में देख लेंगे।

श्री राम कुमार गौतमः सर, दो मिनट में मैं अपनी बात पूरी कर देता हूं।

श्री अध्यक्षः फिर क्या आपकी उनसे सूखी दोस्ती है? आप इस बारे में लिखकर भिजवा देना क्योंकि अभी दूसरे मैम्बर्ज ने भी बोलना है।

श्री राम कुमार गौतमः सर, मैं जल्दी ही अपनी बात समाप्त कर देता हूं। सर, कल आप कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है लेकिन मैंने उसको पड़ा नहीं है इसलिए मैं आपके माध्यम से उस बारे में थोड़ा सा और बताना चाहता हूं और गुजारिश करना चाहता हूं। अभी जो बारिश हुई है उससे कई

गांवों में भयंकर नुकसान हुआ है इसलिए मेरा कहना है कि इसकी स्पेशल गिरदावरी फौरन करवायी जाए। स्पीकर सर, मेरे हल्के के पुठ्ठी, मोला बास, बडछप्पर, बखलाना, खेड़ी गगन, गढ़ी, सोरखी, शेखपुरा आदि गांवों में स्पेशल गिरदावरी की जरूरत है। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि थोड़ी देर पहले यहां पर डेंगू और मलेरिया का जिक्र आया हुआ था, डेंगू और मलेरिया की रोकथाम के लिए भी अभी तक डॉक्टर की कोई टीम नहीं पहुंची है। बहन जी इतने सालों से हैल्थ मिनिस्टर हैं और मैं इनसे बास के अस्पताल के बारे में एक डॉक्टर की डिमांड करते करते थक गया लेकिन यह हमारी बदकिस्मती है कि बास गांव के अस्पताल में एक डॉक्टर भी नहीं गया जबकि बास हमारा चार पंचायतों का गांव है। स्पीकर सर, अगर ऐसा हो रहा है तो फिर बहन जी के हैल्थ मिनिस्टर बनने का फायदा क्या है? इसी तरह से पुठ्ठी गांव में एक भी डॉक्टर नहीं है, कोई फार्मेसिस्ट नहीं है। स्पीकर सर, गांवों में तो कम से कम डॉक्टर भेजे ही जाने चाहिएं। शहरों में तो डाकुओं ने डाका डालकर बड़े–बड़े प्राईवेट होस्पीटल्ज खोल रखे हैं।

डॉ० शिव शंकर भारद्वाजः स्पीकर सर, मैं भी एक डॉक्टर हूं और मैं सारे बीमार लोगों का इलाज करता हूं। ये जो डाकू वाली बात कह रहे हैं वह बिल्कुल गलत है। वह शब्द वापस लिए जाने चाहिएं।

श्री राम कुमार गौतमः डाक्टर साहब, कोई बात नहीं। I am sorry. आप बैठिए। स्पीकर साहब, इसी तरह से पहले मच्छर मारने वाली धुएं की गाड़ी धुआ छोड़ने के लिए जाती थी और डी०डी०टी० दवाई का छिड़काव भी किया जाता था लेकिन अब यह छिड़काव नहीं किया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि यह छिड़काव तुरन्त किया जाना चाहिए और गांवों के हैल्थ सैंटर्ज में डाक्टर्ज की टीम भेजी जानी चाहिए। इसी तरह से बी०पी०एल० कार्ड बनाने में जो लोग जानबुझकर गड़बड़ी कर रहे हैं उनके खिलाफ ऐक्शन लिया जाए।

श्री अध्यक्षः गौतम साहब, आपको बोलते हुए 17 मिनट हो गये हैं इसलिए अब आप वाईंड–अप करें।

श्री राम कुमार गौतमः सर, एक मिनट में मैं अपनी बात खत्म कर देता हूं। इसी तरह से नकली बीज और दवाई बेचने वालों के खिलाफ भी ऐक्शन लिया जाना चाहिए। इनके खिलाफ ऐक्शन लेने के लिए तगड़ा कानून बनाया जाना चाहिए। जिस तरह से धारा 302 और धारा 307 में सख्त सख्त का प्रावधान है उसी तरह से इनके खिलाफ भी बहुत जबरदस्त कानून बनना चाहिए और सख्त ऐक्शन इनके खिलाफ लिया जाना चाहिए। जितने भी ये बेईमान सरकार की इमेज खराब कर रहे हैं उनको सख्त सबक सिखाया जाना चाहिए ताकि ये दोबारा से इन चीजों का नाम न ले सकें। स्पीकर सर, प्रिंसिपल और हैड मास्टर्ज को लगाने की पॉलिसी बनायी गयी है। अनेक गांवों में इनकी पोस्टस खाली पड़ी

हैं इसलिए जल्द से जल्द इनकी पोस्ट्स भी भरी जानी चाहिए। धन्यवाद।

श्री एस०एस० सुरजेवाला (कैथल): स्पीकर साहब, कल भी कृषि के बारे में मैंने चर्चा की थी। मैंने कल मुख्यमंत्री जी का पूसा 1121 के एक्सपोर्ट पर बैन हटवाने के लिए आभार भी प्रकट किया था। अध्यक्ष महोदय, एक ऐसा महत्वपूर्ण आसपैक्ट है जिसके बारे में मैं पहले भी कई बार हाउस में कह चुका हूं। खेतीबाड़ी के भाव जो इस वक्त किसान को मिल रहे हैं वह काफी अच्छे हैं। आज किसान खुशहाल है। आज जहां सरकार अच्छे भाव दे रही है वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे आसपैक्ट्स भी हैं जिनकी वजह से खेती करने वालों को घाटा भी हो रहा है। इसमें सबसे पहले मैं यह कहूंगा कि खेती में कई तरह की मशीनरी यूज होती है चाहें पम्पिंग सैटस हैं, गरीब से गरीब आदमी भी पम्पिंग सैट के द्वारा अपनी खेती को पानी देने की कोशिश करता है। इसके अलावा भी जो दूसरी मशीनरी हैं जैसे ट्रैक्टर हें, कम्बाईन हैं या दूसरे तरह के इम्पलीमैंट्स हैं जो पावर से चलते हैं। इन इम्पलीमैंट्स में डीजल इस्तेमाल होता है। मिट्टी का तेल जो है उसकी भारी मात्रा में डीजल में मिलावट है। इस बात का सबको पता है, सरकार को पता है, डिप्टी कमिश्नर को पता है, डिप्टी डायरैक्ट फूड एंड सप्लाईज को पता है लेकिन सब उदासीन हैं। कोई इस तरफ ध्यान नहीं देता। किसान बेचारा बेबस है, उसका बस नहीं चलता है। इस समस्या के हल के लिए मैं चाहूंगा कि जो सिविल

सप्लाईज डिपार्टमैंट के अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए जिनका काम उनको चौक करना है। मिट्टी का तेल गांव और शहरों के गरीब लोगों के लिए आता है और उसकी गाड़ी की गाड़ी पैट्रोल पम्प वाले ले जाते हैं और डीजल में इस्तेमाल करते हैं। इसका कारण यह है कि इसमें जो वर्तमान में सजा है वह नाम मात्र की है। यह बहुत पुराना ऐक्ट है, बहुत पुराना कानून है। इस सरकार का अन्नी भी डेढ़ साल बाकी है, सरकार चाहे तो यह काम कर सकती है। यह लोगों की बहुत बड़ी मांग है और जहां बहुत अच्छे–अच्छे काम सरकार ने किए हैं वहां यह काम भी करने चाहिएं। इसके लिए चाहे भारत सरकार को लिखना पड़े तो भी लिखना चाहिए। मिलावट करने वाले को कम से कम उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। इसके अलावा बीज हैं वह काफी मात्रा में नकली बिकते हैं। किसान के साथ चीटिंग की जाती है।ऽंचे भाव पर बीज दिये जाते हैं जब वह खेत में जाकर बोता है तो बोता कुछ है और पैदा कुछ और ही होता है। कीडेमार दवाइयों में भी बड़ा भारी स्कैण्डल है। प्राइवेट कंपनीज इसको बनाती हैं। उनके इतने मुश्किल नाम हैं कि किसान समझ ही नहीं सकता। नाम से कतई पता नहीं चलता कि क्या दवाई है। मनमानी कीमतें हैं और उनमें भी बहुत सी नकली दवाइयां हैं, स्पूरियस हैं। पैस्टीसाइड्स और इन्सैक्टीसाइड्स में भी बड़ी चीटिंग होती है। उसमें भी सजा कोई नहीं है। जिस महकमे का यह काम है उसके मंत्री चट्ठा साहब यहां बैठे हैं। स्वयं किसान हैं और किसान के लिए इनके दिल में

दर्द भी होगा। इनके महकमे में जो क्वालिटी कंट्रोल वाले हैं उनका काम सिर्फ मंथली इकट्ठा करना है वह उन्हें घर में या दफ्तर में दे जाते हैं इसलिए कोई किसी को नहीं पकड़ता है। खाद हैं, बीज हैं, कीडेमार दवाइयां हैं या डीजल है और जितने भी ऐग्रीकल्चर इन्पूट्स हैं, मैं यह चाहूंगा कि इस मामले में कम से कम उस कैद की सजा हो और लाइसैंस जब्त हो और उसको हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाए। विशेषतौर पर डीजल जो है इसमें खास तौर से ध्यान देने की आवश्यकता है। धन्यवाद।

डॉ० शिव शंकर भारद्वाज (भिवानी): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो बी०सी–ए के लोगों को राहत दी है, यह एक ऐतिहासिक कदम है। यह गरीब आदमी के लिए बहुत लम्बे समय तक काम आने वाली बात होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भिवानी में जो रीसैट्ली जलभराव की समस्या उत्पन्न हुई है इससे लोगों को बड़ी भारी तकलीफ हुई है, इसकी तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यह समस्या पिछले 10 साल में कई बार पैदा हुई है। इसका कुछ न कुछ परमानैंट समाधान जब तक नहीं किया जाएगा तब तक जनता को राहत नहीं मिल सकती। इस जलभराव का बहुत बड़ा कारण भिवानी में यह है कि जो स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज है, वह अलग नहीं है और सीवरेज की जो बात है वह भी बहुत इन–ऐडीक्वेट है। मुझे यह कहते हुए अफसोस हो रहा है

कि हुडा इतनी अमीर संस्था होते हुए और पैसे की उसके पास कमी नहीं होते हुए भी हुडा ने सैक्टर 15 बनाया, सैक्टर 23 बनाया, इण्डिस्ट्रियल सैक्टर 21 बनाया, सैक्टर 26 बनाया। नयी और पुरानी हाउसिंग बोर्ड कालोनी बनायी गयी थी और अब एक और नयी हाउसिंग बोर्ड कालोनी सर्कुलर रोड पर बनी है लेकिन उसमें सीवरेज का कोई डिस्पोजल नहीं बनाया है। सारे इण्डिस्ट्रियल एरिया का दूषित जल शहर के ओपन नालों में गिर जाता है और नाले ब्लॉक हो जाते हैं और चॉक हो जाते हैं। सारी सड्कों पर पानी फैल जाता है, मच्छर और डेंगू और मलेरिया स्वास्थ्य खराब करने का कारण बनता है। मैं एक प्रार्थना करना चाहूंगा कि हुडा अगर यह सीवरेज का डिस्पोजल बना दें तो हमारी 25–30 प्रतिशत समस्या जो जलभराव की है वह ठीक हो सकती है। हमारे माननीय पब्लिक हैल्थ मिनिस्टर भिवानी में 15 अगस्त को झण्डा फहराने के लिए गये थे। उन्होंने इस समस्या को स्वयं देखा है कि भिवानी का क्या हाल रहा है। हमें कम से कम एक सुपर सैक्कर मशीन दी जाए और दो बड़ी मशीनें और दे दी जाएं ताकि सीवरेज ब्लॉकेज की हमारी इस समस्या को ठीक किया जा सके। भिवानी में दो ही सीवरेज के डिस्पोजल हैं। एक को तो हीट लाईन पर करवा दिया है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं और दूसरी लाईन को भी हीट लाईन पर करवायें। जब तक दो डिस्पोजल नहीं बनेंगे तब तक हमारी सीवरेज की समस्या ठीक नहीं हो सकती है। सीवरेज के काम की रिपेयर के लिए अच्छा पैसा दिया है, इस बात के लिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा

लेकिन पिछले दो साल में अच्छा पैसा नहीं दिया था। इस साल तीन करोड़ रुपये आपने नयी सीवरेज लाईन के लिए और 25 लाख पुरानी लाईन की रिपेयर के लिये दिया है, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं यह राशि बढ़ाई जानी चाहिए क्योंकि जो खान चल रहा था वह 15 करोड़ का था। अगर हर साल 3 करोड़ दिये जाते जब जाकर 15 करोड़ पूरे होते। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि अगले आने वाले समय में 15 करोड़ रुपये की इस राशि को पूरा कर दिया जाए।

श्री अध्यक्षः भारद्वाज साहब, वाईंड–अप कीजिए।

डॉ० शिव शंकर भारद्वाजः राजगढ़ में एक वाटर वर्क्स बन रहा था उसको बनते हुए चार साल हो गये हैं लेकिन उसका काम पूरा नहीं हुआ है बहुत सालों से काम चल रहा है। इसके लिए कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। इसी प्रकार से प्रहलादगढ गांव में दो मार्च 2006 को वाटर वर्क्स का इनआगुरेशन हुआ था लेकिन पता नहीं क्या कारण रहा कि उसका काम अब तक शुरू नहीं हो पाया है। इसी प्रकार मेरे हल्के के गांव उमरावत, गोरीपुर में वाटर वर्क्स की बहुत जरूरत है, मैंने इसके लिए लिखित में भी दिया है। इस पर आप गौर करें। कितलाना और नीमडीवाली गांवों में जल घर तो बन गए थे। लेकिन उनमें जल नहीं था। अब नीमडीवाली गांव में तो आपने ऑल्टरनेटिव चौनल बनाकर जल की पूर्ति कर दी है लेकिन कितलाना में आपने आदेश दे दिया है, लेकिन काम चल तो रहा है लेकिन काम अभी तक पूरा नहीं हुआ

है, इसके लिए भी सरकार एक्शन अवश्य ले। इसी प्रकार से ढाणा लाडनपुर में पाईप डलने का काम वर्षों से चल रहा है, पता नहीं कब तक पूरा होगा। इसके लिए अधिकारियों की एकाउंटेब्लिटी फिक्स करें तब जाकर यह काम हो सकता है। इसी प्रकार से 15.11.2006 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक गर्ल्ज स्कूल की एनाउसमैंट की थी लेकिन इस बारे में जब भी अधिकारियों से मिलते हैं तो वह यह कह देते हैं कि हमें जमीन दे दो। जिस प्रकार से श्री विनोद शर्मा जी ने कहा था कि एक एम०एल०ए० का काम जमीन देना थोड़े ही है यह तो सरकार का ही काम है। सरकार ही जमीन को फाईंड आउट करे और स्कूल के लिए जगह को आईडैंटिफाई करे ताकि यह स्कूल बनाया जा सके। सड्कों की हालत बहुत खराब है। मेरी एक प्रार्थना है कि जब भी रोड बनाई जाए तो पहले ड्रेनेज का इन्तजाम किया जाए और ड्रेनेज का काम ठीक ढंग से किया जाए। मैं पिछले 15 सालों से देख रहा हूं कि जो भी रोड बनाये जाते हैं वे तीन महीने में ही खराब हो जाते हैं। मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि डिफरेंट डिपार्टमैट्स में आपस में कोआर्डीनेशन नहीं है। धन्यवाद।

श्री सुखबीर सिंह (रौहट): स्पीकर सर, हरियाणा सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने पिछले सादे तीन सालों में रिकार्ड तोड़ काम किया है। इसमें चाहे कृषि हो, किसान हो, मजदूर हो, खिलाडी हो, चाहे व्यापारी हो, इन सभी में हरियाणा का नाम नम्बर एक पर है। हरियाणा

हिन्दुस्तान में हर चीज में सबसे आगे है। ओलम्पिक में जो बच्चे जीतकर आए हैं, उनको डी०एस०पी० भर्ती किया गया है, इसके लिए हरियाणा सरकार की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी थोड़ी है। हरियाणा सरकार ने बहुत बड़े–बड़े काम किए हैं जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। हरियाणा सरकार ने जनहित के कई कार्य किए हैं। पिछली सरकार के मुख्यमंत्री अनपढ़ थे, उनको शिक्षा और खेलों के बारे में ज्ञान नहीं था। अध्यक्ष महोदय, यहां विधान सभा में कहा जा रहा है कि बच्चों के लिए सभी तरह की शिक्षा जरूरी है, चाहे वह टैक्नीकल हो या फिर खेलों की शिक्षा हो। पिछली सरकार के जो मुख्यमंत्री थे वह शिक्षा के बारे में जानते नहीं थे क्योंकि वे कभी स्कूल में ही नहीं गए, उन्होंने हमेशा राजनीति का व्यापारीकरण करने का काम किया और सिर्फ धन दौलत कमाई। हरियाणा खेलों में, कृषि में और शिक्षा में हमेशा से ही आगे रहा है। हमारी हिन्दुस्तान में एक धाक होती थी लेकिन पिछली सरकार के समय में हरियाणा बहुत पिछड़ गया था लेकिन अब जो सरकार आई है इससे लोगों को बहुत आशाएं हैं। यह सरकार लोगों की बहुत सी आशाएं पूरी भी कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत ईमानदार हैं और इनकी सोच बहुत अच्छी है। हम तो यह चाहते हैं कि ये जब तक जिएं मुख्यमंत्री रहें और इनको हमारी भी उम्र लग जाए क्योंकि इनके अंदर काबलियत है। अध्यक्ष महोदय, हमारी कुछ मांगें हैं जिनके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। खेलों के मामले में सोनीपत जिला हमेशा आगे रहा है। अभी सभी हमारे साथी जिक्र कर रहे थे कि सोनीपत का

सुसाना गांव बालीवाल गेम में हमेशा आगे रहा है। हरियाणा की ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान की बालीवाल की जो भी टीम बनी है, उसमें सुसाना गांव से 4– 5 प्लेयर्ज रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमारे यहां कोई एकैडमी बननी चाहिए और कोई नर्सरी बननी चाहिए। सुसाना हमारे इलाके का महत्वपूर्ण गांव है लेकिन पिछली सरकार द्वारा हमारे यहां खेलों की कोई सुविधा नहीं दी गई। हमारे सोनीपत के सी०आर० जैड स्कूल के बच्चे हाकी के खेल में हिन्दुस्तान में सबसे आगे रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे यहां न कोई एकैडमी है और न ही कोई स्टेडियम है और न ही खेलों से सम्बन्धित कोई और सुविधा दी गई है। हमारे सोनीपत के खरखौदा गांव के आस–पास आई०एम०टी० बनने जा रही है। आई०एम०टी० का बड़ा महत्व है। गुडगांव का विकास भी आई०एम०टी० के कारण हुआ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की एक सोच है कि हरियाणा में इंडिस्ट्रयलाइजेशन किया जाए ताकि बेरोजगारी खत्म हो। आई०एम०टी० के लिए किसानों की जो जमीन एक्वायर की जाएगी उसके लिए सरकार ने मुआवजा बढ़ाया जो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए 33 साल तक 15 हजार रुपये इन्सैंटिव भी मिलेगा। यह रिकॉर्ड की बात है। मुख्यमंत्री जी की इतनी बड़ी सोच है और किसी ने सोचा भी नहीं था कि किसानों को अपने बच्चे पालने के लिए इतना बड़ा फायदा होगा। साढे 3 साल पहले 15 लाख से 25 लाख रुपये तक मुआवजा रखा गया था लेकिन अब जमीन की कीमतें बहुत बढ़ गई है। इस बारे में चाहे तो 5 एम०एल०एज० की

कमेटी बनाकर तसल्ली करवा ली जाए 1 यह मुआवजा कम से कम 60–70 लाख रुपये होना चाहिए। अगर सरकार 23 लाख रुपये तक मुआवजा देगी तो यह सरकार की बहुत बड़ी मूल होगी क्योंकि वहां जमीन की कीमत 6०–7० लाख रुपये प्रति किला है और किसान आखों देखी मक्खी कैसे खा सकता है इसलिए मैं चाहूंगा कि आई०एम०टी० के लिए जो जमीन एक्वायर की जाएगी उसके लिए किसानों को कम से कम 75 लाख रुपये के हिसाब से मुआवजा जरूर दिया जाए। इस सरकार ने जितने अच्छे काम किए हैं उस बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। दिल्ली में 75 लाख रुपये मुआवजा किया गया है इसलिए हमारे यहां कम से कम 75 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा जरूर दिया जाए। हमारे यहां के लोगों में इस बारे में सरसराहट है और लोग मुझे कह रहे थे कि अगर सरकार 25 लाख रुपये के हिसाब से मुआवजा देती है तो आप इस्तीफा दे दो। अध्यक्ष महोदय, हरिजन बैकवर्ड भाइयों के पीले कार्ड के लिए भी बहुत बड़ी होड़ लग रही है। जहां तक सरकार गरीबों को प्लाट्स देने के बारे में बात कर रही है तो मैं इस बारे में कहना चाहूंगा कि गांवों में न तो डॉक्टर जाना चाहते हैं, न मास्टर जाना चाहते हैं क्योंकि उनको शहरों में सारी सुविधाएं मिलती हैं। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इतना तो अवश्य करें कि चाहे कोई नौकरी करने वाला है, बिजनैस करने वाला है, सभी हरिजन भाइयों और बैकवर्ड क्लास के गांवों में रहने वाले परिवारों को एक–एक खाट 100–100 गज का दिया जाये। उसमें किसी प्रकार की गरीबी रेखा की

या नौकरी वाले के लिए कोई कंडीशन नही होनी चाहिए। जो भाई हमारे गांव में रहते हैं वे गांवों की शोभा बढ़ाते है इसलिए उनकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाये। अध्यक्ष महोदय, हमने अपने फरमाना गांव में हमारे युवा सांसद दीपेन्द्र हुड्डा को बुलाया था, जहां उनका बहुत अच्छा स्वागत किया गया था। साधी और फरमाना गांव आसपास ही हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि मूल से ब्याज प्यारा होता है। चौधरी दीपेन्द्र हुड्डा जी जब फरमाना गांव में आये थे उस समय वे लोगों को आश्वासन देकर आये थे कि वे हमारी दो–तीन डिमांडज जरूर पूरी करेंगे। एक तो उन्होंने हावली से फरमाना तक की सड़क बनाने की डिमांड मानी थी, जिसकी तरफ 40 साल से किसी ने ध्यान नहीं दिया। दूसरा उन्होंने फरमाना में चौधरी मातूराम के नाम से आई०टी०आई० मंजूर की थी।

श्री अध्यक्षः फरमाना जी, आप अपनी डिमांडज लिखकर भिजवा देना। Please take your seat. अब प्रो० छतर पाल जी बोलेंगे।

प्रो० छत्तर पाल सिंह (धिराय): अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। स्पीकर सर, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो रोज की तवज्जो प्रांत की तरफ है और जो विभिन्न सैक्शंज से डिमांडज आती हैं उनको मुख्यमंत्री जी पहले ही अपने जहन में संजोकर रखते हैं। यही कारण है कि लोगों की अपेक्षा से पहले ही लोगों के इंट्रस्ट में मुख्यमंत्री जी की कोई न कोई घोषणा आ

जाती है। जिससे मतदाताओं और पोल्टीकल नेतृत्व के बीच में पूरे प्रदेश मेँ एक विश्वास बना है जो कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय की बहुत बड़ी उपलब्धि है। स्पीकर सर, एप्रोप्रियेशन बिल में कम्युनिटी डिवैल्पमैंट और एग्रीकल्चर के बारे में जो ईशूज हैं, मैं उन पर चर्चा करना चाहता हूं। मेरी मंत्री महोदय से गुजारिश है कि वे मेरी बात ध्यान से सुनें। स्पीकर सर, जहां तक एग्रीकल्चर का ताल्लुक है, हमारी 90 प्रतिशत जनसंख्या एग्रीकल्चर पर निर्भर है। जो लोग किसानों का हितैषी होने का दम भरते थे और किसान उनके झूठे वायदों में आ गये तथा उनका साथ दिया। लेकिन उन लोगों की सरकार बनने के बाद उन लोगों ने किसानों को चीट किया और उनके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया। यही कारण है कि हमारे प्रदेश में मतदाताओं और राजनेताओं के बीच में बहुत बड़ी खाई पैदा हो गई थी। यह खाई आज जो साथी विपक्ष में बैठें हैं उनकी देन रही है। इस समय वे लोग सदन में उपस्थित नहीं हैं। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस की सरकार ने इस खाई को खत्म करके जनता में विश्वास पैदा करने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर कम्युनिटी का प्रदेश के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी की अच्छी नीतियों की वजह से एग्रीकल्चर कम्यूनिटी में विश्वास पनपा है, उसके बहुत बड़े मायने हैं, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। स्पीकर सर, जो लोग गांवों में रहते हैं और खेती से जुड़े हुए हैं, आज उनके सामने अपनी आजीविका कमाने की सबसे बड़ी समस्या पैदा हो गई है

क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही हे और जमीन कम हो रही है। खेती करने वाले लोगों को कई बार बिजली की कमी की दिक्कत आ जाती है जिससे उनकी फसल प्रभावित होती है। अध्यक्ष महोदय, जो वाटर मैनेजमैंट का ईशू है उस पर भी पहले वाली सरकारों ने काम नहीं किया जिससे किसान हमेशा प्रभावित रहे। किसान कभी बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं, कभी सूखे की चपेट में आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो नहरों का जाल बिछा हुआ है उनकी समय पर रिपेयर और सफाई का काम न होने की वजह से ज्यादातर नहरों की टेल्ज पर पानी नहीं पहुंचता था जिससे किसानों को हमेशा दिक्कत आती रही है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक वाटर कोर्सिज की बात है, जो इंजीनियरिंग स्किल का स्टाफ है, उन्होंने लैवल्ज बनाते वक्त एस्टीमेट गलत बना दिया जिसको रैक्टीफाई करने में काफी समय लगता रहा और किसानों को हमेशा दिक्कत का सामना करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं यह भी कहना चाहूंगा कि प्रजातांत्रिक जमाना है इसलिए कई बार सख्त कदम भी नहीं उठाये जा सकते। जहां पर अधिकारियों और कर्मचारियों की गलतियां रहती हैं उनको बहुत लम्बी चौड़ी सजा जब तक नहीं मिले तब तक वे अपने आपको दुरुस्त नहीं करते। इसमें करप्शन इनवॉल्वमैंट का जो फैक्टर है उसकी वजह से भी किसान काफी सीमा तक प्रभावित रहता है। श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला जी ने जिक्र किया कि आज फसलों के भाव अच्छे मिल रहे हैं। इस बारे में एग्रीकल्चर मिनिस्टर के बयान भी आते रहते हैं। इसके बावजूद भी अच्छे बीज और अच्छे पैस्टीसाईडस की

किल्लत हमारे किसानों को प्रभावित करती ही रहती है। आज एक और बड़ी समस्या पैदा हो गई है हमारे किसान मजबूरन आर्थिक व्यवस्था को इम्प्रूव करने के लिए और बैटर प्रोडक्शन लेने के लिए हर किस्म के पैस्टीसाईड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे उनको इंस्टैंट प्रोडक्शन तो मिला है लेकिन उससे उनकी जमीन खराब हो गई है। इसके अलावा इससे उनकी हैल्थ भी इतनी प्रभावित होती रही कि कैंसर, टीबी. और हार्ट अटैक जैसी अनेक बीमारियों ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। मैं इस सदन का ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहूंगा कि ऑर्गेनिक मैन्योर बेस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्टस की तरफ आज हमारा ध्यान जा रहा है जिससे हम बैटर हैल्थ और अच्छी हाईजैनिक कंडीशन के बारे में सोचने लगे हैं। इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरी कांस्टीच्यूएंशी के किसान भाइयों को अपनी उपज को मण्डियों तक ले जाने के लिए सड्कों की कमी के कारण बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ऐसी कुछ महत्वपूर्ण सड्कों के निर्माण की मांग सरकार से करना चाहूंगा। वे सड़कें हैं खेदड से नवोदय विद्यालय पाबड्ा तक, लाडवा से मीरका तक, डाटा से सिसाय तक, फरीदपुर से भैणी बादशाहपुर तक, सिंघवा राघो से सिंघड तक, दौलतपुर हे किलाना तक। Speaker Sir, Khanpur Sindhar road has to be linked with Singwa Ragho village. इसके अलावा जो दौलतपुर से किलाना तक की सड़क है यह पहले आधी बन चुकी थी। इससे पहले भी मैंने इस अगस्ट हाउस का ध्यान इस ओर दिलाया था। तब मुझे

अश्योर भी किया गया था कि completion work will be taken up on priority basis, लेकिन अभी तक इस सड़क को नहीं बनाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक गुजारिश और सरकार से करना चाहता हूं कि गांवों के पास और म्युनिसिपलटीज मार्किट कमेटीज के पास कम्युनिटी डिवैल्पमैंट के लिए इतने फण्डज हैं कि हरियाणा में जितने भी विलेजिज हैं, अच्छी प्लानिंग के साथ उन सभी की गलियां सी०सी० से बन सकती हैं। इसके साथ ही उनकी डिस्पोजल के लिए अच्छे नाले भी बनाये जाने चाहिएं। इससे देहात के लोगों को बहुत फायदा होगा। इसके अलावा मेरी यह भी गुजारिश है कि जितनी सभी कम्युनिटीज हैं जिन गांवों में जनरल कास्ट के भी लोग बसते हैं उन गांवो में एस०सी० और बी०सी० के लोगों को प्लांट अलाट करने की बात कही गई है वहां पर जनरल कैटेगरी सहित सभी प्रत्याशियों को भी अगर उसी कंडीशन के आधार पर प्लॉट दिए जायें तो यह हरियाणा में एक बहुत अच्छा सबब संदेश होगा जिससे जाट बिरादरी व अन्य सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के भले की बात भी खे जायेगी। जिस प्रकार से राजस्थान में जाट बिरादरी को रिजर्व कैटेगरी में डाला गया है, इसी प्रकार से हमारे यहां भी जाटों की आर्थिक हालत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है इसलिए अगर उनको भी बी०सी० कैटेगरी के अन्दर डाल दिया जाये तो बहुत अच्छा होगा। अतः गुरनाम सिंह आयोग रिपोर्ट को बहाल किया जाना चाहिए। स्पीकर सर, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अरजन सिंह (छछरौली): अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा। मेरे पास वे शब्द नहीं हैं जिनसे मैं इनका धन्यवाद कर सकूं। मेरे छछरौली हल्के में इतने काम पिछले 50 सालों में भी नहीं हुए जितने काम इस सरकार के आने के बाद हुए हैं। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी व उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं। इसके बावजूद जो काम करता है उससे उम्मीद और बढ़ जाती है कि इन्होंने इतने काम किये हैं तो एक–आध और भी कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरे एक–दो काम रह गये हैं मैं उनके बारे में भी प्रार्थना करना चाहता हूं। एक तो जो सारी सड़कें पहले बनाई गई थी वे स्टोन क्रशर एरिया में गाड़ियों के आने–जाने की वजह से सारी की सारी टूट चुकी हैं। वहां पर कोई भी सड़क ऐसी नहीं रही जिस पर चला जा सके और वहां से अब निकलना भी मुश्किल हो गया है। मेरा अनुरोध है कि उनको दोबारा बनवाया जाये। एक बी०के०डी० रोड को भी बहुत जल्द बनाया जाये। अध्यक्ष महोदय, जो काम हो चुके हैं हम तो उनके बारे में भी बोलते हैं। हम इनैलो के साथियों की तरह नहीं हैं कि हो चुके काम को भी नकार दें। उनको तो आप बोलने का मौका भी देते हैं फिर भी वे गलत बोलते हैं। उनको तो चौटाला जी लिख कर दे देते हैं कि आपने यह बोलना है और वे वही बोलते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आपने इतने काम किये हैं उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। आपके मुंह पर भले ही कुछ न कहता हूं लेकिन पीठ पीछे जरूर मैं आपकी तारीफ करता हूं। आपके लिए जितनी लड़ाई मैं लड़ता

हूं उतनी और कोई नहीं लड़ता होगा। जो बात ठीक है उसको ठीक कहने की हिम्मत भी मेरे अन्दर है और जो बात गलत है उसका विरोध करने की क्षमता भी मैं रखता हूं। आज जिस प्रकार से उन्होंने बी०पी०एल० के बारे में हंगामा किया उनको तो यह करना ही नहीं पड़ता अगर और 6 महीने उनकी सरकार रह जाती। चौटाला साहब तो इन सबको ही बी०पी०एल० में पहुचा देते। आपको भी लिस्ट बनाने की या सर्वे करने की जरूरत नहीं पड़ती सिर्फ एक ही लाईन लिखनी थी कि ये सारे बी०पी०एल० में हैं। आप लोगों के कारण ही लोगों का दोबारा से राजनीतिक लोगों पर विश्वास होना शुरू हुआ है। अब तो लोग इनके फोटोज को भी अलग ही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हमारे पड़ोसी गांव में एक आदमी ने चौटाला का फोटो बिजली के स्विच के पास टांग रखा है। मैंने उससे पूछ लिया कि आप तो इस पार्टी में भी नहीं हो फिर यह फोटो यहां पर क्यों टांग रखा है तो वह आदमी बोला कि बच्चे इससे डरते हैं और बिजली के स्विचों को छेड़ते नहीं है। इसी प्रकार से एक भिखारी ने जिस घर में चौटाला साहब का फोटो लगा हुआ था उस घर से भिक्षा नहीं मांगी। हमने उससे पूछा कि भाई .आपने इस घर को क्यों छोड़ दिया, तो वह बोला कि यहां तो चौटाला की फोटो लगी हुई है। इनको तो चौटाला ने इस लायक छोड़ा ही नहीं होगा कि ये कुछ दे सकें। लेकिन आज की सरकार को मैं बधाई देता हूं कि उसने लोगों के मन में फिर से उम्मीद जगाई है।

वित्त मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): अरजन सिंह जी, कभी–कभी सरकार की बुराई भी कर दिया करो। (हंसी)

श्री अरजन सिंह: सर, अगर बुराई होगी तो मैं अवश्य करूंगा। मैं तो जो भी बात होती है कह देता हूं। मैं तो बुराई ढूंढता हूं अगर कोई बुराई मिलेगी तो मैं जरूर करूंगा। लेकिन आप लोगों का इतना अच्छा बैच है कि आप बधाई के पात्र हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे दो पुल पिछले 5 साल से टूटे पड़े हैं। मेरी आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश है कि उनकी तरफ भी सरकार ध्यान दे।

सिंचाई मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव): आपके दो पुल कौन–कौन से हैं उनके नाम बता दीजिए।

श्री अरजन सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि एक तो बोडिया नहर का पुल है और दूसरा फतेहपुर में झोटा रोड पर है जो सहारनपुर (यू०पी०) से जोड़ता है। यह नहर का पुल है जो पिछले 5 साल से टूटा पड़ा है। साढे तीन साल तो आपकी सरकार को भी हो गये है लेकिन अभी तक उस पुल का काम नहीं हुआ है। इसी प्रकार से जो बोडिया वाला पुल है वह भी 6 महीने से बंद पड़ा है, उस पर तो ट्रैफिक भी ज्यादा नहीं है। स्कूल वाले बच्चों को भी 15–20 किलोमीटर दूर से चक्कर लगा कर आना पड़ता है और अगर किसी को हॉस्पिटल जाना पड़ जाये तो वह भी नहीं जा सकता।

अगर वह पुल बन जाये तो बच्चों को भी सुविधा हो जायेगी और बीमारों को भी परेशानी नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कला अध्यापकों का जो ग्रेड का मामला है उसको भी निपटाने की कोशिश करना। अध्यक्ष महोदय, उन टीचर्ज के ग्रेड का कुछ मामला था।

शिक्षा मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता): वह ठीक कर देंगे।

श्री अरजन सिंह: स्पीकर सर, मेरे हल्के में धाडो पीपली और टाबो माजरा के पुल बनाने के लिए मैंने रिक्वैस्ट की थी। उनके ऐस्टिमेट्स तैयार करके इंजीनियर साहब ने भिजवा दिये थे। (विघन)

श्री अध्यक्ष: अरजन सिंह जी, आपकी जो बात बकाया रह गई है वह आप लिख कर भिजवा दें।

श्री अरजन सिंह: स्पीकर सर, लिखना तो मेरे लिए मुश्किल है मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। हमारे यहां पर फोरैस्ट ने जमीन ऐक्वायर की थी। वह गांव की जमीन है उस जमीन का कुछ हिस्सा फोरैस्ट के दोनों तरफ है लेकिन बीच में से कोई रास्ता नहीं है। 4—5 गांवों की कुछ जमीन परले पार है और कुछ जमीन उरले पार है। यह फोरैस्ट डिपार्टमैंट की मिस्टेक है कि उन्होंने बीच में से रास्ता नहीं दिया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां रास्ता दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं।

श्री नरेश यादव (अटेली): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे ऐप्रोप्रिऐशन बिल पर बोलने के लिए समय दिया है। अध्यक्ष महोदय, 'कृषि, म्युनिसिपल कमेटियों, गांवों और शहरों का जो बजट है, मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। स्पीकर सर, मैंने कल भी इस बारे में बोला था। जो पानी और कृषि क्षेत्र में पिछले तीन साल से दिक्कत महसूस की जा रही है वह दूर की जानी चाहिए। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि नांगल चौधरी और अटेली में बाजरा, गेहूं और सरसों का रिकार्ड तोड़ उत्पादन हुआ है। इन फसलों में बीमारी लग जाती है और जब भी कृषि में किसी और प्रकार की भी परेशानी होती है तो हम कृषि अधिकारियों के पास जाते हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, आप कृषि विश्वविद्यालय में स्टूडैंट्स यूनियन के प्रैजिडैंट भी रहे हैं, आप एक वैज्ञानिक भी रहे हैं और हमारे गुरु भी रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं। पीछे मैं कुछ पढ़ रहा था और मुझे यह पढ़ कर बड़ा अफसोस हुआ। कृषि विश्वविद्यालय, हिसार ने बड़ी प्रोग्रैस की है। अध्यक्ष महोदय, ऐप्रोप्रिऐशन किल पर बोलते हुए सबसे पहले मैं कृषि के बारे में कहना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, आज भी देश के 85% लोग कृषि पर निर्भर हैं और देश में कृषि की अपनी एक पहचान है। वेटरनरी डॉक्टर्ज और एम०बी०बी०एस० डॉक्टर्ज की अपनी

पहचान है लेकिन कृषि विकास अधिकारी को मैडीकल अधिकारी और वेटरनरी डॉक्टर के बराबर पे स्केल दे कर उसको पूरी सुविधाएं प्रदान करने की कृपा करें। जब भी कोई सर्वे करवाते हैं या गांव में कोई तकलीफ होती है तो कृषि अधिकारी को कहा जाता है लेकिन उनकी अपनी कोई पहचान नहीं है, उनका अच्छा पे–स्केल नहीं है, उनके पास व्हीकल नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आज भी हमारा देश कृषि प्रधान देश है और देश के 85% लोग गांवों में रहते हैं। कृषि विकास अधिकारी की कोई पहचान नहीं है वे सात साल का कोर्स करते हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि उनको मैडीकल ऑफिसर के बराबर वेतनमान और सुविधाएं मिलनी चाहिएं। अध्यक्ष महोदय, पशु भी बोल कर अपना दर्द बता सकता है और इंसान भी अपनी बात बता सकता है लेकिन पौधे का दर्द तो खुद पौधे के डॉक्टर को बताना पड़ता है। मेरा आपके माध्यम से कहना है कि उनको पैरेटी में पे–स्केल देकर बजट में प्रावधान किया जाए। स्पीकर सर, इस सरकार ने हर क्षेत्र में बढ़िया कार्य किया है। स्पीकर सर, भाई कर्ण सिंह दलाल टाटा कम्पनी के बारे में एक प्रस्ताव लेकर आए हैं। इस बारे में मेरा सुझाव है कि जमीन तो हमने और कम्पनियों को भी दी है लेकिन टाटा कम्पनी को हरियाणा सरकार की पॉलिसी के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि अगर वह जमीन लेने के लिए हरियाणा में आएंगे तो उन्हें 35 साल तक 30 हजार रुपये प्रति एकड़ एस०ई०जैड० लगाने वाली कम्पनी की तरह देने पड़ेंगे। हमारे इस बारे में जो भी

प्रावधान हैं उन्हें उनकी जानकारी होनी चाहिए। कहीं ऐसा न हो जैसे कि वहां सिंगर में हुआ है, वहां काफी लोग मारे गए हैं, वैसे ही यहां पर भी किसान अपनी मांगे लेकर खड़े न हो जाएं।

अध्यक्ष महोदय, मैंने सदन में पुलिस विभाग और इरीगेशन विभाग के बारे में सवाल दिए थे लेकिन वे लगे नहीं हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए खूब रेड्ज लगाई, कई अधिकारियों को जेलों में डाला गया। इसमें डॉक्टर और दूसरे लोग चाहे वे किसी भी डिपार्टमैंट से संबंधित हों, जेलों में गए हैं लेकिन इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि वे डॉक्टर और अधिकारी जहां से वे सस्पैंड हुए हों वापिस तबादला करवा कर और जेलों से छूट कर उसी विभाग में वापिस आ जाते हैं। मैं इस बारे में एग्जाम्पल दे सकता हूं जैसे कनीना में एक डॉक्टर, नारनौल में एक डॉक्टर दूसरे डिपार्टमैंटस के या एक्साईज एंड टैक्सेएशन के अधिकारी हों। मेरा इस बारे में निवेदन हे कि जब उन डॉक्टरों को और अधिकारियों को रेड डालकर पकड़ते हैं तो उन अधिकारियों को दोबारा से उसी विभाग और उसी पोस्टिंग पर नहीं लगाया जाना चाहिए। सरकार भले ही उनको बहाल कर दे लेकिन उनको वापिस वहीं पर नहीं भेजा जाए क्योंकि जिन लोगों ने उन्हें पकड़वाया होता है जब वे अधिकारी वापिस वहीं पर आ जाते हैं तो उन पकड़वाने वाले लोगों को परेशानी होती है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि सरकार को इस बारे में गौर करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, पी०डब्ल्यू०डी० मिनिस्टर अभी यहां पर नहीं बैठे हुए हैं। हमने उनसे हमारे यहां की आधे किलोमीटर और एक किलोमीटर की छोटी–छोटी 23 सड्कों को बनवाने के लिए मांग की थी। अध्यक्ष महोदय, हमारा अटेली और नांगल चौधरी राजस्थान से जुड़ा हुआ है। राजस्थान ने तो अपने वहां पर सभी सड्कों को बोर्डर तक कम्पलीट कर लिया है लेकिन हमारे यहां पर जो आधे और एक किलोमीटर के सड्कों के टुकड़े हैं, वह नही बने हुए हैं। ये सभी सड़कें हमें राजस्थान से लिंक करने वाली हैं। राजस्थान ने अपनी सभी सड़कें चाहे वे बहरोड तहसील में हो, चाहे कोठपुतली तहसील में हों, पूरी कर ली हैं। अध्यक्ष महोदय, इलैक्शन भी नजदीक हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने राजस्थान से लिंक करने वाली सड्कों के बारे में 2 करोड़ 76 लाख रुपये के एस्टीमेटस सरकार को बनाकर भेजे थे। अगर सरकार यह अमाउंट खर्च कर देगी तो हमारी जो ये 24 के करीब सड़कें हैं वे पूरी हो जाएंगी और हमें राजस्थान से लिंक कर देगी।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे नांगल चौधरी और अटेली में ही पानी के लिए सैंकड़ों बोरिंग की गई हैं। अध्यक्ष महोदय, एक बोरिंग के लिए जितना खर्चा 'आता है .अधिकारियों ने उससे डेढ़ गुणा का बजट बनाया हुआ है। इस बारे में उच्च अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, बोरिंग करते वक्त दो पाईप तो ठीक डाले जाते हैं लेकिन बाकी के पाईप गलत लगा

दिये जाते हैं और कम वेट के लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ समय बाद ही उस बोरिंग की समय अवधि से पहले ही वहां पर प्रोब्लम आने लग जाती है और दोबारा से वहां पर काम करना पड़ता है। इस बारे में भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से हमारे यहां पर म्यूनिसिपल कमेटी बहाल हुई थी लेकिन उसमें किसी भी तरह का बजट का प्रावधान नहीं किया गया था। मैंने इस बारे में पिछले सैशन में माननीय वित्त मंत्री जी से मांग की थी और सदन में बहस भी हुई है। अध्यक्ष महोदय, वाटर रिचार्जिंग के लिए तो इस बार भगवान ने भी मौका दिया। इस बारे में मेरा यह भी कहना है कि जो मौजूदा पानी है उसकी डिस्ट्रिक्टवाइज सही ऐलोकेशन नहीं हुई है। यदि इस बारे में बजट की कमी हो तो और अधिक बजट का प्रोवीजन किया जाये ताकि हमारे इलाके को पानी मिल सके। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि कृषि विकास अधिकारी या खेती से, किसानों से जुड़े हुए जो ए०डी०ओज०, इंस्पैक्टर या दूसरे अधिकारी हैं उनसे थोड़ा काम लिया जाए और उनकी ड्यूटी लगायी जाए। उन्हें पांच दस गांवों की जिम्मेवारी दी जाए और उनसे कहा जाए कि वे वहां पर काम करें। धन्यवाद।

श्रीमती अनिता यादव (साल्हावास): स्पीकर सर, आपने मुझे ऐप्रोप्रिएशन बिल पर बोलने के लिए जो समय दिया हे इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं। हमारी सरकार की जो गतिविधियां अब तक की रही हैं उनकी मैं भूरि–भूरि प्रशंसा करती

हूं क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने जो आज तक कहा नहीं वह भी उन्होंने पूरा करके दिखा दिया है। अध्यक्ष महोदय, एक ही विश्वविद्यालय खुलना था और वह उन्होंने हमारे दक्षिणी हरियाणा को दिया। इसके साथ ही साथ पाली गोठडा में एक सैनिक स्कूल भी हमारी सरकार खोलने जा रही है। इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे लेकिन आज ये दोनों की दोनों चीजें उन्होंने हमें दी हैं। इसके साथ ही साथ मातनहेल में भी एक सैनिक स्कूल खोलने का एक पत्थर लगा हुआ है जिसके लिए मैं हरियाणा सरकार को आपके माध्यम से अर्ज करना चाहूंगी कि जिस तरह से उन्होंने पाली गोठड़ा में सैनिक स्कूल खुलवाकर दिया है उसी तरह से मातनहेल में सैनिक स्कूल खोलने का जल्द से जल अमलीजामा पहनाने में सहयोग करें। इसके लिए उनको सैंटर के कंसर्ड मिनिस्टर से बात करनी चाहिए और मातनहेल में सैनिक स्कूल खोलने का काम शुरू करवाना चाहिए। सर, चूंकि समय की कमी है इसलिए मैं केवल हैल्थ के बारे में विशेष तौर से बहन जी से कहना चाहूंगी कि गांवों में चिकनगुनिया और डेंगू जैसा बुखार बहुत ज्यादा फैल रहा है। हमारे हल्के के जुट्टी गांव में विशेष तौर से इस बुखार का प्रकोप है। हूर घर में एक या दो पेशंटस इस बुखार की चपेट में है। स्पीकर साहब, हमारे विपक्ष के साथी बैठे नहीं है, मैं गुजारिश करना चाहती हूं कि उस समय जब हम कहते थे कि हमारे होस्पीटल में बैडज की संख्या बढ़ा दो या वहां पर डॉक्टर लगा दो तो वे कहते थे कि क्या हम बीमार है। यदि हम बीमार हैं तो वे कहते थे हम डॉक्टर भेज देंगे यानी उस वक्त

हमेशा उल्टा जबाव वे देते थे। लेकिन आज मैं अपनी सरकार को बधाई देना चाहती हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोसली में तीस बैडस का अस्पताल दिया। इसी तरह से आज नाहड का अस्पताल भी अच्छी तरह से चल रहा है लेकिन इसके बारे में एक बात मैं मंत्री महोदया से कहना चाहती हूं कि वहां पर डॉक्टर्ज की कमी है। कोसली की सी०एच०सी० में और नाहड की पी०एच०सी० में केवल एक–एक ही डॉक्टर है। अगर कई बार वह छुट्टी पर चला जाता है तो वहां पर बहुत दिक्कत आ जाती है। वहां की ओ०पी०डी० में पेशंटस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। हमारी सरकार ने फार्मेसिस्टस लगाए हैं। जो फार्मेसिस्टस के खाली पद पड़े हुए थे अब उन्हें भरा गया है। मेरी मंत्री महोदया से गुजारिश है कि अगर डॉक्टर्ज की भर्ती कर ली गयी है तो जिन अस्पताल में डॉक्टर्ज की कमी है वहां पर इनको भेजे जाने चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जमालपुर, नाहड और कोसली के अस्पताल में एक–एक, दो–दो डॉक्टर जरूर भेजे जाने चाहिए। स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री जी ने कई बातों के लिए कहा नहीं फिर भी उन्होंने काम किया है।

श्री अध्यक्षः अनिता जी, आप लिखकर भिजवा देना।

श्रीमती अनिता यादवः स्पीकर साहब, प्रदेश की गली सड़ी कानून व्यवस्था को भी इस सरकार ने ठीक किया है और आज हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। आज हर आदमी की सरकार में पूरी तरह से सुनवाई हो रही है। उठ बिरादरियों को आज सम्मान मिला है इसलिए स्पीकर साहब,

मैं इस बिल का समर्थन करती हूं। धन्यवाद, जय हिन्द। (इस समय सभापतियों की सूची में से एक माननीय सदस्य श्री आनन्द सिंह डांगी पदासीन हुए।)

कृषि मंत्री (सरदार एच०एस० चट्ठा): आनरेबल चेयरमैन सर, अभी अभी सुरजेवाला साहब ने बोलते हुए ऐग्रीकल्चर के बारे में कुछ बातें कहीं। उनके सुझाव, उनकी बातें बहुत ठीक और वाजिब हैं क्योंकि उनको खेतीबाड़ी की बहुत नोलेज है। खेती के मुतल्लक वे बहुत जानते हैं। इस तरह से प्रोफैसर छतर पाल सिंह जी ने भी उनको दोहराया। मैं यह मानकर चलता हूं कि ऐडल्ट्रेशन होती है। मैं उनमें से नहीं हूं जो ये कहूं कि सब सच है, सब ठीक है। एक बात जरूर कहता हूं कि पिछले साल लोगों ने गेहूं को जब ले किया तो 200– 250 एकड़ भूमि में लगी गेहूं की फसल जल गई। उस समय सी०एम० साहब ने आदेश दिये और सारे आफीसर्ज को वहां भेजा। उन कंपनी वालों को पकड़ कर उनका जुर्माना लगाया। किसानों को उनके नुकसान की पेमेन्ट करवाई, कुछ जो रोहतक के रह गए हैं उनके हमने अदालत में केस डलवाए हैं। जिन्होंने ये दवाइयां बेची थी उनके लाइसैंस कैसिल किए हैं। इसी तरह से सीड की बात है। पिछले साल पैडी के सीड में कुछ शिकायतें आई थी। कुछ पैडी बड़ी हो गई, कुछ पैडी छोटी हो गई और क्सका कारण यह निकला कि एक किसान ने प्राइवेट दुकानदार से पैडी ली उस पैडी के चोज की पूरी

प्रोसैस नहीं हुई थी इस वजह से उस दुकानदार का लाइसैंस कैंसिल कर दिया।

श्री सभापतिः इस तरह का एक ही केस था या कई केसिज थे?

सरदार एच०एस० चट्ठाः इस्माइलाबाद का एक ही केस रग उसके बाद जब हमने डिपार्टमैंट के अधिकारियों को मोके पर भेजा तो 3–4 केसिज और सामने आए जिसमें से एक केस ऐसा आया जिन्होंने सीड कार्पोरेशन से बीज लिया था उसकी भी शिकायत हमारे पास आई। हमने सीड कार्पोरेशन के मुलाजिमों को इस बारे में सजा दी और यह भी हिदायत दी कि इसके बाद यदि कोई ऐसी शिकायत आइ तो उनको बक्शा नहीं जाएगा। उनको सस्पैंड भी किया और यहां से बदल भी दिया। इसी तरह से पेस्टीसाइड्स की कुछ और भी शिकायतें थीं। जिन–जिन की शिकायतें थी उनके लाइसैंस कैंसिल कर दिये। कईयों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया है। चेयरमैन साहब, मैं आपके मार्फत हाउस को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार इस बात पर पूरी तरह जांच रख रही है कि किसान को मिलावटी चीज न मिले। जहां तक मिलीबग नामक बीमारी की बात आई थी, तेले की बात आई थी उसका ऐग्रीकल्चर में सिस्टम कुछ और है। तेले का सिस्टम हवा और गर्मी से है। मिलीबग का सिस्टम गर्मी में 20 दिन में बच्चा जवान हो जाता है और तकरीबन 500–600 अंडे देता है फिर वह अंडे जब पैदा होते हैं तब पूरे ऐडल्ट होकर बनते हैं।

मिलीबग में ज्यादातर फीमेल बच्चे होंगे, मेल कम होंगे। मिलिका के मुतल्लिक वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं लेकिन इसका परमानैंट सौल्यूशन कोई नहीं है। जो–जो बातें सुरजेवाला साहब ने यहां पर कहीं हैं उसमें मेन डीजल की मिलावट की बात कही है वह ठीक बात है। मिलावट जहां भी हुई हैं वहां–वहां हमने रेड कराए हैं, सैम्पल लिए हैं, टैस्ट हुए हैं। जिनके सैम्पल टैस्ट होने पर सही नहीं पाये गये हैं उनका ऐसैशियल कमोडिटीज ऐक्ट के तहत चालान हुआ है। माननीय सदस्य ने इच्छा जाहिर की है कि उम्र कैद की सजा कर दो। माननीय सदस्य की और सारी बातों के मैं हक मे हूं लेकिन जो उस कैद वाली बात है इसको रिव्यू करना चाहिए। मैं सी०एम० साहब से प्रार्थना करूंगा कि इस बात को जितना आगे ले जा सकें, ले जाएं। मैं हाउस को यकीन दिलाता हूं कि ऐग्रीकल्चर सैक्टर में किसान के खिलाफ बात नहीं होगी। हमेशा किसान के हित की बात होती रहेगी और ऐसी कोई बात नहीं होगी कि किसान के विरोधी की हम कहीं इमदाद करें। गांव तालों ने भी आजकल दुकानें डाल रखी हैं और वे दवाइयां पी अपने पास रखते हैं, वहा भी ऐसा होता है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि चाहे दुकानदार खो, चाहे किसान हो हम किसी का लिहाज नहीं करेंगे। जो मिलावट करता होगा उसको पकड़कर अंदर करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

वित्त मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह): चेयरमैन सर, हरियाणा एप्रोप्रिएशन बिल नं० 5 पर माननीय सदस्यों ने बड़े विस्तार से चर्चा की है और श्री राम कुमार गौतम जी ने, श्री सुरजेवाला जी के बारे में कृषि संबंध जो कुछ बिन्दु उठाये थे उसका विस्तार से जबाव कृषि मंत्री जी ने दे दिया है। चेयरमैन सर, हमारे कुछ साथियों ने बहुत ही नीतिगत मुद्दे भी उठाये हैं। खासतौर पर श्री सुखबीर सिंह फरमाणा जी जो हमारे माननीय सदस्य हैं उन्होंने कहा कि सोनीपत जिले में जो स्पोर्टस है जिसमें खासतौर पर हॉकी और वॉलीवाल का जिक्र किया। यह सही बात है। मैं पिछले कम से कम 40 साल से यह देख रहा हूं कि सोनीपत का सी०आर०जैड स्कूल देश के चार सबसे बढ़िया स्कूलों में से रहा है जिसकी हॉकी के प्लेयर तैयार करने में भूमिका रही है। कई बार इन्होंने आल इण्डिया जूनियर ट्रॉफी जीती है। फरमाणा जी ने सुसाणा गांव में वालीवाल एकेडैमी बनाने की बात की है। सुसाणा भी एक ऐतिहासिक गांव है जहां वालीवाल के बहुत ही दिग्गज प्लेयर पैदा हुये हें। जिन्होंने देश का और प्रदेश का नाम अन्तर्राष्ट्रीय जगत में भी रोशन किया है। जैसे कल स्पोर्टस मिनिस्टर और मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में विस्तार से चर्चा भी की है। खिलाड़ियों को सम्मानित करने के बाद हाउस ने एक प्रस्ताव भी पारित किया जिन्होंने देश की शान के लिए जो कीर्तिमान स्थापित किए और ओलम्पिक में ईनाम लेकर देश का नाम रोशन किया, देश के नाम के साथ हरियाणा का नाम रोशन हुआ। उस समय उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम बड़ी गम्भीरता से यह सोचेंगे कि

कहां पर स्पोर्ट्स नर्सरी बनायी जाएं और कहां पर एकेडैमी स्थापित की जाएं। मैं यह बात मानता हूं कि ये दोनों स्थान इसके लिए उपयुक्त हैं और स्पोर्ट्स डिपार्टमैंट इन स्थानों को नजरअन्दाज नहीं कर सकता। इसी प्रकार से खरखोदा में आई०एम०टी० बनाने की बात की है। आई०एम०टी० बनाना भी हमारी सरकार की सोच का एक हिस्सा है। सांपला, खरखौदा और समालखा ऐसे शहर हैं जहां पर इण्डस्ट्रियल टाऊनशिप डिवलैप करने की योजना है और उनमें खरखौदा का अहम् स्थान है मैं इसके बारे में समझ सकता हूं कि अगले पांच साल में यह राज्य के महत्वपूर्ण स्थान होंगे जिस प्रकार मानेसर है। इन्होंने इस बात पर ऐतराज किया कि भूमि का अधिक करने के लिए 22–23 लाख रुपये ही मुआवजा दिया जा रहा है जबकि इन्होंने 76 लाख रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने की मांग की है। इसके बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि जिस सोच के साथ हमने आज से तीन साल पहले जमीन का फ्लोर रेट तय किया था, हमारा यह मानना था कि दिल्ली के चारों तरफ जो विकास हो उसमें किसानों की जमीन का अगर सरकारी तौर पर अधिग्रहण होता है तो उसको उचित मुआवजा मिले। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुऐ अध्यक्ष महोदय, मुझे अच्छी तरह से याद है कि पहले किसान दो–तीन लाख रुपये का मुआवजा बढ़वाने के लिए किसान आन्दोलन करते थे उनकी कभी यह सोच का हिस्सा नहीं होता था कि 20 लाख रुपये मिलें। वे यह सोचते थे कि दो या अढाई लाख रुपये ही मिल जायें। यह जो सुपर एक्सप्रैस हाईवे के लिए 14 किलोमीटर की भूमि एक्वायर

की गई थी, उसमें ज्यादातर राई हल्के में किसानों को अढ़ाई–तीन लाख रुपये से ज्यादा मुआवजा नहीं मिला। जिसकी वजह से किसानों ने आन्दोलन किया। उसको देखते हुए हमारी सरकार ने सोच समझ कर यह निर्णय लिया जिसके तहत फ्लोर रेट तय किए गए और जब फ्लोर रेट तय किए गए तो उसी आधार पर सारे राज्य में जमीनों की कीमतें एकदम बढ़ गई किसान को यह लगने लगा कि उसकी जमीन की कीमत 20 लाख रुपये कम है, 22 लाख रुपये कम है, उसको तो एक करोड़ रुपये जमीन का रेट मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का तो पक्षधर हूं कि किसान को जागरूक होना चाहिए और उसको अपने हक के लिए लड़ाई लडनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हमने उसको कोर्ट में जाने से रोका नहीं है। मार्किट रेट के हिसाब से अगर किसान समझता है कि 20 लाख रुपये या 22 लाख रुपये कम है तो वह कोर्ट में जा सकता है। कोर्ट रेट बढ़ा देता है उसके बाद भी अगर उसको वह रेट ठीक नहीं लगता तो वह हाई कोर्ट में जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। सरकार कोर्ट के आदेश के हिसाब से पैसा देगी। किसी जगह पर जमीन एक करोड़ रुपये या 2 करोड़ रुपये के हिसाब से खरीदी गई है या बेची गई है तो उसको मार्किट रेट नहीं माना जा सकता लेकिन यह बात सही है कि मार्किट रेट ज्यादा है तो किसान का हक बनता है कि उसको उसका हक मिले। हम मानते हैं कि उसको कोर्ट में जाना चाहिए हम उसका बढ़ा हुआ मुआवजा देंगे। उसको कोर्ट में जाना भी चाहिए क्योंकि अपने हक के लिए सभी कोर्ट में जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमने महसूस किया है कि 100 किलोमीटर दिल्ली के चारों तरफ हरियाणा की जो जमीन है उसकी कीमत दो लाख, 4 लाख या 5 लाख रुपये प्रति एकड़ नही होनी चाहिए बल्कि उसका रेट 20 लाख, 25 लाख या 50 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से होना चाहिए और इसीलिए हमने फ्लोर रेट तय किए और इस बात की प्रशंसा इनको जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा रामकुमार गौतम जी ने पब्लिक हैल्थ के बारे में बोलते हुए पाइप लाइंस के बारे में कहा। अध्यक्ष महोदय, पिछले दो सालों से पाइपों की खरीद के बारे में हमें काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, आप सुनकर हैरान होंगे कि कुछ किस्म के पाइपस ऐसे हैं जिनको सारे देश में केवल दो कम्पनियां ही बनाती है। शुरू में तो हमें पाइपस खरीदने में कठिनाई आई थी लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं है। जिन गांवों में भी पाइपस बिछाने में देरी हुई है हम वहां जल्दी पाइप बिछाकर उनको वाटर वर्क्स से जोड़्ने का प्रयास करेंगे ताकि जिन गांवों में पानी की पूरी सप्लाई नहीं हो सकी वहां पानी पूरा पहुंच सके। अध्यक्ष महोदय, डॉ० शिव शंकर भारद्वाज जी ने भी अपने विधान सभा क्षेत्र के लिए कुछ मांगें रखी है। उन्होंने कुछ नए वाटर वर्क्स बनाने की मांग की है और कुछ वाटर वर्क्स के काम में शिथिलता के बारे में उन्होंने कहा। कुछ वाटर वर्क्स के बारे में इन्होंने कहा है कि 3–4 सालों से उन पर काम चल रहा है लेकिन काम कम्पलीट नहीं हुआ। हम इस महकमे के मंत्री जी के ध्यान में ये बातें ला देंगे। जहां–जहां पर भी काम धीमी गति से चल रहे हैं उनको स्पीड अप करेंगे।

इन्होंने गवर्नमैंट स्कूलों के बारे में और रोड कंस्ट्रक्शन की भी बात रखी है इस बारे में मैं इनको बताना चाहूंगा कि सम्बन्धित विभाग के मंत्री यहां बैठे हुए थे उन्होंने इनकी बात को नोट कर लिया है। प्रो० छत्तर पाल सिंह जी ने एक बात कही है, उसके बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा। इन्होंने ओर्गेनिक कल्टीवेशन के बारे में कहा। आज हरियाणा का किसान अगर इस बात को समझ जाए कि इस ओर्गेनिक कल्टीवेशन से वह मालामाल हो सकता है तो इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं है। मैं खुद देखता हूं कि पिछले 20 साल पहले हमारे गेहूं का भाव 300 रुपये से 400 रुपये के बीच में था। यह आर्गेनिक कल्टीवेशन की बात तो अलग है। एम०पी० में जो रेन फैड होता है वह फरवरी में दिल्ली की मार्किट में आता है तब उसका भाव 500 रुपये या 400 रुपये प्रति क्विंटल होता है और वह 1100 रुपये या 1200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकता है यानि 3 गुना ज्यादा रेट पर बिकता है। पिछले दिनों रबी क्रोप के बारे में जब मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई तब यह बात सामने आई थी कि ओर्गेनिक कल्टीवेशन तो ठीक है लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या सर्टीफिकेशन की है कि किसान की फसल को यह सर्‌टीफाई किस प्रकार किया जाये कि फसल आर्गेनिक कल्टीवेशन से पैदा हुई है। यह इसमें सबसे बड़ी दुविधा है। उस समय मुख्यमंत्री जी का और मीटिंग में उपस्थित सभी सदस्यों का यही व्यू था कि ऐसा मैकेनिजम सरकारी तौर पर स्थापित किया जाये ताकि किसानों की फसल को सर्‌टीफाई किया जा सके और सर्‌टीफिकेशन के बाद

किसान अपनी फसल को मार्केट में दुगने, तिगने या चौगुने भाव पर बेच सकें। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का फैसला हमने लिया हुआ है। ऐसा करने से किसान की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार होगा।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से वाटर मैनेजमैंट के बारे में भी माननीय सदस्यों ने जिक्र किया है। यह सही बात है कि चौनल्ज की रिमोडलिग होनी चाहिए और सभी टेल्ज तक पानी पहुंचना चाहिए। हमारे प्रो० छत्तर पाल जी के हल्के में बहुत से ऐसे गांव हैं और बहुत से ऐसे चौनल्ज हैं जिनकी टेल पर पानी नहीं पहुंच रहा है। लेकिन हम इनके यहां हर टेल पर पानी पहुंचाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त चौनल्ज की रिमाडलिग के लिए उपयुक्त धन राशि बहुत जरूरी है। चाहे रिमाडलिग का काम काडा करवाये या सिंचाई विभाग करवाये, हम रिमाडलिग के लिए उचित धन राशि का प्रबंध करेंगे क्योंकि आज से एक साल पहले जब हमने अपनी सरकार के दो साल पूरे किए थे तब हमने सिरसा की रैली में यह घोषणा की थी कि अगले दो साल में हम चौनल्ज की रिमाडलिग का काम पूरा कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, वह घोषणा हमारे ध्यान में है, उसके लिए हम पर्याप्त धन राशि जुटायेगे।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान (पाई): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी चौनल्ज के बारे में बात कर रहे हैं। इस बारे में मैं मंत्री जी को एक बात कहना चाहूंगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री

जी ने घोषणा की थी कि हम सारे चौनल्ज को पक्का करवा देंगे। अध्यक्ष महोदय, पहले जो चौनल्ज बने हुए हैं वे डिजाईन में साढ़े चार इंच के बने हुए हैं जो एक साल में टूट जाते हैं। यदि मंत्री जी इनका डिजाईन 9 इंच का करके पक्का करवा देंगे तो ये दस साल तक चलेंगे। यह बात मैं इंजीनियरिंग प्वायंट ऑफ व्यू से दावे के साथ कहता हूं। साढ़े चार इंच के जो नाले होते हैं उनमें डगर का पैर लगने से भी वे टूट जाते हैं या किसान एक कस्सी मारकर जान–बूझकर भी तोड़ देते हैं लेकिन 9 इंच के नाले को न तो किसान तोडेंगे और डगर आदि के पैर लगने से भी नहीं टूटेंगे। क्या मंत्री जी साढ़े चार ईंच के नालों को 9 ईंच का बनाने पर विचार करेंगे?

श्री वीरेन्द्र सिंह अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य ने बिल्कुल ठीक बात कही है और बहुत से चौनल्ज को हमने पिछले सालों में साढ़े चार ईच से 9 ईंच में कनवर्ट भी किया है। अध्यक्ष महोदय, जब भी रिमाडलिंग की बात होती है तो किसान भी यही चाहते हैँ कि चौनल्ज को साढ़े चार इंच से बढ़ाकर 9 ईंच के कर दिये जायें लेकिन इसमें डबल खर्चा आता है। इसीलिए हमारे को फंडज की दिक्कत आई थी लेकिन हम इस बात को सही मानते हैं कि अगर चौनल्ज 9 इंच के होंगे तो उनकी लाईफ भी लम्बी होगी और उनमें तोड़फोड़ भी कम होगी तथा किसान भी उनको नहीं तोड़ेंगे। यह बात हमारे ध्यान में है और इस पर हमने काम भी किया है।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा भाई नरेश यादव जी ने कहा है कि ए०डी०ओज० की पहचान नहीं रही है। उनको एम०बी०बी०एस० के बराबर या वैटनरी डाक्टर्ज के बराबर ग्रेड दिए जायें। अध्यक्ष महोदय, आप भी एग्रीकल्चर के ग्रेजुएट हैं, डाक्टरेट हैं। मैं तो कई बार यह बात दोहरा चुका हूं कि यह बड़ा गंभीर विषय है कि आज एग्रीकल्चर की हमारी यूनिवर्सिटीज में, केवल एच०ए०यू० की बात नहीं है बल्कि देश भर की यूनिवर्सिटीज में जो नये अनुसंधान और रिसर्च होने चाहिए जिनसे डिवैल्पमैंट हो सके, वे नहीं हो रहे हैं। यही कारण है कि हम आहिस्ता–आहिस्ता इसमें पिछड़ रहे हैं। कई बीज तो ऐसे हैं जो पिछले बीस साल से नहीं बदले गये हैं और उत्पादन भी उतने का उतना ही है। सबको मालूम है कि आज जमीन घटी है और थोड़ी–थोड़ी रह गई है। जमीन को ध्यान में रखते हुए क्या हम ऐसे बीजों का इजाद कर सकते हैं जिनसे पहले 15–20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से वीहट दस उत्पादन होता था और वह अब बढ़कर 40–45 या 50 क्विंटल प्रति एकड़ होने लगे ताकि किसानों को तिगुना लाभ हो सके। इस प्रकार से जो जैनेटिक बैरियर हैं उनको तोड्ने की आवश्यकता है। अनुसंधान करके जैनेटिक बैरियर तोड़े जा सकते हैं। Our entire work force of the scientists of this country, who are to innovate new things, should put their heads together and that is the requirement of the time. लेकिन पिछले दिनों में इस काम में शिथिलता आई है। मैंने बजट सैशन में भी यह बात कही थी और आज भी मैं यह कहता हूं कि अगर इस बारे में

किसी यूनिवर्सिटी को पैसे की जरूरत होगी तो हम किसी किस्म का बैरियर नहीं रखेंगे। जो कोई भी इस बारे में अनुसंधान करना चाहेगा हम उनको पूरा योगदान देंगे। खूब पैसा अनुसंधान करने वालों को देंगे। आज हमें नये अनुसंधान करने चाहिए। हम बायो–टेक्नोलोजी के माध्यम से जैनेटिक बैरियरज को तोड़ सकते हैं जिससे किसान की प्रोडक्टिविटी हाई से तीन गुणा तक बढ़ेगी। इतना ही नहीं कई जैनेटिक साइंटिस्ट ने तो यहां तक कहा है कि अगर बायो–टेक्नोलोजी का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाये तो प्रति एकड़ से 200 क्विंटल तक गेहूं पैदा की जा सकती है।

श्री नरेश यादवः स्पीकर सर, मेरा प्यांवट ऑफ ऑर्डर है। स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज देश और विदेशों में जो भी बड़ी–बड़ी कम्पनियां बीज बनाती हैं उनमें जो साईंटिस्ट हैं उनमें से अधिकतर हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हिसार में ही पढ़े हुए हैं। आज उन्हीं का बाजरे का बीज आ रहा है। बाजरे के अतिरिक्त दूसरे बीज भी आ रहे हैं एच०ए०यू० में पड़े वैज्ञानिक आज दुनिया भर में हाई लैवल पर हैं। इसका कारण यह रहा होगा कि उन्हें यहां बहुत कम फैसीलटीज मिलती होंगी जिससे वे अमेरिका, इंग्लैंड, आस्ट्रेलिया जैसे दूसरे देशों में चले गये। हैदराबाद में भी जो बीज की कम्पनियां हैं उनके जो हैड हैं वे भी एच०ए०यू० के वैमानिक हैं।

प्रो० छत्तर पाल सिंहः स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। स्पीकर सर, इसमें कोई दो राय नहीं कि एच०ए०यू० के

रिसर्च ऑफिसर्ज, साईंटिस्ट और डॉक्टर्ज हैं उनका कैम्पस लैवल पर रिसर्च वर्क बहुत अच्छा है और फार्मर्ज को बहुत अच्छे बेनीफिट्स उनसे मिले हैं। लेकिन जहां तक ए०डी०ओज० की बात आई है मैं उनके बारे में कहना चाहूंगा कि ए०डी०ओज० की अब तक की जो वर्किंग वैल्युएशन है उनकी अकाऊंटिबिलटी अगर आप देखेंगे तो आप पायेंगे कि फार्मर्ज के हित में उनका कोई विशेष कंट्रीब्यूशन नहीं पाया गया है। अगर एग्रीकल्चर क्राप्स के बारे में आप बात करें तो फार्मर्ज उनके मुकाबले में कहीं ज्यादा एक्सपर्ट दिखाई देते हैं। स्पीकर सर, मेरा आपके माध्यम से कृषि मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे इस बात को देखें कि ए०डी०ओज० की अकाऊटिबिलटी तय हो। श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर सर, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि ए०डीभ्योज० की आज जो भूमिका है जैसा कि माननीय सदस्य प्रो० छत्तर पाल सिंह जी ने कहा उसकी भूमिका नगण्य है। आज उसका काम यह भी है कि जो मार्किट फोर्सिज हैं उनका जो लेटेस्ट डाटा है उसके बारे में भी वह किसान को समझाये कि जो प्रोडयूस किया है उसको इस टाईम पर बेचेंगे तो इतना लाभ होगा। किसी प्रोडयूस की एक समय में अमेरिका, ब्रिटेन और आस्ट्रेलिया में क्या कीमत है। इसीलिए हमने यह फैसला किया था कि कि ए०डी०ओज० हैं अगर एम०बी०ए० की क्वालिफिकेशन भी उनकी रखी जाये तो वे किसानों के लिए ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि हम एम०बी०बी०एस० डॉक्टर्ज के बराबर उनका ग्रेड कर दें। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि ग्रेड की बात नहीं है अगर वे

अच्छे रिजल्ट दें तो हम उनका ग्रेड डॉक्टरों से भी ज्यादा कर देंगे। इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आपने उनके पे–स्केल की बात कही है। मैं यह कहूंगा कि सिक्सथ पे कमीशन की रिकमण्डेशन्ज 01 सितम्बर, 2009 से भारत सरकार में लागू हो गई हैं। हमारे पास भी उसी प्रकार से वे आयेंगी और जब हम उनको किसी ग्रेड में फिट करेंगे तो उसके लिए एक कमेटी बनेगी उसमें जाकर वे अपनी बात कह सकते हैं कि हमें यह ग्रेड मिलना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए चीफ सैक्रेटरी की अध्यक्षता में अभी भी एक कमेटी बनी हुई है। यह तो पे–फिक्शेसन से पहले की बात है। उसके बाद भी अगर उनको किसी बात पर ऐतराज है और वे समझते हैं कि जिसके वे पात्र थे वह स्केल उनको नहीं मिला तो वे एनामली कमेटी में रिप्रेजैंट कर सकते हैं। स्पीकर सर, इससे पहले हमने एक नीतिगत फैसला लिया हुआ है कि जब तक सिक्सथ पे कमीशन लागू नहीं हो जायेगा तब तक हम इस बारे में कोई भी फैसला नहीं करेंगे।

श्री राधे श्याम शर्मा (नारनौल): अध्यक्ष महोदय, मेरा बाइट ऑफ ऑर्डर यह है कि माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि अगर हमारे ए०डी०ओज० किसानों को जागरूक करें तो हम 200 क्विंटल तक गेहूं पैदा कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ऐसी कौन–सी रुकावट है जिसके कारण यह काम नहीं हो रहा है? क्या मंत्री जी उस रुकावट को दूर करने की कोशिश करेंगे?

श्री वीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं। लेकिन इसके लिए पिछले 5 साल तक जो सरकार थी वह भी जिम्मेदार है। उन्होंने ए०डी०ओज० की भर्ती नहीं की। उनको तो लोग दोष नहीं देते, कहते हैं कि वह तो किसानों की सरकार थी। हमने उनका रास्ता खोला और 10– 12 सालों से जो बी०एस०सी० एग्रीकल्चर या पी०एच०डी० करके बैठ गये थे उनको आज सबको नौकरी मिली है और यह प्रयास भी हमारी सरकार से शुरू हुआ है। मैं ही यह बात नहीं कहता, यह सदन ही नहीं कहता बल्कि आज यह आम किसान के मन में है कि ये जो ए०डी०ओज० बने हैं ये बिलकुल ही काम नहीं करते वे हमारे किसी काम नहीं आते। चाहे कोई माने या न माने लेकिन ये लैब टू लैंड जो बनाई गई थी उसके प्रयास किये गये थे और उनके रिजल्ट आये। लेकिन जब से यह लिब्रैलाईजेशन का युग आया है तब से टैक्नीकल तौर पर, वाणिज्यिक तौर पर और कृषि के तौर पर इन तीनों तौर पर जब तक ए०डी०ओ० किसानों को जागरूक नहीं करेगा, मैं समझता हूं कि he is not fulfilling his responsibility as Agriculture Development Officers.

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर यह है कि जो चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी कह रहे थे वह बड़ी सोचने वाली बात है और अगर विभाग के नियम इजाजत देते हैं तो इन ए०डी०ओज० को विभाग से निकाल कर अगर कृषि विज्ञान केन्द्रों के मातहत कर दिया जाये तो ये किसानों का ज्यादा भला कर सकते हैं क्योंकि कृषि विज्ञान केन्द्र जो हर जिले के अन्दर हैं

वहां नई–नई खेती के बारे में लोगों को जानकारी दी जाती है। हमारे ए०डी०ओज० डिपार्टमैंट के अन्दर काम करते हैं। कृषि विज्ञान केन्द्र जो हमारी कृषि विश्वविद्यालय का अभिन्न अंग हैं उसके साथ उनको बैठा दिया जाये तो ये किसानों की ज्यादा मदद कर सकते हैं। इस प्रकार से वे लोगों की ज्यादा मदद कर सकते हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंहः सर, अभी अरजन सिंह जी ने अपने विचार रखे हैं और उन्होंने हमारी सरकार को प्रैफैक्ट सरकार का खिताब दे दिया है इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। इन्होंने एक बात आर्ट एण्ड क्राफ्ट अध्यापकों के ग्रेड के बारे में और कही है। इस बारे में मेरा कहना है कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद भी अगर वे संतुष्ट न हों तो बाद में वे हमारे पास आ सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि एप्रोप्रिएशन बिल को ध्वनि मत से पास किया जाये।

Mr. Speaker: Question is

That the Haryana Appropriation (No. 3) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the B **ill** clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker Question is—

That Clause 3 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker: Question is—

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried

Clause 1

Mr. Speaker: Question is -

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is -

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Finance Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Shri Birender Singh): Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion Moved -

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा म्यूनिसिप्लिटी पब्लिक डिसक्लोजर बिल, 2009

Mr. Speaker: Now, the Urban Development Minister will introduce the Haryana Municipality Public Disclosure Bill, 2008 and will move the motion for its consideration.

Urban Development Minister (Shri A.C. Chaudhary): Sir,1 beg to introduce the Haryana Municipality Public Disclosure Bill, 2008.

Sir, I also beg to move -

That the Haryana Municipality Public Disclosure Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved -

That the Haryana Municipality Public Disclosure Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is -

That the Haryana Municipality Public Disclosure Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Sub-Clause 2 of Clause 1

Mr. Speaker: Question is—

That Sub Clause 2 of Clause 1 stands part of the Bil.

The motion was carried.

Clauses 2 to 7

Mr. Speaker: Question is -

That Clauses 2 to 7 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause 1 of Clause 1

Mr. Speaker: Question is -

That Sub-Clause 1 of Clause 1 stands part of the Bill

The motion was carried

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is —

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Urban Development Minister will move that the Bill be passed.

Urban Development Minister (Shri A.C. Chaudhary): Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is--

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा फायर सर्विसिज बिल, 2008

Mr. Speaker: Now, the Urban Development Minister will introduce the Haryana Fire Services Bill, 2008 and will also move the motion for its consideration.

Urban Development Minister (Shri A.C. Chaudhary): Sir, **I** seek your permission that because of some technical lacuna, I propose to withdraw this Bill for carrying out necessary correction.

Mr. Speaker: Is it the sense of the House that the permission to withdraw this Bill be granted?

Voices: Yes, yes.

Mr. Speaker: Keeping in view the sense of the House, the permission to withdraw the Bill is granted.

The Bill was withdrawn.

दि हरियाणा म्यूनसिपल कर्पोरेशन (अमैण्डमैंट) बिल, 2008

Mr. Speaker: Now, the Urban Development Minister will introduce the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2008 and will also move the motion for its consideration.

Urban Development Minister (Shri A.C. Chaudhary): Sir, I beg to introduce the Haryana Municipal (Amendment) Bill, 2008.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री धर्मवीर (गुड़गांव): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को मुबारिकबाद देना चाहता हूं कि जो अमैंडमैंट हुई है यह बहुत ही जरूरी थी। इन्होंने कहा है कि इलैक्शन कमीशन ने हमें लिखा है कि within six month इलैक्शन हो जाने चाहिएं और तीन महीने तक हमें हर हाल में डिलिमिटेशन से वार्ड की हदबन्दी मिल जानी चाहिए। स्पीकर सर, गुड़गांव कारपोरेशन बने हुए तीन महीने हो गये हैं। क्या यह गारन्टी है कि एक साल के अन्दर यह डिलिमिटेशन करके इलैक्शन करवा पाएंगे या इसमें एक और अमैंडमैंट कर सकते हैं कि अगर एक साल में यह न हो पाए तो उसको छः महीने और बढ़ा दिया जाएगा, यह एक बात है और दूसरी बात यह है कि डिलिमिटेशन होनी है वह किससे करवाएंगे ताकि यह काम वक्त पर पूरा हो सके। अगर इसको प्राईवेट ऐजैंसी से करवाएंगे तो यह हो पाएगा। अगर आप यह टीचरों या पटवारियों के जिम्मे लगाएंगे तो यह दो साल तक नहीं हो सक्ता है। इस बारे मैं फैसला आपने ही करना है।

श्री ए०सी० चौधरी: स्पीकर सर ये इन्स्ट्रक्शंज नहीं हैं, ये म्यूनिसिपल कारपोरेशन एक्ट में सब–क्लॉज 4(4) में प्रोवीजन है। इसमें यह है कि कोई भी सीट खाली हो या कोई वैकेंसी हो तो उसको विद–इन 6 मन्थ में भरना होता है। अध्यक्ष महोदय, यह कारपोरेशन नई बनी है इसलिए इसकी वार्डचंदी का कार्य नए सिरे

से करना पड़ेगा। वार्डबंदी के साथ उसमें जो रिजर्वेशन की क्लाज है उसके मुताबिक सारे आईडैंटिफाई करने होंगे और इस सारे प्रोसैस को नए सिरे से बाऊंडरी से लेकर के अन्दर तक की इन्टरनल सैटिंग तक करने कें लिए टाईम की जरूरत है। डिपार्टमैंट ने इस बोर में लिखकर दिया हुआ है कि इन तीन महीनों के प्रैस्क्राइबड टाईम में नहीं कर पाएंगे। अध्यक्ष महोदय, यह कारपोरेशन 2 जून को बनी है और बाकी प्रोसैस में भी दो महीने का समय निकल गया है। मैं समझता हूं कि उनकी जो रिक्वैस्ट है वह जैनुअन है और उनकी जैनुअन डिफिकल्टी को देखते हुए हमें हाउस के सामने यह अमैंडमैंट रखी है। जहां तक दूसरा सवाल है कि हम यह किस से करवाएंगे। यह बिल पास होने के बाद हम अपने शैडयूल के अन्दर ही करवाने का प्रयास करते हुए ये सारी चीजें देख लेंगे और जो भी वाजिब होगा उसको भी कन्सल्ट कर लेंगे। इसके अलावा और भी ऑनरेबल मैम्बर्ज जो भी सलाह देंगें उनको हम प्राथमिकता देते हुए कंसल्ट करेंगे।

श्री धर्मवीर गाबाः अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो एक साल की मियाद रखकर इसको बढ़ा रहे हैं, क्या ये इसमें ऐसा प्रोवीजन करेंगे कि अगर उस साल तक भी यह नहीं हुआ तो 6 महीने और बढा देंगे?

श्री ए०सी० चौधरीः स्पीकर सर, यह तो कुदरती बात है कि समय बढ़ेगा। वैसे तो ऐसी नौबत नहीं आएगी लेकिन God

forbids, अगर सारी वार्डबंदी होती है तो बहुत सारी बातों में कुरैक्शन लानी पड़ती है उसमें क्या दिक्कत है। (विघ्न) अगर जरूरत पड़ेगी तो परमिशन तो हाउस से ही लेनी है, ले लेंगे।

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल): स्पीकर सर, ये जो बिल लाए हैं इसको जरूर इजाजत दी जानी चाहिए और यह वाजिब बात भी है लेकिन इसके साथ मैं आपकी मार्फत मुख्यमंत्री जी से और मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो इन्होंने गुड़गांव की म्यूनिसिपल कारपोरेशन एक्ट के तहत व्यवस्था दी है यह बहुत अच्छा काम किया है। यह हमारी संवैधानिक जिम्मेवारी है क्योंकि 74वी अमैंडमैंट आ चुकी है और सरकार को म्यूनिसिपल बॉडिज को यह व्यवस्थाएं सौंपनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपके मार्फत मुख्यमंत्री जी से और मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि गुड़गांव के हालात को देखते हुए वहां पर म्यूनिसिपल कारपोरेशन की जो मौजूदा कई क्लाजिज हैं, उनका स्कोप या तो आपको बढ़ाना पड़ेगा या नए क्लाजिज उसमें आपको जोड्ने पड़ेंगे। आज गुड़गांव हरियाणा का ही नहीं बल्कि देश का प्रमुख शहर बन चुका है। आज दुनिया की निगाहें वहां पर लगी हुई हैं। मल्टी नैशनल कम्पनीज और दुनिया के जिस भी तरह के लोग हैं वे वहां पर बसे हुए हैं या बसने जा रहे हैं उसके लिए गुड़गांव के अन्दर म्यूनिसिपल कारर्पोरेशन के प्रोवीजन के अलावा भी अगर मुख्यमंत्री ठीक समझे तो वे एक और ऑटोनोमस व्यवस्था को अन्जाम दें और उसको ये अपनी देख–रेख में चलाएं और वहां पर लोगों को

राहत दें। इस वजह से वहां की व्यवस्था ठीक रह सकेगी, वहां की कानून व्यवस्था ठीक रह सकेगी और वहां पर हम और अच्छी सुविधाएं दे सकेंगे। इस बारे में इनकी विचार करना चाहिए।

श्री ए०सी० चौधरी: स्पीकर सर, आनरेबल मैम्बर कर्ण सिंह दलाल जी ने जो कम्पैक्शन की बात कहीं है, मैं इनको यह कहना चाहता हूं कि म्यूनिसिपल कारपोरेशन सिर्फ सिविक बाई। की ड्यूटी परफार्म करता है। पुलिस का मामला सैप्रेट है और बाकी की बात देश के संविधान में क्लीयर है कि अगर संविधान में अमैंडमैंट की जरूरत है तो वक्त–वक्त में उसमें अमैंडमैंट की जा सकती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आने वाले वक्त की क्या जरूरत है तो उस वक्त में एग्जामिन करने की बात हो सकती है। As on date तो इस प्रावधान को कर दिया जाए ताकि हम प्रोसैस पर इस गाड़ी को तेजी से निकाल सकें।

Mr. Speaker: Question is -

That the Haryana Municipality Corporation (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause - 2

Mr. Speaker: Question is -

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause - I

Mr. Speaker: Question is—That Clause I stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is -

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is -

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carded.

Mr. Speaker: Now, the Urban Development Minister will move that the Bill be passed.

Urban Development Minister (Shri A.C. C haudhary): Sir, I beg to move -

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved -

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is -

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा टाउन इम्प्रूवमैंट बिल, 2008

Mr. Speaker: Now, the Urban Development Minister will intordUce the Haryana Town Improvement Bill, 2008 and wilI also move the motion for its consideration.

Urban Development Minister (Shri A.C. Chaudhary): Sir, I beg to introduce the Haryana Town Improvement Bill, 2008.

Sir, I also beg to move -

That the Haryana Town Improvement Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved -

That the Haryana Town Improvement Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is -

That the Haryana Town Improvement Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Sub-Clause 2 of Clause 1

Mr. Speaker: Question is -

That Sub-Clause 2 of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause 3 of Clause 1

Mr. Speaker: Question is—

That Sub-Clause 3 of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 2 to 106

Mr. Speaker: Question is -

That Clauses 2 to 106 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause 1 of Clause 1

Mr. Speaker: Question is -

That Sub-Clause 1 of Clause i stands part of the Bill..

The motion was carried

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is -

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is —

That Title be the Title of the Bill

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Urban Development Minister will move that the Bill be passed.

Urban Development Minister (Shri A.C. Ch audhary): Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Bill be passed.

श्री धर्मबीर (गुडगांव): स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से एक रिक्वैस्ट करना चाहता हूं। मंत्री जी इस बिल के माध्यम से इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट के बारे में अमैंडमैंट लेकर आए हैं। क्या मंत्री जी इनको पावर देंगे ताकि शहरों के अंदर मशरूम ग्रोथ रुक जाए और सिस्टेमैटिकली इम्प्रूवमैंट वहां हो जाए? इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट को पावर देने से शहरों में सिस्टेमैटिकली इम्प्रूवमैंट होगी और शहरों की मशरूम ग्रोथ रुकेगी। इसके अलावा मेरी एक रिक्वैस्ट यह भी है कि इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट को आप कम से कम इतना तो बना दो कि

उसको पूरा स्टाफ मिले। आज इसका चेयरमैन तो है लेकिन स्टाफ नहीं है और जब स्टाफ ही नहीं है तो फिर शहरों की तरक्की कैसे होगी, कैसे इम्प्रूवमैंट होगी? मंत्री जी, आप इनको पावर दें क्योंकि जब तक आप इनको पावर नहीं देंगे तब तक बात नहीं बनेगी।

श्री ए०सी० चौधरी: स्पीकर सर, चेयरमैन और स्टाफ की सैपरेट सैंकटिटी है। इसमें कोई लम्बी चौड़ी बात नहीं थी। पंजाब टाऊन इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट, 1222 को ऐडाप्ट करके हम अब तक अपना काम कर रहे थे लेकिन जिस तरह से सरकार डिवैल्पमैंट के काम कर रही हैं उन डिवैल्पमैंट के काम को पूरी तरह से कंट्रोल में करने के लिए और आर्गेनाइजेशन के स्टेटस को बढ़ाने के लिए हमने इसको अपना नाम देने का काम किया है। जहां तक पावर देने की बात है, सैपरेट सैंकटिटी के तौर पर उसकी रिकोगनिशन है और वह काम कर रहा है। जहां जरूरत पड़ेगी वहां स्टेट की गाइडैंस ले लेंगे।

यह पंजाब का 1922 का ऐक्ट था और उस ऐक्ट के तहत ये ट्रस्ट काम कर रहे हैं। अब इसे हरियाणा का 2009 का ऐक्ट बनाकर हरियाणा की रिक्वायरमैंट के मुताबिक इसे ऐडजस्ट किया है, इसे बढ़ाया है, कम नहीं किया है।

श्री धर्मवीर: आप क्या बात करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय 1022 की बात कर रहे हैं जब कि आज वर्ष 2008

चल रहा है, पुराने ऐक्ट पर कब तक चलेंगे तब से अब रिक्वायरमैंट्स कितनी बढ़ गई हैं?

श्री ए०सी० चौधरी: सर, सीधी सी बात है, वही तो बदल रहे हैं और इस आशय के साथ बदल रहे हैं कि जो कमियां रह गई हैं उन कमियों को खत्म करके इसे हमने अपनी स्टेट का नाम दिया है ताकि जिस स्पीड के साथ हम डिवैल्पमैंट के काम कर रहे हैं उसी के हिसाब से उनको पॉवर्ज दे दी जाएं और पंजाब के नाम से उसमें अमैंडमैंट न करनी पड़े।

Mr. Speaker: Question is —

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि हरियाण म्यूनिसिपिल सिटीजन्ज पार्टिसिपेशन बिल, 2008

Mr. Speaker: Now the Urban Development Minister will introduce the Haryana Municipal Citizens Participation Bill, 2008 and will move for its consideration.

Urban Development Minister (Shri A.C. Chaudhary): Sir, I beg to introduce the Haryana Municipal Citizens Participation Bill, 2008.

Sir, **I** also beg to move—

That the Haryana Municipal Citizens Participation Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Haryana Municipal Citizens Participation Bill be taken into consideration at once.

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को और मंत्री जी को मुबारिकबाद देना चाहता हूं कि जो एक आधुनिक सोच दुनिया के अंदर बनती जा रही है उसका हिस्सा हरियाणा भी बनने लगा है। यह जो नया बिल लेकर आ रहे हैं, इससे यकीनन तौर पर म्यूनिसिपल एरियाज में रह रहे आम आदमी को फायदा होगा क्योंकि जो चुनाव म्यूनिसिपल बॉडीज में होते थे उसमें तमाम काम चुने हुए नुमाइंदों तक सीमित हुआ करता था। इस बिल को लाकर एरिया, वार्ड और कमेटी की निश्चितता तय की है, कारगुजारी निश्चित की है, यह प्रशंसनीय कार्य है। मैं समझता हूं कि शायद हरियाणा उत्तर भारत में ऐसा पहला राज्य होने जा रहा है जो इस तरह की सुविधायें देने जा रहा है। इस बिल के बारे में मेरा एक निवेदन है कि इनकी कार्यप्रणाली पर ठीक तरीके से निगरानी रखने के लिए जो एरिया कमेटी है उसमें यदि मान लीजिए कि म्यूनिसिपल बॉडी ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है तो उस एरिया कमेटी को वहां के नुमाइंदों को वापस बुलाने का अधिकार होना चाहिए। उससे एक कदम राइट टू रीकाल की तरफ भी बढ़ेगा. और अगर एरिया कमेटी यह समझती है कि उनके नगर के चुने हुए प्रतिनिधि ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं और वे लोग उनकी सिफारिश करें तो उनको उनके पद से हटा देना चाहिए। इसके अंदर माननीय मंत्री जी यदि ठीक समझें तो इस बिल में या

आने वाले समय में ओम्बड्समैन की नियुक्ति भी अगला कदम होगी, यह एक बहुत बड़ी राहत होगी, इसके लिए मैं इनकी सराहना करता हूं। यह बिल हरियाणा के हित में लेकर आए हैं। म्यूनिसिपल बॉडीज में इसका फायदा होगा।

श्री ए०सी० चौधरी: अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकारों ने शहरों के विकास के लिए क्या कुछ काम किए, यह बात किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज चाहें सैंट्रल गवर्नमैंट की एक–एक स्कीम को चाहे जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन है, उसके अलावा अपना जो अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवैल्पमैंट और स्मॉल और मीडियम टाउंज के लिए है चाहे इन्टीग्रेटिड हाउसिंग स्कीम्ज हैं ये सैन्ट्रल गवर्नमैंट की वे स्कीम्ज हैं जिनके लिए सैन्ट्रल गवर्नमैंट से फाइनैंशियल हैल्प लेने के लिए हमारी सरकार तेजी से आगे बड़ी है और इस बारे में इस बिल में प्रावधान है। इसके तहत हमें वार्ड कमेटी बनानी है। वार्ड कमेटी का वजूद सिर्फ ऐडवाइजरी बॉडी तक का है और that will be headed by the local Municipal Councilor. वैसे इसका ज्यादा फायदा नहीं है। इसका एक फायदा यह जरूर होगा कि कोई मोनोपोलिस्टिक व्यू नहीं ले पाएगा। जब कमेटी ऐडवाइज करेगी और उसकी कोई भी अच्छी ऐडवाइज होगी, जिसके बारे में वह कहेगी कि यह काम होना चाहिए या इस काम को प्रियोरिटी देनी चाहिए या कोई यह कहता है कि क्वालिटी औफ वर्क में कोई कमी है तो इसकी इकोरमेटिव जानकारी के आधार पर आवश्यक कदम उठायेंगे और जिन

काउंसलरों का कण्डक्ट ठीक नहीं है उनके खिलाफ हम एक्शन ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री एस०एस० सुरजेवाला (कैथल): अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहूंगा कि इस वक्त फरीदाबाद और गुड़गांव एम०सीज० को छोड़कर जो शहरों में म्यूनिसिपल काउंसिल्ज हें उनका जो स्टाफ है उसका पैटर्न बहुत पुराना है यह बात मंत्री जी की पर्सनल नॉलेज में भी है। उनके इतने पुराने नार्म्स हैं और उस स्टाफ की क्वालिफिकेशन, टैन्योर और उनका स्टेट्स और उनका एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा नहीं है। उनके इंजीनियरिंग स्टाफ की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। म्यूनिसिपल इंजीनियर के पद पर एक जे०ई० के स्टेटस का कर्मचारी होता है। उसके०पर कोई इंजीनियर नहीं होता। पूरे शहर में लम्बी सड़कें, गलियां, नालियां जगह–जगह बनानी पड़ती हैं। म्यूनिसिपल काउंसिल का सबसे बड़ा आफिसर सैक्रेटरी होता है। ई०ओ० तो एग्जिक्यूटिव आफिसर होता है, जो कहीं–कहीं होता है। सैक्रेटरी की क्वालिफिकेशन मैट्रिक होती है और जो पुराने हैं वे तो मिडिल पास ही होते हैं। इनकी प्रोपर क्वालिफिकेशन और प्रोपर ट्रेनिंग नहीं होती। जब तक इस पूरे स्टाफ का पैटर्न ठीक नहीं होगा तब तक म्यूनिसिपल कमेटी का जो काम होता है, उसमें नकली जापानी सामान लगेगा। जिस प्रकार सैकिण्ड वर्ल्ड वार के समय यह कहते थे कि यह जापानी काम है। जब डिमाण्ड करते हैं कि गलियां बनवा दो तो जबाव मिलता है कि बी०एण्ड आर० से

बनवा लो। इनके बजट के मुताबिक वहां पर ट्रेंड इंजीनियर जैसे एस०डी०ओ० लैवल का आफिसर लगाया जाये और उसकी हैल्प के लिए एक जे०ई० को भी लगा दिया जाए और इनके स्टाफ पैटर्न को दोबारा से रिव्यू करवाया जाए।

श्री अध्यक्षः गौतम साहब, आप पहले 15 मिनट बोलकर सदन से बाहर चले गये और जब वित्त मंत्री जी रिप्लाई दे रहे थे उस समय उनका रिप्लाई आपने सुना नहीं। अब कहो आप इस बिल के बारे में क्या कहना चाहते हैं?

श्री राम कुमार गौतम (नारनौंद): स्पीकर सर, मैंने एफ०एम० साहब का रिप्लाई सुन लिया था। स्पीकर साहब, मैं एक महत्वपूर्ण बात इस बिल के बारे में बोल रहा हूं। म्यूनिसिपल काउंसलर के प्रैजीडैंट का चुनाव, काउंसलर के माध्यम से होता है। वह प्रैजीडैंट कितना ही अच्छा इन्सान क्यों न हो उसको ईमानदार नहीं रहने देते। वह ऐसा हो जाता है कि जो भी ईंट और पत्थर आये वह उसके यहां से आये। इसलिए म्यूनिसिपल काउंसलर का डायरेक्ट इलैक्शन होना चाहिए। जिस प्रकार से सरपंच का इलैक्शन आजकल डायरेक्ट होता है उसी तरह इसका इलैक्शन भी डायरेक्ट होना चाहिए।

श्री अध्यक्षः गौतम साहब, आप इस बिल के बारे में कोई सुझाव दें। यह जो आप कह रहे हैं। इनका बिल से कोई रैलीवेन्स नहीं है। इसलिए आप बैठ जाईये।

श्री राधेशाम शर्मा अमर (नारनौल): अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि शहरों के विकास के लिए और मलिन बस्तियों का विकास करने के लिए उनमें सुधार करने के लिए, यह एक अच्छा बिल लेकर आये हैं जिससे हम गांव के विकास की कल्पना कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं बिल के बारे में बोल रहा हू। इस तरह से हमारे जो राष्ट्रीय शहर हैं गुड़गांव और फरीदाबाद, उनका विकास होगा। उनको देखकर जो सोहना और नारनौल जैसे छोटे शहर हैं उनके लिए भी यह योजना बनाई जाए तो उनका भी विकास होगा। जो गंदी बस्तियां हैं जिनमें पानी की या सीवरेज की कोई व्यवस्था नही है उनका विकास होगा। यह बहुत अच्छा बिल सरकार लाई है इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सरकार के जो उद्देश्य हैं वह उनको जल्दी से जल्दी पूरा करे।

Mr. Speaker: Question is -

That the Haryana Municipal Citizens Participation Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Sub Clause 2 of Clause 1

Mr. Speaker: Question is -

That Sub Clause 2 of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried

Clauses 2 to 19

Mr. Speaker: Question is -

That Clauses 2 to 19 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub Clause 1 of Clause 1

Mr. Speaker: Question is -

That Sub Clause 1 of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is -

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is -

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Urban Development Minister will move that the Bill be passed.

Urban Development Minister (Slid. A.C. Cbaudhary): Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved -

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is —

That the Bill be passed.

The motion was carried

दि हरियाणा अर्धन डिवैल्पमैंट अथोरिटी (अमैंडमैंट) बिल, 2008

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Haryana Urban Development Authority (Amendment) Bill, 2008 and will also move the motion for its consideration.

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to introduce the Haryana Urban Development Authority (Amendment) Bill, 2008.

Sir, I also beg to move -

That the Haryana Urban Development Authority (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल): अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल लाया गया है यह बहुत अच्छा बिल है। अर्बन डिवैल्पमैंट अथोरिटी की जहां–जहां लोकेशन हैं, इस बिल के आने से उनमें बहुत सुधार होगा इसलिए इसके लिए मैं सरकार को मुबारिकबाद देता हूं। इसके साथ–साथ मैं सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूं कि इस बिल में वायलेशंस के लिए पनिशमैंट का जो प्रोवीजन किया गया है यह बहुत अच्छा है। मेरा सुझाव है कि इनको इसमें एक प्लिंथ लैवल की समस्या को अवश्य जोड़ना चाहिए। वह समस्या यह है कि हुडा की कालोनियों में आप जाकर देखें। किसी ने धरती से 4 फुट उठाकर मकान बनाया हुआ हे किसी ने छ फुट०पर उठाकर मकान बनाया हुआ है। कोई सीढ़ियां सारी बाहर निकाल लेता है और अपने प्लाट में सारा मकान बना लेता है जिसकी वजह से नौबत यह आ जाती है कि आप न गाड़ी खड़ी कर सकते हैं और न आ सकते हैं और न जा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि इस चीज का भी कोई प्रोवीजन इस बिल में एड कर लिया जाए। जैसा माननीय ए०सी० चौधरी जी नया हरियाणा म्यूनिसिपल सिटीजंस पार्टिसिपेशन बिल लाए हैं उसी तरह इस हुडा ऐक्ट में भी रैजीडैंशियल वैल्फेयर एसोसिएशंज का ये रोल मुकर्रर कर दें क्योंकि वे वहां के लोकल बशिंदें होते हैं और प्लिंथ लैवल की तकलीफों को सबसे ज्यादा उन्हीं को झेलना पड़ता है। मेरा सुझाव है कि इस हुडा ऐक्ट में इन आर०डब्ल्यू०एज० की सिक्योरिटी सर्विसिज का कोई प्रोवीजन किया जाए ताकि उनको इस प्लिंथ लैवल की समस्या से छुटकारा मिल

सके और इससे वाटर हारवैस्टिंग में भी उनको मदद मिल सकती है।

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Haryana Urban Development Authority (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is -

That the Haryana Urban Development Authority (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is -

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is -

That Clause 3 stands part **of the B ill.**

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is -

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is -

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is -

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill be passed.

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved —

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is -

That the Bill be passed.

The motion was carried.

दि हरियाणा टैक्स ऑन एन्टरी आफ गुड्ज लघू लोकल एरियाज (अमैंडमैंट) मिल, 2008

Mr. Speaker: Now, the Excise and Taxation Minister will introduce the Haryana Tax on Entry of Goods into Local Areas (Amendment) Bill, 2008 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Shri Birender Singh): Sir, **I** beg to introduce the Haryana Tax on Entry of Goods into Local Areas (Amendment) Bill, 2008.

Sir, **I** also beg to move -

That the Haryana Tax on Entry of Goods into Local Areas (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved -

That the Haryana Tax on Entry of Goods into Local Areas (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is -

That the Haryana Tax on Entry of Goods into Local Areas (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Sub Clause 2 of Clause 1

Mr. Speaker: Question is —

That Sub Clause 2 of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 2 to 8

Mr. Speaker: Question is -

That Clauses 2 to 8 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub Clause 1 of Clause 1 Mr. Speaker: Question is -

That Sub Clause I of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is -

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Excise and Taxation Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Shri Birender Singh): Sir, I beg to move That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is That the Bill be passed.

The motion was carried

विशेषाधिकार समिति की विशेष रिपोर्ट पर चर्चा (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now discussion on Special Report of the Committee of Privileges will resume. Shri K.L. Sharma, was on his legs when Special Report of the Committee of Privileges was presented in the House. Shri K.L. Sharma may speak now.

श्री के०एल० शर्मा (शाहाबाद): धन्यवाद स्पीकर सर। सर, आपने मुझे कल भी बोलने के लिए समय दिया था लेकिन हाऊस का समय सामाप्त हो जाने के कारण कल मैं अपनी बात पूरी नहीं कह पाया था। स्पीकर सर, मैं यह कहना चाह रहा था कि मैं भी उस समय प्रिविलेज कमेटी का मैम्बर था जब यह बात 13.02.2007 को कमेटी की मीटिंग में उठी थी। स्पीकर सर, मुझे वह समय भी याद है जब यहां पर एक ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसी लैंग्वेज यूज की गई थी जो कि उससे एक्सपैक्ट नहीं किया जा सकता था। उसके अगेंस्ट प्रिविलेज मोशन लाया गया और प्रिविलेज कमेटी के पास भेजा गया। स्पीकर सर, प्रिविलेज कमेटी

द्वारा किसी केस पर अपनी रिपोर्ट पेश करने का एक निर्धारित समय होता है। इस केस में भी आपने यह समय निर्धारित कर दिया था कि अगले सैशन में कमेटी को अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। परन्तु बड़े दुःख की बात है कि बार–बार नोटिस देने के बावजूद भी जब श्री चौटाला की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं मिला तो प्रिविलेज कमेटी की ओर से इस केस में एक्सटैंशन होती रही। यह एक्सटैंशन भी सात महीने में सात बार हुई। प्रिविलेज कमेटी ने श्री चौटाला को बुलाने की पूरी कोशिश की लेकिन उनकी तरफ से कोई जबाव नहीं आया। फिर श्री चौटाला ने एक बात कही कि उन्हें वकील करने का मौका दिया जाये। जय श्री चौटाला ने कमेटी से वकील करने की इजाजत मांगी तो कमेटी ने तुरन्त इसका जबाव दिया कि आप अपना वकील कर सकते हैं और आप वकील को कमेटी के सामने लाकर अपनी बात कह सकते हैं। उसके बाद श्री अशोक अग्रवाल जी जो कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के सीनियर वकील हैं और शेर सिंह बडशामी जी कमेटी के सामने उपस्थित हुए और उन्होंने कमेटी की बात को सुना। कमेटी के चेयरपर्सन के विनम्र और सम्मानजनक व्यवहार से वे काफी प्रभावित हुए। कमेटी के चेयरपर्सन के ऐसे व्यवहार को देखकर उन्होंने यह बात कही कि यह जो आप बड़े प्यार से बात कर रहे हैं उन्हें इस प्रकार की आशा नहीं थी। उन्होंने कहा कि वे इस माहौल से बहुत इम्प्रैस हुए हैं उन्होंने कहा कि वे अपनी एक बात कहना चाहते हैं, कमेटी के चेयरपर्सन ने पूछा कि कहिए आपको क्या कहना है। इस पर वे कहने लगे कि आप इस केस

को ड्राप कर दें। उनकी इस बात पर चेयरपर्सन ने यह कहा कि ऐसा भी हो सकता था यह भी पॉसीबल था लेकिन आप 7 बार बुलाने के बाद आये हैं। हमने श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला, पार्लियामैंट्री अफेयर मिनिस्टर को भी बुलाया था जिन्होंने 12.09.2007 को अपना वक्तव्य दिया था। उस वक्त आकर अगर श्री चौटाला इतनी बात कह देते कि जोश में, गुस्से में, जाने–अनजाने में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई है अब मुझे उस बात पर दुःख है। अगर श्री चौटाला यह छोटी सी बात उस समय कह देते तो ऐसा पॉसीबल था कि कमेटी इस केस को ड्राप कर देती। परन्तु इतना समय बीत जाने के बाद अब ऐसा पॉसीबल नहीं है। श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अपना वक्तव्य दे दिया है और इस बात को दोहराया है कि श्री चौटाला के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। इसलिए अब इस स्टेज पर यह सम्भव नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि हमें रिकार्ड का अवलोकन करना है। इस पर कमेटी ने कहा कि इस केस से रिलेटिड जो भी, जैसा भी और जिस प्रकार का भी रिकार्ड आप जब भी देखना चाहें वह कमेटी को बता दें कमेटी उसके अनुसार संबंधित स्टाफ को ऑर्डर कर देगी कि वह रिकार्ड आपकी सुविधानुसार आपको पूरे का पूरा मुहैया करवाया जाये। उस समय वे बड़ी खुशी से गये। वे उस समय यह तय करके गये कि जो हमारी अगली डेट होगी उस डेट पर हम आकर रिकार्ड देखेंगे। लेकिन उसके बाद वे नहीं आये और तब तक नहीं आये जब तक कि उनको यह नोटिस नहीं दिया गया कि हम कंटैम्ट नोटिस उनको देते हैं। श्री चौटाला को यह

कहा गया कि आपको कंटैम्पट नोटिस दिया जायेगा और न आने पर भी आपके खिलाफ एक्शन लिया जायेगा। स्पीकर सर, उसके बाद 25 जुलाई, 2009 को श्री चौटाला आते हैं और आकर कहते हैं कि आपने जो कंटैंम्पट नोटिस हमें दिया है यह गलत किया है। वे कहते हैं कि मुझे इस बात का पता नहीं था। मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि मैं इस कमेटी की बात को न मानूं या कोई ऐसी बात करूं। उन्होंने आकर जब यह कहा कि मैं केवल यह समझकर नहीं आया कि मेरा जाना शायद इतना जरूरी नहीं है मेरे वकील ही सफीशिएंट हैं। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था। हालांकि यह बात झूठ थी क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति को जो इस हाउस के अन्दर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो उसे इस बात का ज्ञान न हो कि प्रिविलेज कमेटी तो बनाई ही इसलिए जाती है कि जब कोई केस उनके पास आता है तो दोषी मैम्बर को बुलाकर केस की पूरी तहकीकात करके रिपोर्ट निर्धारित समय में हाऊस में दे। प्रिविलेज कमेटी द्वारा जो मीटिंग्स की जाती हैं उन पर खर्च आता है, 8–9 महीने तक कमेटी चलती रहे, हरेक हफ्ते उसकी मीटिंग बुलाई जाये, हजारों–लाखों रुपये का खर्चा कर दिया जाये लेकिन एक मुख्यमंत्री के लैवल का इन्सान आकर यह कहे कि मुझे तो ज्ञान ही नहीं था कि मुझे वहां जाना है। अध्यक्ष महोदय, आपके खिलाफ यहां हाउस में गलत कहा गया उनसे वह स्पष्टीकरण लेना है। चेयरपर्सन ने भी श्री चौटाला जी से पूछा कि आप उस बात को मानते हैं या इनकार करते हैं। आप कहते हैं कि मुझे इस बात का ज्ञान ही नहीं है, बड़े दुःख की बात

है। अध्यक्ष महोदय, फिर भी मैं चेयरपर्सन को बधाई देना चाहता हूं उन्होंने कहा कि ठीक है अगर आपको इस बात का ज्ञान नहीं था, हम आपकी बात को मानते हैं और उन्होंने कंटैम्ट मोशन को ड्राप कर दिया। इस बात से यह बात पता चलती है कि भावना हाउस की, भावना माननीय मुख्यमंत्री जी की और भावना हमारे चेयरपर्सन की और किसी की भी ऐसी नहीं थी कि उनके साथ कुछ गलत किया जाये। हमारी तो सिर्फ एक ही बात थी कि हाउस के अन्दर अगर कोई कार्यवाही चलती है और बीच में उठकर कोई डिस्टर्ब करे, उसके बीच में खड़ा होकर कोई अनर्गल बात करे और जो बात उनकी समझ में भी नहीं आती, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, एक रटे–रटाये शब्द बोल दे यह ठीक नहीं था। उस दिन उन्होंने जो कहा अपैक्स चेयर के खिलाफ कहा। मुझे बड़े दुःख से यह बात कहनी पड़ रही है कि इस बार कुछ ऐसे व्यक्ति चुनकर आ गये हें जो या तो कुर्सी के काटे हुए हैं या फिर उनको इस अगस्त हाउस का, इस पवित्र सदन का और इस महान सदन की गरिमा का पता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, कैसी भाषा यूज करते हैं। उनको तो यह चाहिए था कि जब उनके लीडर के खिलाफ प्रिविलेज मोशन हो चुका है उसके बाद उनका किरदार देखते। आज भरी सभा के अन्दर कैसे बात कर रहे थे, कैसे इल्जाम लगा रहे थे?

स्पीकर सर, मुझे इस बात का बहुत दुःख है। आज एक–एक आदमी का किरदार बहुत ऑबौक्शनेबल है। स्पीकर सर,

ऐसे व्यक्ति को हाउस में बैठने का कोई हक नहीं है, उनकी सदस्यता खत्म कर देनी चाहिए। आज भी जब उनको बुलाया गया तो डेट फिक्स करने के बाद भी घर जा कर कहते हैं कि मुझे 5 जुलाई के बाद की कोई तारीख दे दें क्योंकि मैं विदेश घूमना चाहता हूं मैं विदेश में जाना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

आदरणीय मांगेराम जी, मेरी बात ध्यान से सुनिये, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात हाउस में कह रहा हूं। स्पीकर सर, आप मुझे टाईम ही ऐसे समय पर देते हैं जब लोगों को भूख लग चुकी होती है। कल भी मैं केवल दो मिनट ही बोल सका। बीच में किसी को डिस्टर्ब करके अपनी बात कहना यह मेरा किरदार नहीं है। मैं बता रहा हूं कि हाउस कैसे चलना चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को क्या सजा दी जानी चाहिए? मैं ये सब बातें कहना चाहता हूं लेकिन हमारे माई यह सब सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। फिर मैं यह समझता हूं कि आप भी उनकी बातें सुनने के लिए तैयार हैं।

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, शर्मा जी को भी अभी बहुत कुछ कहना है और बहुत सारे सदस्य और बोलना चाहते हैं। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि सारे सदन के सदस्यों की राय को देखते हुए जब दोबारा हाउस मीट करे तब इस प्रस्ताव को ले लिया जाये और तब फिर शर्मा जी बोल लेंगे।

अध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I am highly thankful to all of you for extending your cooperation to me for smooth conducting of the business of the House. I am also thankful of the press representatives, Government officers and officials of Haryana Vidhan Sabha Secretariat for their cooperation extended during the present Session.

श्री एस० एस० सुरजेवाला (कैथल): अध्यक्ष महोदय, अब सैशन ककलूड हो रहा है इसके लिए मैं तमाम सदस्यों की तरफ से आपको बधाई देना चाहता हूं कि जिस संयम से जिस discipline से, जिस निष्पक्षता से आपने हाऊस को चलाया और जिस प्रकार से आपने हर मैम्बर्ज को मौका दिया, चाहे वो किसी भी पार्टी का था उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूं और यह विश्वास दिलाता हूं कि आपकी अध्यक्षता में हाउस के तमाम मैम्बर्ज को आप में गहरा विश्वास है और आप इस बात के लिए मुबारकबाद के अधिकारी है।

Mr. Speaker: Now, the House stands adjourned sine die.

***15.04 Hrs.**

(The Sabha then *adjourned sine die.)